ISSN-0971-8397

विशेषांक

योजना

नवंबर 2018 | विकास को समर्पित मासिक | ₹ 30

स्वच्छता
विचार से वास्तविकता तक

खुले में शौच से मुक्त : जन आंदोलन
अरुण जेटली

स्वच्छ भारत की ओर बढ़ते कदम
नितिन गडकरी

स्वच्छता : बदलाव का शंखनाद
धर्मेन्द्र प्रधान

फोकस
स्वच्छ गांव स्वस्थ गांव
नरेन्द्र सिंह तोमर

विशेष आलेख
स्वच्छता क्रान्ति : बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन
परमेश्वरन अय्यर

स्वच्छता से शुचिता तक
सुदर्शन अय्यंगर

स्वराज की सीढ़ी : स्वच्छता
डी. जॉन चेल्लादुरई

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Scanned by CamScanner

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 29 सितंबर, 2018 को नई दिल्ली में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का शुभारंभ किया। पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में पेय जल और स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती, आवासीय और शहरी मामलों के राज्य मंत्री (प्रभारी) श्री हरदीप पुरी और पेय जल और स्वच्छता राज्य मंत्री श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनगी भी मौजूद थे।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती संबंधी कार्यक्रमों की शुरुआत के तहत पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छता पर चार दिनों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन-महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन किया। इसी दौरान स्वच्छ भारत अभियान की चौथी वर्षगांठ भी थी। इस सम्मेलन में 68 देशों के 160 से भी ज्यादा अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में कुल मिलाकर 350 प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें 53 स्वच्छता मंत्री थे।

इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 29 सितंबर, 2018 को किया। राष्ट्रपति ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर हम उन्हें खुले में शौच से मुक्त भारत से बेहतर तोहफा नहीं दे सकते।

सम्मेलन के शुरुआती दौर के बाद तकनीकी सत्रों की शृंखला के जरिये स्वच्छता संबंधी अहम मुद्दों/विषयों की पड़ताल की गई। इनमें रणनीतिक साझीदारी, शहरी स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्त समुदायों से जुड़ी जानकारी आदि का जायजा लिया गया।

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन के दूसरे दिन स्वच्छता मंत्रियों समेत 116 विदेशी प्रतिनिधियों ने महात्मा गांधी के जीवन और कार्य से संबंधित स्थलों का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने सबसे पहले पंसारी गांव की यात्रा की, जो स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का एक उदाहरण है। यहां के 5,100 निवासियों के लिए प्रत्येक घर में पानी की सुविधा के साथ शौचालय है। चूंकि इस गांव को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, इसलिए यहां के किसी भी बच्चे ने स्कूल की पढ़ाई नहीं छोड़ी है। प्रतिनिधिमंडल ने भारत में इस्तेमाल की जाने वाली दोहरे गड्ढे वाली शौचालय तकनीक में काफी दिलचस्पी दिखाई, जो सस्ता, पर्यावरण के अनुकूल और ग्रामीण भारत के बड़े हिस्सों में उपयोग के लिए उपयुक्त तकनीक है।

प्रतिनिधियों ने स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं को भी देखा और पाया कि यहां नवजात और मातृत्व संबंधी मृत्यु दर जीरो है। इन लोगों ने स्कूल, आंगनवाड़ी का भी दौरा किया और गांव के लोगों से उन शौचालयों के बारे में बात की, जो उन्होंने अपने घरों में बनाया है। प्रतिनिधियों ने पौधा रोपण भी किया और वे गांव में कंपोस्ट गड्ढे और निकास व्यवस्था को भी देखने गए। प्रतिनिधिमंडल ने महात्मा गांधी मंदिर कॉम्प्लेक्स में दांडी कुटीर का दौरा किया और अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ❑

वेबसाइट : mgisc.gov.in, ट्विटर : @SwachhBharat, फेसबुक : facebook.com/sbmgramin

सोशल मीडिया टैग : #SwachhBharat, #MGISC

Scanned by CamScanner

विशेषांक

योजना

वर्ष : 62
अंक : 11

नवंबर 2018
कार्तिक-मार्गशीर्ष, शक संवत् 1940

मूल्य : ₹ 30
पृष्ठ : 76

वेबसाइट www.yojana.gov.in

प्रधान संपादक : दीपिका कच्छल
वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
संपादक : डॉ. ममता रानी

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971

संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वी के मीणा
आवरण: गजानन पी धोपे

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि वे लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं है।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना मंगवाने की दरें
एक वर्ष: ₹ 230, दो वर्ष: ₹ 430, तीन वर्ष: ₹ 610

पत्रिका न मिलने की शिकायत के लिए pdjucir@gmail.com पर ईमेल करें, योजना की सदस्यता लेने या पुराने अंक मंगाने के लिए भी इसी ईमेल पर लिखें या संपर्क करें- दूरभाष: 011-24367453
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें-

संपादक (प्रचार एवं विज्ञापन)
प्रचार एवं विज्ञापन अनुभाग
प्रकाशन विभाग,
कमरा सं. 56, भूतल, सूचना भवन,
सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
नयी दिल्ली-110003

इस अंक में

खुले में शौच से मुक्त : जन आंदोलन
अरुण जेटली 7

स्वच्छ भारत की ओर बढ़ते कदम
नितिन गडकरी 10

फोकस

स्वच्छ गांव स्वस्थ गांव
नरेन्द्र सिंह तोमर 15

स्वच्छता : बदलाव का शंखनाद
धर्मेंद्र प्रधान 19

विशेष आलेख

स्वच्छता क्रान्ति : बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन
परमेश्वरन अय्यर 24

स्वच्छता ही सेवा 30

स्वास्थ्य सेवाओं में साफ-सफाई
प्रीति सूदन 32

महिलाओं व बच्चों के लिए साफ-सुथरा, आरोग्यमय वातावरण
राकेश श्रीवास्तव 39

स्वच्छता क्रांति : शहरी भारत की सफाई
दुर्गा शंकर मिश्र 44

स्वच्छता सबकी ज़िम्मेदारी
अक्षय राउत 52

स्वच्छता से शुचिता तक
सुदर्शन अय्यंगर 58

स्वराज की सीढ़ी : स्वच्छता
डी जॉन चेल्लादुरई 63

स्वच्छता के दूत
संतोष कुमार मल्ल 66

स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत
आलोक कुमार तिवारी 71

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	[illegible]
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	[illegible]
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	[illegible]
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	[illegible]
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	[illegible]
तिरुवनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	[illegible]
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाडिगुडा सिकंदराबाद	500080	[illegible]
बेंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	[illegible]
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	[illegible]
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज	226024	[illegible]
अहमदाबाद	द्वितीय तल, अम्बिका कॉम्प्लेक्स, पालडी, मदर टेरेसा रोड	380052	[illegible]

www.publicationsdivision.nic.in
@DPD_India

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

Scanned by CamScanner

आपकी राय

yojanahindi@gmail.com

स्वरोज़गार के लिए कौशल विकास कार्यक्रम

रोज़गार और स्वरोज़गार पर आधारित विकास को समर्पित पत्रिका योजना का सितंबर, 2018 का अंक पढ़ा। अंक से ढेरों सारगर्भित, ज्ञानवर्धक जानकारी मिली। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है तथा विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इसलिए यहां रोज़गार का प्रश्न उठना स्वाभाविक है। प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी सेवा में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें सीमित रिक्तियां होती हैं। भारत सरकार ने हमेशा रोज़गार का माहौल निर्मित करने के लिए अनेकों रोज़गार कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया है। वर्ष 2005 में मनरेगा को प्रारम्भ किया गया। अभी वर्ष 2014 में बनी नई सरकार द्वारा देश में स्वरोज़गार को बढ़ावा देने एवं कौशल युक्त वातावरण निर्मित करने के लिए 'कौशल विकास कार्यक्रम' को शुरू किया गया है। साथ ही स्वरोज़गार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए नाममात्र के ब्याज शुल्क पर 'मुद्रा योजना' के तहत लोगों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

सरकार अटल इनोवेशन मिशन, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आदि योजनाओं के माध्यम से युवाओं की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिससे युवाओं के लिए अपना कारोबार शुरू करना आसान हो रहा है। साथ ही सरकार ने देश में निवेश की गति को बढ़ाने के लिए निवेश प्रक्रिया को लचीला बनाया है, जिससे देश में निवेश की गति बढ़ी है। विश्व बैंक के 'ईज ऑफ डुइंग बिजनेस' रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा सुधार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को हुआ है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का 40 फीसदी योगदान है। इसमें लगी पूंजी की प्रति यूनिट के हिसाब से ज्यादा संख्या में लोग कार्यरत हैं। सरकार तकनीक को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे रोज़गार के नए अवसरों का सृजन हुआ है। पटना विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा 7 अक्तूबर से 13 अक्तूबर तक कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 'पुस्तक प्रकाशन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम' का संचालन किया गया, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को पुस्तक प्रकाशन से संबंधित जानकारी दी गई, जो रोज़गार के एक नए क्षेत्र का परिचय है। भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी कौशल विकास योजना पर बल दे रही है। अंत में कहा जा सकता है कि सरकार देश में बेरोज़गारी को दूर करने का हर संभव प्रयास कर रही है।

–अमित कुमार 'विश्वास'
रामपुर नौसहन, हाजीपुर
वैशाली, बिहार

महिलाओं के नेतृत्व में सशक्तीकरण

श्रीमती मेनका गांधी द्वारा उनके अपने आलेख जो स्वयं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संचालिका है, से महिलाओं के नेतृत्व में राष्ट्र का सशक्तीकरण के संबंध में अहम जानकारियां मिली हैं, ये वास्तविकता है कि आज समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा मिलना प्रारंभ हुआ है। आज न केवल महिलाएं सेवा क्षेत्र में बल्कि वे अंतरिक्ष जगत में भी अपना सम्मानजनक स्थान पाने में सफल हुई हैं। वर्षों से हमारे समाज में महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित रही। बावजूद कम अंतराल के उनकी प्रगति काफी प्रेरणादायक है।

महिलाओं के संरक्षण से जुड़ी तमाम योजनाएं बनाने एवं उनको अमल करने में सरकार लगभग सफल साबित हुई है। साथ ही आज भी कुछ वंचित समुदायों की महिलाओं हेतु सरकार एवं संबंधित मंत्रालय को काफी आगे तक जाना है एवं वास्तविक महिला सशक्तीकरण को परिभाषित करना है।

यह आलेख (महिलाओं के नेतृत्व में विकास से राष्ट्र का सशक्तीकरण) न मेरे बल्कि उन सभी पाठकों हेतु कारगर साबित हुआ है। इस हेतु मैं प्रकाशन विभाग को धन्यवाद एवं बधाई देता हूं कि वे समाज के आखिरी छोर तक राष्ट्र के सशक्तीकरण एवं देश को बल देने वाली योजनाओं का निचोड़ प्रदान करते हैं।

– प्रतीक चौहान
बिलाड़ा, ज़िला-जोधपुर

कृपया ध्यान दें

पत्रिका न मिलने की शिकायत के लिए pdjucir@gmail.com पर ईमेल करें, योजना मंगवाने या पुराने अंक प्राप्त करने तथा संबंधित जानकारी के लिए भी इसी ईमेल पर लिखें या संपर्क करें- दूरभाष: 011-24367453

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें–
संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग, प्रकाशन विभाग,
कमरा सं. 56, भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

Scanned by CamScanner

स्वच्छता - एक जीवन शैली

स्वच्छता ऐसी अवधारणा है, जो हर किसी के जीवन से जुड़ी हुई है। दांत साफ करने, नहाने से लेकर भोजन से पहले और उसके बाद हाथ धोने तक, स्वच्छता हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा है। हालांकि, स्वच्छ व्यक्ति वह नहीं है, जो गंदगी से भागता हो। इसकी बजाय स्वच्छ वक्त अपने आसपास भी सफाई के लिए समय निकालकर प्रयास करता है। ज्यादातर लोग अपने घरों को साफ रखते हैं, लेकिन अपने आसपास की जगहों पर गंदगी फैलाने में जरा भी नहीं हिचकते। अपने घर का कचरा सड़कों पर फेंकने से लेकर सड़कों पर थूकने तक, एक गंदे शख्स द्वारा अपने आसपास गंदगी फैलाने की कोई सीमा नहीं होती।

राष्ट्रपिता ने स्वच्छ हिंदुस्तान के अपने आह्वान में इसी से संबंधित अपील की थी। 'स्वच्छता देवत्व के बराबर है'- महात्मा गांधी के लिए यह न सिर्फ विचार बल्कि जीवन शैली थी। गांधी जी ने न सिर्फ स्वच्छता का पाठ पढ़ाया, बल्कि स्वयं भी इसका पालन किया। स्वच्छता को लेकर उनकी अवधारणा न सिर्फ तन बल्कि मन की सफाई से भी जुड़ी थी। वह ऐसा भारत देखना चाहते थे, जो न सिर्फ खुले में शौच से मुक्त हो, बल्कि उसमें तन और मन की स्वच्छता भी हो।

पिछले कुछ साल में भारत में आर्थिक विकास में लगातार बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है। हालांकि, सफाई और स्वास्थ्य की हालत अच्छी नहीं होने के कारण उसे बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। अपर्याप्त स्वच्छता देश के आर्थिक विकास के लिए गंभीर चुनौती पैदा करती है। स्वच्छता की हालत ठीक नहीं होने के परिणाम बुरी सेहत, मौत, शिक्षा में नुकसान और सकल उत्पादकता पर प्रतिकूल असर के रूप में देखने को मिलते हैं। विश्व बैंक के मुताबिक, सिर्फ इस वजह से भारत को सालाना 6.4 फीसदी सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) के नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। साथ ही, प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर राष्ट्रपिता को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में 2019 तक भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया।

पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय इस अभियान को लागू करने वाला प्रमुख मंत्रालय था। हालांकि, इस अभियान से जुड़े पहलू अब सभी के कामकाज का हिस्सा बन गए हैं। राजनीतिक इच्छाशक्ति, सार्वजनिक नीति और लोगों की भागीदारी ने स्वच्छ भारत अभियान को जन आंदोलन बना दिया है। स्वच्छता पखवाड़ा, रैलियां, ग्राम पंचायतों के जरिये जागरूकता अभियान, बड़े पैमाने पर शौचालयों का निर्माण, कचरा प्रबंधन, स्वच्छ सर्वेक्षण के जरिये निगरानी और कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग जैसे उपायों से लोगों के व्यवहार में धीरे-धीरे बदलाव हो रहा है। छात्र-छात्राओं, स्वच्छाग्रहियों, सरपंचों, जिलाधिकारियों, सिविल सोसायटी और मीडिया ने जनता तक 'स्वच्छता ही सेवा' का संदेश पहुंचाया है। अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर जैसे स्वच्छता के दूतों के जरिये भी शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।

इस अभियान से संबंधित स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास जैसे प्रमुख मंत्रालय अपने क्षेत्रों में खास मुद्दों से निपटने के लिए हरमुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कायाकल्प, विश्वास (स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता अभियान को जोड़ने के लिए गांव आधारित पहल), बाल स्वच्छता अभियान आदि ने इस अभियान को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा, शौचालयों के निर्माण, आंगनवाड़ी और शिशु देखभाल से जुड़े संस्थानों में स्वच्छ पेय जल की सुविधाओं की भूमिका भी अहम रही है।

किसी भी तरह का बदलाव लाने में युवा मुख्य दूत और अगुआ के तौर पर भूमिका अदा करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने शैक्षणिक संस्थानों के जरिये स्वच्छता की संस्कृति को विकसित करने के लिए युवाओं का उपयोग करने का फैसला किया है। इसी तरह, रेलवे, पेट्रोलियम, आवास और शहरी मामलों जैसे मंत्रालय मिशनरी अंदाज में रेलगाड़ियों, रेलवे स्टेशनों, पेट्रोल पंपों और स्मार्ट सिटी और गांवों के बड़े नेटवर्क के जरिये जलापूर्ति, कचरे के सुरक्षित प्रबंधन और आधारभूत संरचना के रखरखाव से संबंधित स्वच्छता की पूरी शृंखला तैयार करने को लेकर काम कर रहे हैं। इस तरह से यह अभियान पहले ही 'स्वच्छता' को जीवन शैली बनाने की राह पर पहुंच चुका है। ❑

Scanned by CamScanner

खुले में शौच से मुक्त : जन आंदोलन

अरुण जेटली

जब भारत के प्रधानमंत्री ने साल 2014 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, तो कुछ लोगों को लगा था कि यह योजना थोड़ी बहुत प्रगति के साथ महज तस्वीर खिंचाने का अवसर साबित होगी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह एक ऐसी योजना है, जिसे देश के लोगों ने सरकार से छीनकर उसे 'जनता के आंदोलन' में बदल दिया। जब इस अभियान का ऐलान किया गया था तो भारत में ग्रामीण इलाकों में सफाई का कवरेज 39 फीसदी था

पहले के दौर में सरकारी योजनाओं को आम तौर पर अविश्वास की नजर से देखा जाता रहा है। इसकी मुख्य वजह यह है कि इसके लाभ संबंधित लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं या ये प्रस्तावित मानकों को कभी हासिल नहीं कर पाते हैं। हालांकि, कई योजनाओं का मामला अलग होता है। तर्कपूर्ण नजरिये से स्वच्छ भारत अभियान सबसे सफल योजनाओं में से एक है।

स्वच्छ भारत अभियान

जब भारत के प्रधानमंत्री ने साल 2014 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, तो कुछ लोगों को लगा था कि यह योजना थोड़ी बहुत प्रगति के साथ महज तस्वीर खिंचाने का अवसर साबित होगी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह एक ऐसी योजना है, जिसे देश के लोगों ने सरकार से छीनकर उसे 'जनता के आंदोलन' में बदल दिया। जब इस अभियान का ऐलान किया गया था तो भारत में ग्रामीण इलाकों में सफाई का कवरेज 39 फीसदी था। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत को लेकर लक्ष्य तय करते हुए ऐलान किया था कि जब हम 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएंगे, तब तक भारत को 'खुले में शौच से मुक्त' कर दिया जाएगा। यह प्रतीक काफी सही था, क्योंकि गांधी जी स्वच्छता पर काफी जोर देते थे। इस योजना के चार साल पूरे होने के बाद स्वच्छता के कवरेज का मामला 39 फीसदी से बढ़कर शानदार 92 फीसदी पर पहुंच चुका है। यह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं था। इसके तहत लोगों का तौर-तरीका बदलने का मामला शामिल था। शुरू में ग्रामीण इलाकों में कई लोग इस बदलाव के लिए इच्छुक नहीं थे।

हालांकि, यह 'जनता का आंदोलन' आज 'महिलाओं के आंदोलन' में बदल गया है और ग्रामीण महिलाएं इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। हम सभी जानते हैं कि महिला की गरिमा और सम्मान के लिए निजी शौचालय की दरकार थी। हालांकि, भारत की महिलाएं अब इस अभियान की लाभार्थी की भूमिका से आगे बढ़कर इसको लेकर नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उदाहरण के तौर पर शौचालयों के निर्माण में हमेशा से पुरुषों का एकाधिकार जैसा रहा है। हालांकि, कई राज्यों में हजारों ग्रामीण महिलाओं को स्वयं-सहायता समूहों की मदद से राजमिस्त्री की तरह प्रशिक्षित किया गया है और वे अब राज्य को खुले में शौच से मुक्त करने में अहम ताकत बन रही हैं। शौचालयों के निर्माण के जरिये महिलाएं रोजी-रोटी कमा रही हैं और परिवार की आय में बढ़ोतरी कर रही हैं।

शौचालय के उपयोग में स्वच्छता भी एक एहतियाती स्वास्थ्य सेवा योजना है। वैश्विक विशेषज्ञों का मानना है कि 2019 तक जब देश खुले में शौच से मुक्त होगा, तब तक स्वच्छ भारत अभियान से 3 लाख लोगों की जिंदगी बचाई जा सकेगी। देश के कई हिस्सों में शौचालयों को 'इज्जत घर' नाम दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है,

प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत को लेकर लक्ष्य तय करते हुए ऐलान किया था कि जब हम 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएंगे, तब तक भारत को 'खुले में शौच से मुक्त' कर दिया जाएगा

लेखक भारत सरकार में वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री हैं। ईमेल: fmo@nic.in

जब शौचालय निर्माण के अभियान का विषय राष्ट्रीय एजेंडे में प्रमुखता से अपनी जगह बना चुका है। यह आम चर्चा का विषय बन गया है। सरकार ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जरूरी तमाम फंड उपलब्ध कराया है। यह योजना देश की ग्रामीण आबादी विशेष तौर पर महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने में काफी मददगार होगी।

ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास योजना, शौचालय और सस्ती दर पर अन्न के साथ रसोई गैस कनेक्शन जैसी सुविधाओं से देश के ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर में बड़े पैमाने पर सुधार होगा। इसके अलावा, आयुष्मान भारत जब पूरी तरह से लागू हो जाएगा, तो यह देश की ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर को बदल कर रख देगा। आयुष्मान भारत के तहत हर परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने की बात है।

मानदेय में बढ़ोत्तरी

केंद्र सरकार ने आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को भुगतान की जाने वाली रकम में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य आधार हैं। तकरीबन 12.9 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जबकि आंगनवाड़ी सहायकों की तादाद 11.6 लाख है। उनके मेहनताने में हुई बढ़ोतरी का फायदा इन 24.9 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायकों और उनके परिवार को होगा।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मेहनताना 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है। इसी तरह से मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मेहनताना 2,250 रुपये प्रति महीना से बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति किया गया है, जबकि आंगनवाड़ी सहायकों का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये प्रति महीना किया गया है। इन कार्यकर्ताओं को हर महीने 500 रुपये का इंसेंटिव भी मिलेगा। इसके अलावा, उनके प्रदर्शन की वास्तविक समय में निगरानी के आधार पर भी 250 रुपये प्रति महीने प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। इससे पहले सरकार ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बुरी तरह से कुपोषित बच्चों के लिए मदद की राशि में अहम बढ़ोतरी की थी।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक लंबे समय से मेहनताने में बढ़ोतरी कर इसे उचित स्तर पर लाने की मांग कर रही थीं। जाहिर तौर पर इससे राजस्व पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखते हुए पिछली सरकारें ने इन 25 लाख कार्यकर्ताओं को फायदा देने में हमेशा हिचकिचाट दिखाई। बजट के मोर्चे पर दबाव के बावजूद सरकार ने इन कर्मियों के मेहनताने में एक बार में तकरीबन 50 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इन कार्यकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने में यह बढ़ोतरी काफी सहायक होगी। ❑

सफलता की कहानी

पंजाब ने ओडीएफ मोबाइल ऐप पेश किया

पंजाब 'मेरा गांव, मेरा गौरव' अभियान के तहत ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) सस्टेनिबिलिटी (निरंतरता) ऐप पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह अपनी तरह का खास ऐप है और इसमें स्वच्छता से संबंधित सभी मानकों और संधारणीयता जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। ऐप में निम्न खूबियां हैं:

- इसमें खुले में शौच से जुड़ी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा है। इससे राज्य में खुले में शौच से मुक्ति की अवस्था को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- साथ ही, शिकायतकर्ता शिकायत से संबंधित प्रगति पर निगरानी रख सकते हैं।
- अगर कोई सदस्य इस कार्यक्रम से छूट गया है और उसके पास किसी वजह से शौचालय नहीं है, तो वह ऐप के जरिये शौचालय के लिए आवेदन पत्र हासिल कर सकता है।
- इसके अलावा, ऐप में सोशल मीडिया कोना और स्वच्छता गैलरी भी है, जहां इस सूचना, शिक्षा और संवाद से संबंधित सामग्री देखी जा सकती है।

'मेरा गांव, मेरा गौरव' अभियान में खुले में शौच से मुक्ति के लिए जागरूकता, सुबह-सुबह निगरानी, स्वच्छता अभियान, महिला मोहल्ला, ठोस कचरे को अलग करने जैसे मामलों में विभिन्न गांवों के बीच विभिन्न तरह की प्रतियोगिता की भी बात है। प्रखंड (ब्लॉक), जिला और राज्य स्तर पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले समूहों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। ❑

Scanned by CamScanner

स्वच्छ भारत की ओर बढ़ते कदम

नितिन गडकरी

2 अक्टूबर 2014 को 'स्वच्छ भारत' का शंखनाद करते समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस बात का भली-भांति अहसास था कि उन्होंने जो कार्य हाथ में लिया है वह बड़ा विकट है। देश में स्वच्छता का बुनियादी ढांचा बहुत ही अपर्याप्त था। करोड़ों लोग खुले में शौच करते थे। कूड़े-कचरे के कारगर तरीके के प्रबंधन से लोग अनजान थे और साफ-सफाई के काम को समाज में बहुत कम या नहीं के बराबर प्राथमिकता दी जाती थी। एक ओर अगर देश के सभी सवा सौ करोड़ लोगों के लिए स्वच्छता का बुनियादी ढांचा खड़ा करना एक चुनौती भरा काम था तो लोगों के मन में साफ-सफाई के प्रति जागरूकता जगाना तथा उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना तो और भी मुश्किल कार्य था। मगर भारत में स्वच्छता और आरोग्य के महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करना सरकार के लिए बड़ी प्रतिबद्धता है। यह हमारे प्रधानमंत्री की 'न्यू इंडिया' (नये भारत) की परिकल्पना का अभिन्न अंग है। इसलिए पिछले चार साल से अधिक समय से हमारी सरकार ने इस दिशा में लगातार प्रयास किये हैं। देश में स्वच्छता का आधारभूत ढांचा खड़ा किया गया है जिसके तहत शौचालय बनाए गये हैं और कूड़े-करकट के प्रबंधन की सुविधाएं तैयार की गयी हैं। इसके साथ ही लोगों को साफ-सफाई की आदतों को रोज़मर्रा की जिंदगी में अपनाने को प्रेरित करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाये गये हैं।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री के तौर पर मेरे लिए स्वच्छता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह रही है कि किस तरह गंगा की सफाई करके उसकी अविरलता और निर्मलता को बहाल किया जाए ताकि उसका प्रदूषण रहित प्रवाह लगातार जारी रहे। गंगा में प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो समय के साथ-साथ और भी जटिल होती चली गयी है। हालांकि पिछली सरकारों ने इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। गंगा में प्रदूषण के कई स्रोत और कारण हैं। इसके तटों पर बसे 97 शहर और कस्बे रोज़ाना लगभग 2 अरब 95 करोड़ लीटर सीवेज उत्पन्न करते हैं जिसे बिना साफ किये नदी में उड़ेल दिया जाता है। इन शहरों और कस्बों में सीवेज की सफाई के लिए बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है और कई मामलों में उचित रख-रखाव के अभाव में यह ढांचा ठप्प पड़ा हुआ है। जैसे-जैसे

लेखक भारत सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन नदी विकास, गंगा पुनरुद्धार मंत्री हैं। ईमेल: nitin.gadkari@nic.in

Scanned by CamScanner

भारत में स्वच्छता और आरोग्य के महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करना सरकार के लिए बड़ी प्रतिबद्धता है। यह हमारे प्रधानमंत्री की न्यू इंडिया (नये भारत) की परिकल्पना का अभिन्न अंग है। इसलिए पिछले चार साल से अधिक समय से हमारी सरकार ने इस दिशा में लगातार प्रयास किये हैं। देश में स्वच्छता का आधारभूत ढांचा खड़ा किया गया है जिसके तहत शौचालय बनाए गये हैं और कूड़े-करकट के प्रबंधन की सुविधाएं तैयार की गयी हैं। इसके साथ ही लोगों को साफ-सफाई की आदतों को रोज़मर्रा की जिंदगी में अपनाने को प्रेरित करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाये गये हैं

इन शहरों और कस्बों में आबादी बढ़ रही है, अवजल की मात्रा भी बढ़ती जा रही है जिससे प्रदूषण की समस्या के और जटिल होने की आशंका है। इसके अलावा नदी तट पर स्थित औद्योगिक इकाइयों से उत्पन्न होने वाला गंदा पानी, शहरों का ठोस कूड़ा-कचरा, कृषि अपशिष्ट, खुले में शौच से उत्पन्न अपशिष्ट, प्रदूषित सहायक नदियों और नालों का गंदा पानी भी गंगा में मिल जाता है जिससे नदी के पानी में प्रदूषण फैलाने वाले घटकों की मात्रा और भी बढ़ जाती है। गंगा की समग्र सफाई के लिए ऐसे बुनियादी ढांचे, प्रणालियों और तौर-तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है जो ऐसे प्रत्येक स्रोत से होने वाले प्रदूषण के नदी में पहुंचने की निरंतर और चिरस्थायी रोकथाम कर सके। इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकारों तथा विभिन्न निजी एजेंसियों की समन्वित और संगठित कार्रवाई के साथ-साथ नदी किनारे रहने वाले तमाम लोगों की भागीदारी भी आवश्यक होगी।

नमामि गंगे

गंगा को निर्मल बनाने के पिछली सरकारों के प्रयासों के कोई खास अच्छे परिणाम सामने नहीं आये जबकि मौजूदा सरकार द्वारा 2015 में शुरू किये गये 'नमामि गंगे' कार्यक्रम ने इस दिशा में अच्छी प्रगति की है। गंगा को स्वच्छ बनाकर उसका पुनरुद्धार करने के लिए 2014 में एक नया मंत्रालय गठित किया गया और 2015 में 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से 'नमामि गंगे' नाम का महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को लागू करने की ज़िम्मेदारी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सौंपी गयी जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 2016 में और अधिक अधिकार सौंपकर प्राधिकरण घोषित किया गया है। इसके अलावा 2017 में राज्य और जिला गंगा समितियों की भी स्थापना की गयी है।

इस कार्यक्रम के तहत 2015 से 2020 तक की अवधि के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो गंगा को स्वच्छ बनाने के इतिहास में अब तक किया गया सबसे बड़ा आवंटन है। कार्यक्रम के तहत अब तक 22,238 करोड़ रुपये लागत की 240 परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं में जल-मल के निस्तारण के लिए सीवेज लाइनें बिछाना, नदी-घाटों और श्मशान घाटों का निर्माण, रिवरफ्रंट का विकास, नदी की सतह की सफाई, संस्थागत विकास, जैव-विविधता संरक्षण, वृक्षारोपण और ग्रामीण स्वच्छता जैसे कार्य शामिल हैं। इनमें से 64 परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं और बाकी निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। गंगा की मुख्यधारा के किनारे बसे 97 ऐसे शहरों और कस्बों की पहचान की गयी है जिनसे 3603 एमएलडी सीवेज पैदा होने का अनुमान लगाया गया है (2035 के लिए अनुमानित) जबकि इन कस्बों की मौजूदा सीवेज शोधन क्षमता केवल 1651 एमएलडी की ही है। इसे कार्यक्रम के अंतर्गत बढ़ाया जाएगा। इन 97 शहरों कस्बों में हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर, कोलकाता, हावड़ा और बाली भी शामिल है जहां से नदी में सबसे अधिक प्रदूषण फैलता है। इनमें बड़े पैमाने पर जलमल शोधन संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं।

गंगा को निर्मल बनाने के पिछली सरकारों के प्रयासों के कोई खास अच्छे परिणाम सामने नहीं आये जबकि मौजूदा सरकार द्वारा 2015 में शुरू किये गये 'नमामि गंगे' कार्यक्रम ने इस दिशा में अच्छी प्रगति की है।

अभिनव प्रयोग

हमने इस क्षेत्र में हाइब्रिड एन्यूइटी मोड और वन-सिटी, वन-ऑपरेटर कॉन्सेप्ट जैसे कुछ अभिनव मॉडलों की भी शुरुआत की है जिनमें सभी नये और मौजूद जलमल शोधन संयंत्र एक ही ऑपरेटर के अधीन लाये जा सकेंगे जिससे उनका बेहतर रखरखाव और देखभाल संभव हो सकेगी। मथुरा में बनाया जा रहा जलमल शोधन संयंत्र अपने आप में अनोखा है। इसे बनाने का ठेका वन-सिटी, वन-ऑपरेटर अवधारणा के तहत हाइब्रिड एन्यूटी मोड में सौंपा गया है। इसमें एक ही निजी ऑपरेटर 30 एमएलडी क्षमता के एक संयंत्र का निर्माण करेगा और 38 एमएलडी क्षमता वाले तीन पुराने संयंत्रों की क्षमता में बढ़ोतरी करने के साथ-साथ उन सबके संचालन और रखरखाव के लिए भी उत्तरदायी होगा। मथुरा में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी इन जलमल शोधन

Scanned by CamScanner

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देश भर के राजमार्गों में अपने टोल प्लाजा पर सड़क के दोनों ओर पुरुषों और महिलाओं के लिए पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित अलग-अलग हरित शौचालयों का निर्माण कर रहा है। 2019 तक इसके सभी 372 टोल प्लाजा में इनका निर्माण पूरा हो जाएगा।

संयंत्रों से प्राप्त होने वाले परिशोधित अपशिष्ट जल को 8.70 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद कर इसका उपयोग करेगी। इससे रिफाइनरी द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले यमुना के 2 करोड़ लीटर पानी की किफायत होगी और उसका उपयोग दूसरे कार्यों में किया जा सकेगा।

इसके अलावा 16 परियोजनाएं गंगा की सहायक नदियों जैसे यमुना (हरियाणा में सोनीपत और पानीपत (दिल्ली, और उत्तर प्रदेश में मथुरा तथा वृंदावन), रामगंगा (उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद), सरयू (उत्तर प्रदेश में अयोध्या) और कोसी (बिहार में नवगछिया) में भी शुरू की गयी हैं। 3028 करोड़ रुपये लागत की इन परियोजनाओं की जल मल शोधन क्षमता 1353 एमएलडी होगी। गंगा की अन्य सहायक नदियों पर 68 शहरों और कस्बों में कुछ और परियोजनाएं भी शीघ्र ही बनाई जाएंगी।

केन्द्र सरकार द्वारा शतप्रतिशत वित्तपोषित इस कार्यक्रम के बारे में कहा जा सकता है कि यह विस्तृत और समन्वित कार्यक्रम है। यह राज्यों और केन्द्र की एजेंसियों के बीच सहयोग से कार्य करने पर आधारित है और इसके माध्यम से गंगा की सहायक नदियों को एक छत्र के नीचे ले आया गया है। इसका अपना अलग बजट है जो 5 साल के लिए है और कार्यक्रम का लगातार रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए 15 साल की संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) लागत को भी इसके बजट में जोड़ लिया गया है।

गंगा को स्वच्छ बनाने के कार्य में कई निजी कंपनियां भी भागीदारी निभा रही हैं और नदी की सफाई तथा घाटों और श्मशान घाटों के जीर्णोद्धार में हाथ बंटाने के साथ-साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों (कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) को पूरा करने के लिए नदी के किनारे वृक्षारोपण जैसी विभिन्न गतिविधियां संचालित कर रही हैं। गंगा प्रहरी के रूप में वे अन्य लोगों को नदी और उसके तटों को स्वच्छ रखने के बारे में प्रेरित करते हैं।

अब तक जो कार्य किया जा चुका है और किया जा रहा है उसे ध्यान में रखते हुए हम दावा कर सकते हैं कि मार्च 2019 तक गंगा 70-80 प्रतिशत तक और 2020 के अंत तक पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगी।

स्वच्छ सड़कें

स्वच्छता मेरे दो अन्य मंत्रालयों-सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्रालय की भी प्राथमिकता है। हम परिवहन के किफायती और पर्यावरण की दृष्टि से अधिक अनुकूल तरीके के रूप में जलमार्गों के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र सहित 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इसके अलावा मैं परिवहन क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में स्वच्छ ईंधन जैसे एथेनॉल, मीथेनॉल, बायो-डीजल, बायो-सीएनजी और बिजली के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा हूं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देश भर के राजमार्गों में अपने टोल प्लाजा पर सड़क के दोनों ओर पुरुषों और महिलाओं के लिए पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित अलग-अलग हरित शौचालयों का निर्माण कर रहा है। 2019 तक इसके सभी 372 टोल प्लाजा में इनका निर्माण पूरा हो जाएगा। टोल प्लाजा में कूड़ेदान भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं और स्वच्छता के संदेश के साथ-साथ कूड़ा फैलाने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए भी होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। राजमार्ग मंत्रालय इस बात का भी ध्यान रख रहा है कि सड़कों के निर्माण के दौरान कम से कम अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो और कोयला जलाने से बची फ्लाइ एश, प्लास्टिक, तेल की तलछट और शहरी कूड़े-कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में करने की दिशा में भी प्रयत्नशील है।

हरित बंदरगाह

जहाजरानी मंत्रालय ने भी बंदरगाहों के चिरस्थायी और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल दीर्घकालीन विकास के लिए पर्यावरण के अनुकूल 'हरित बंदरगाहों' के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया है। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी (यानी भारतीय हरित ऊर्जा परिसंघ) ने हाल में विशाखापट्टणम बंदरगाह न्यास भारत को सेवा क्षेत्र में 'नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल में उत्कृष्टता' वाली श्रेणी का विजेता घोषित किया। यह बंदरगाह वर्ष में 1.2 एम.यू. बिजली की खपत करता है जिसे शत-प्रतिशत पर्यावरण को प्रदूषित किये बिना बनायी गयी हरित ऊर्जा से ही पूरा किया जा रहा है।

यहां मैं बताना चाहूंगा कि हमारे उपर्युक्त प्रयासों के सार्थक परिणाम सामने आये हैं क्योंकि इस अभियान के हर चरण में इससे जुड़ी केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों का अच्छा सहयोग मिला है और उनके बीच अच्छा तालमेल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देश के आम लोगों का सहयोग रहा है जो स्वच्छ भारत की छवि से प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं और स्वच्छ भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए काम करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। 2014 में शुरू हुआ भारत को साफ-सुथरा बनाने का अभियान एक दुष्कर मिशन था। लेकिन चार साल बीत जाने के बाद एक देश के रूप में हम देशवासी इस बात का सामूहिक गौरव ले सकते हैं कि हमने इस दिशा में अच्छी सफलता प्राप्त की है और हमारी मुहिम के अच्छे नतीजे आने शुरू हो गये हैं।

Scanned by CamScanner

प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र का 'चैंपियस ऑफ द अर्थ' पुरस्कार

प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण संबंधी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में 3 अक्टूबर को प्रवासी भारतीय केंद्र में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उन्हें 'यूएनईपी चैंपियस ऑफ द अर्थ' पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार का ऐलान न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 73वीं बैठक के अवसर पर 26 सितंबर को किया गया। प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुटरेश के हाथों मिला।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (इंटरनेशनल सोलर एलायंस) में महत्वपूर्ण कार्य और 2022 तक भारत में प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने की दिशा में अभूतपूर्व संकल्प के लिए नेतृत्व श्रेणी में प्रधानमंत्री का चुनाव किया गया है। 'चैंपियस ऑफ द अर्थ' सालाना पुरस्कार सरकार, सिविल सोसायटी और निजी क्षेत्र से जुड़े वैसे लोगों को दिया जाता है, जिन्होंने अपने काम से पर्यावरण पर सकारात्मक असर डाला हो।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुटरेश ने 3 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 'चैंपियंस ऑफ द अर्थ' पुरस्कार दिया। इस अवसर पर विज्ञान व प्रौद्योगिकी और पर्यावरण मंत्री श्री हर्षवर्द्धन भी मौजूद थे।

प्रधानमंत्री का 'मिशन गंगे' प्रतिनिधिमंडल के साथ संवाद

पर्वतारोहण में अनुभव रखने वाले 40 उत्साही पर्वतारोहियों ने हाल में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। यह दल गंगा सफाई को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए साहसिक यात्रा शुरू कर रहा है। इस ग्रुप में 8 ऐसे पर्वतारोही हैं, जो सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं और इसकी अगुवाई मशहूर पर्वतारोही बछेंद्री पाल कर रही हैं। सुश्री बछेंद्री पाल विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला हैं।

मौजूदा साहसिक अभियान केंद्र सरकार के 'नमामि गंगे' अभियान से प्रेरित है और इसे 'मिशन गंगे' नाम दिया गया है। इसके तहत एक महीने तक राफ्टिंग (नौका चालन) के जरिये ये पर्वतारोही का समूह हरिद्वार से पटना तक जाएगा। जो बीच में बिजनौर, नरोरा, फरुखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और बक्सर में भी रुकेगा। यह समूह इन सभी 9 शहरों में गंगा को साफ रखने और सफाई संबंधी गतिविधियों को अंजाम देने के मामले में जागरूकता बढ़ाएगा।

इस समूह के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने इस साहसिक यात्रा को लेकर पहल के लिए समूह के सदस्यों की तारीफ की। उन्होंने स्वच्छ और साफ-सुथरी गंगा के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने समूह से जागरूकता अभियान के तहत उन शहरों में विशेष तौर पर स्कूल के बच्चों तक पहुंचने का अनुरोध किया, जहां से वे गुजरेंगे।

नई दिल्ली में 4 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 'मिशन गंगे' के सदस्यों के साथ। इस अवसर पर टीएसएएफ की निदेशक सुश्री बछेंद्री पाल भी मौजूद थीं।

Scanned by CamScanner

सरकार अपने विभिन्न प्रयासों के जरिए गांवों के विकास की क्रांति लाने का काम कर रही है और स्वच्छता इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अगर गांव स्वच्छ नहीं होंगे, तो गांवों का विकास अधूरा ही रहेगा। ऐसे अनेक अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे करोड़ों लोगों का जीवन बदला है और बदल रहा है

स्वच्छ गांव स्वस्थ गांव

नरेन्द्र सिंह तोमर

हमारा देश गांवों में बसता है और गांवों के विकास से ही देश का समग्र एवं समावेशी विकास हो सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के बहुमुखी विकास के लिए कृत-संकल्प है लेकिन विकास का यह सपना ग्रामीण भारत को स्वच्छ बनाए बिना, पूरा नहीं हो सकता। सरकार अपने विभिन्न प्रयासों के जरिए गांवों के विकास की क्रांति लाने का काम कर रही है और स्वच्छता इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अगर गांव स्वच्छ नहीं होंगे, तो गांवों का विकास अधूरा ही रहेगा। ऐसे अनेक अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे करोड़ों लोगों का जीवन बदला है और बदल रहा है। एक ऐसी पहल, जिसने करोड़ों लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में विशेष योगदान दिया है, वह है स्वच्छ भारत मिशन। प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को प्रारम्भ किए गए स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य मानवीय जीवन को अधिक स्वच्छ, स्वस्थ और उन्नत बनाना है। स्वच्छता न केवल जीवनदायिनी शक्ति है, बल्कि मानव विकास की आधारशिला भी है। कोई भी समुदाय और समाज तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक कि वह स्वच्छ न हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, मानव विकास इत्यादि से संबंधित लक्ष्य स्वच्छता के अभाव में प्राप्त नहीं किए जा सकते। राष्ट्र के आर्थिक विकास में भी स्वच्छता का विशेष योगदान है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल-किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अपने पहले संबोधन में स्वच्छ भारत के निर्माण का आह्वान किया था। उन्होंने स्वच्छता को राष्ट्रीय प्राथमिकता प्रदान की। नई दिल्ली में स्वच्छ भारत का शुभारंभ करते समय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि भारत के नागरिक के रूप में यह हमारा सामाजिक दायित्व है कि हम स्वच्छ भारत की गांधी जी की परिकल्पना को वर्ष 2019 में उनकी 150 वीं जयंती तक साकार करने में सहयोग दें। आज सम्पूर्ण राष्ट्र उस आह्वान से जुड़ा हुआ है। समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने आगे बढ़कर स्वच्छता के इस जन-आंदोलन को आगे बढ़ाया है और यह सिलसिला अनवरत जारी है। हर रोज देश के करोड़ों लोग भारत-भूमि को स्वच्छ बनाने की पहल में शामिल हो रहे हैं। आज देश के 22 राज्य, 468 जिले और 4 लाख 68 हजार से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्त-ओडीएफ हो गए हैं। 2 अक्टूबर, 2014 से अब तक 8 लाख 59 हजार से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छता कवरेज 38.70 प्रतिशत था जो वर्तमान में 93.90 प्रतिशत हो गया है। पूरे विश्व में स्वच्छता के क्षेत्र में इतनी बड़ी प्रगति कहीं देखी नहीं गई।

लेखक केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा खान मंत्री, भारत सरकार हैं। ईमेल: nstomar@gmail.nic.in

Scanned by CamScanner

भारत के इस महा-प्रयास ने विश्व के समक्ष अद्भुत मिसाल पेश की है कि राष्ट्र को सामाजिक सरोकार के मुद्दे पर किस तरह प्रेरित और आंदोलित किया जा सकता है। आज दुनिया के कई देश, भारत के इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हुए इसी तर्ज पर योजना बनाकर अपने देशों में स्वच्छता-स्थिति को सुधारने या बेहतर बनाने में लगे हुए हैं।

गांवों की बदलती तस्वीर

स्वच्छ भारत ने आज देश के गांवों की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। ऐसे कई अध्ययन हुए हैं जिनसे पता चला है कि खुले में शौच से मुक्त गांव के हर घर में प्रत्येक वर्ष करीब 50,000 रुपये की बचत हो रही है, क्योंकि पूरा परिवार कई तरह की बीमारियों पर होने वाले खर्च से बच रहा है। ग्रामीण परिवार इस बचत का उपयोग अपनी सुविधाएं बढ़ाने, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने और जीवन-स्तर को उन्नत बनाने में कर रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में कमी आई है और वे अधिक दिनों तक श्रम कर पा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन से हम ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल बड़ी संख्या में बच्चों को घातक बीमारियों से बचा पाने में सफल हुए हैं और इस दिशा में स्थिति लगातार सुधर रही है। स्वच्छ भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे अनूठे प्रयासों को भी जन्म दिया है, जो पहले कभी देखे नहीं गए। स्व-सहायता समूह (एसएचजी) से जुड़ी महिलाओं ने स्वच्छता आंदोलन में सराहनीय योगदान किया है। उन्होंने अपनी बचत को स्वच्छता संबंधी कार्यों में निवेश कर पर्यावरण और परिवेश को सुंदर और स्वच्छ बनाने में अहम भूमिका निभाई है। स्व-सहायता समूहों की बहनों ने ऐसे अनेक परिवारों को आर्थिक मदद दी है, जो आर्थिक संकट में फंसे हुए थे। स्व-सहायता समूहों ने आपसी सहयोग के अनेक प्रयासों से सामाजिक सद्भाव को मजबूत बनाने में भी मदद दी है। हमारे पंचायत प्रतिनिधियों ने भी स्वच्छ भारत मिशन में असाधारण दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने अपनी पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त बनाने हेतु प्रभावी योजनाएं बनाईं, उन्हें उत्साह और कुशलता के साथ कार्यान्वित किया और रख-रखाव में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पंचायतों ने आमजन को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए निष्ठापूर्ण प्रयास किए हैं और सबके सहयोग से ग्राम पंचायतों को न केवल खुले में शौच से मुक्त कराया है, बल्कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित गतिविधियां चलाकर पर्यावरण संबंधी स्वच्छता को भी बढ़ावा दिया है।

जनांदोलन बनता स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत मिशन अब एक जन-आंदोलन का रूप ले चुका है और इसे आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम-मनरेगा के माध्यम से बहुत से उपाय किए हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति ग्राम-पंचायतों के बीच जागरूकता का प्रसार, ग्रामीणों के आजीविका-सृजन से जुड़े कार्य और गतिविधियां शुरू करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जाना शामिल है। मंत्रालय व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों एवं सोख्ता गड्ढों के निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (वर्मी/एनएडीईपी कम्पोस्ट गड्ढों), ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन से जुड़े कार्यों (ड्रेनेज चैनल, तरल जैव खाद, पुनर्भरण गड्ढों, स्कूलों एवं आंगनवाड़ियों में शौचालय, सोकेज चैनल, गांव की नालियां, इस्तेमाल किए जा चुके ग्रे-वॉटर (गंदे जल) को उपयोगी बनाने के लिए जल-स्थिरीकरण तालाब का निर्माण) तथा जल संरक्षण कार्यों पर जोर दे रहा है। इस बात पर बल दिया जा रहा है, कि गांव की हर पंचायत, स्वच्छ पंचायत बने।

गंदे जल का प्रबंधन

अपशिष्ट यानी इस्तेमाल किए गए गंदे जल (वेस्ट वॉटर) का प्रबंधन मौजूदा समय में पूरे विश्व के लिए बड़ी चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, अपशिष्ट प्रबंधन की आयोजना और अवसंरचना की कमी के कारण जीवन की परिस्थितियां भी अस्वच्छ हो जाती हैं। इससे बीमारियां फैलती हैं, संक्रमण फैलता है। इस संबंध में हमें यह बताने में खुशी हो रही है कि तेलंगाना राज्य में अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर सोखते गड्ढों का निर्माण मनरेगा के माध्यम से किया जा रहा है। इसी तरह, महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में मनरेगा की धनराशि से सोखते गड्ढों का निर्माण कर गांवों को मच्छरों से मुक्त बनाने में मदद मिली है। इस योजना के कार्यान्वयन में लगभग 30 गांव शामिल हैं। उन्होंने मिल-जुलकर सुनिश्चित किया कि सोखते गड्ढों के निर्माण से मच्छरों पर नियंत्रण किया जाएगा, जिससे गांव के लोग चैन की नींद सो सकेंगे और मच्छरों से होने वाली बीमारियों से उनका बचाव होगा। मिज़ोरम के आइज़ोल जिले में त्लैनगुआम आर.जी. ब्लॉक के लिंगपुई वाटर टैंक का निर्माण, मनरेगा के अंतर्गत अभिनव प्रयोग के रूप में शुरू किया गया। यह वाटर टैंक, आइज़ोल जिले

Scanned by CamScanner

में हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़क के किनारे हवाई जहाज के आकार में बनाया गया है। टैंक परिसर में सार्वजनिक नल भी है, जिनसे सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति होती है और वहां भुगतान पर इस्तेमाल किए जाने वाले शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। इन सुविधाओं और व्यवस्थाओं के साथ यह टैंक बहुउद्देश्यीय परिसम्पति बन गया है। इससे ग्राम पंचायत की आमदनी भी हो रही है। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत अपशिष्ट जल के स्थिरीकरण के लिए पांच पॉण्ड वाली प्रणाली विकसित की है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट जल का समुचित निपटान करना और बेहतर परिस्थितियां सुनिश्चित कर, गांवों का वातावरण स्वच्छ बनाना है। केरल के त्रिशूर जिले के मतिलाकम ब्लॉक की एरियाड ग्राम पंचायत में निर्माण सामग्री के उत्पादन की परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना में तैयार किए गए सीमेंट कंक्रीट ब्लॉकों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों जैसे मनरेगा कार्यों के लिए ही किया गया। महात्मा गांधी मनरेगा योजना के अंतर्गत वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों का निर्माण भी किया जा रहा है।

ग्रामीण स्वच्छता पर बल

ग्रामीण स्वच्छता से जुड़े कार्यों पर मनरेगा की बड़ी मात्रा में धनराशि खर्च की जा रही है और इसका अपेक्षित परिणाम भी मिला है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान इस योजना के माध्यम से व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण पर 92435 लाख रुपये खर्च किए गए थे। पिछले वित्त वर्ष के दौरान इस पर 139835 लाख रुपये से अधिक राशि खर्च की गई। सोख्ता गड्ढों के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2014-15 के 2938 लाख रुपये के मुकाबले, पिछले वित्त वर्ष के दौरान 15695 लाख रुपये से अधिक राशि व्यय की गई। वर्मी/एनएडीईपी कम्पोस्ट गड्ढे के जरिए ठोस कचरा प्रबंधन पर वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 1676 लाख रुपये खर्च हुए जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान इन कार्यों पर 54853 लाख रुपये से अधिक खर्च किया गया। ड्रेनेज चैनल, तरल जैव खाद, रिचार्ज पिट, स्कूल और आंगनवाड़ी शौचालय, सोकेज चैनल, गांव की नालियां और स्थिरीकरण पॉण्ड जैसे ठोस तरल कचरा प्रबंधन कार्यों पर वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 49512 लाख रुपये खर्च किए गए थे। इसके मुकाबले वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 85221 लाख रुपये से अधिक राशि इन कार्यों पर खर्च की गई। जल संरक्षण कार्यों पर वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान लगभग 471231 लाख रुपये खर्च किए गए थे। इसकी तुलना में पिछले वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 692216 लाख रुपये खर्च किए गए। वित्त वर्ष 2014-15 में स्वच्छता संबंधी सभी कार्यों पर लगभग 617792 लाख, वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान लगभग 698357 लाख रुपये वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 1065228 लाख रुपये और वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग 987822 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान भी ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता संबंधी सभी गतिविधियों पर अब तक लगभग 593070 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों की समग्र स्वच्छता पर मनरेगा की बहुत बड़ी राशि खर्च की गई और खर्च की जा रही है।

भौतिक प्रगति

मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में हुई भौतिक प्रगति पर नजर डालने से पता चलता है कि मनरेगा की राशि से वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान लगभग 13.88 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया।

वित्त वर्ष 2015-16 में लगभग 7 लाख, वित्त वर्ष 2016-17 में करीब साढ़े सात लाख और वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान करीब 9 लाख शौचालयों का निर्माण मनरेगा की निधियों से किया गया। सोख्ते गड्ढों के निर्माण में वित्त वर्ष 2016-17 से बहुत तेजी आई है। जहां वित्त वर्ष 2015-16 में करीब 37,000 सोख्ते गड्ढों का निर्माण हुआ था, वहीं वित्त वर्ष 2016-17 में यह संख्या बढ़कर 4,21,553 हो गई। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान भी 2,19,000 से अधिक सोख्ते गड्ढों का निर्माण किया गया। वर्मी/एन.ए.डी.ई.पी. कम्पोस्ट गड्ढों के जरिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस बारे में जहां वर्ष 2014-15 के दौरान लगभग 5,000 काम हुए थे, वहीं वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान ऐसे कार्यों की संख्या बढ़कर 1,82,000 और वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग 2,54,000 हो गई। ड्रेनेज चैनल, तरल जैविक खाद, रिचार्ज गड्ढों, स्कूल एवं आंगनवाड़ी शौचालयों, सोकेज चैनल, ग्रामीण नालियों और स्थिरीकरण तालाब (स्टेबलाइजेशन पॉंड) के जरिए ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों में भी अच्छी प्रगति हुई। वित्त वर्ष 2015-16 में ऐसे 82,564 कार्य किए गए थे, जिसकी संख्या वित्त वर्ष 2016-17 में बढ़कर 3,82,725 हो गई। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान भी 1,83,000 से अधिक कार्य पूरे किए गए। मनरेगा की निधियों का उपयोग जल-संरक्षण कार्यों में कुशलतापूर्वक किया जा रहा है और इसमें भी बहुत अच्छी प्रगति हुई है। जल-संरक्षण संबंधी अवसंरचना के विकास कार्यों पर वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान लगभग 2,76,000, वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 2,77,000, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान करीब 6,00000 और वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान करीब 3,84,000 कार्य किए गए।

Scanned by CamScanner

समग्र स्वच्छता के प्रयास

ये सभी तथ्य और आंकड़े इस बात को प्रमाणित करते हैं कि केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ गांवों को हर दृष्टि से स्वच्छ बनाने पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय देश की जीवन-रेखा माने जाने वाले गांवों का सही मायने में विकास करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु विविध प्रयास कर रहा है। यह एक ऐसा पहलू है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही देश की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा ने इसका महत्व समझा है और उसकी सफलता की हजारों कहानियों ने साबित कर दिया है कि हमारे देश के नागरिक गांवों में स्वच्छता का माहौल बनाने की दिशा में जागरूक हुए हैं और वे ग्रामीण भारत को स्वच्छ बनाने और स्वच्छता लगातार बनाए रखने का संकल्प ले रहे हैं।

अब ग्राम पंचायतें केवल व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के जरिए ही स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही हैं, बल्कि वर्मी कम्पोस्ट गड्ढों के जरिए कचरा साफ करने की दिशा में भी कदम उठा रही हैं। पंचायतें मनरेगा के कार्यान्वयन में मल-जल निकासी व्यवस्था, तरल जैव खाद, रिचार्ज किट, स्कूल और आंगनवाड़ी शौचालयों, सोकेज चैनलों, ग्रामीण नाले-नालियों और जल स्थिरीकरण तालाबों के माध्यम से स्वच्छ पर्यावरण के रख-रखाव में भी मुख्य भूमिका निभा रही हैं। हालांकि देश में गांवों के स्वरूप की विविधता को देखते हुए यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भारत की सभी 2,38,617 ग्राम पंचायतों के लिए स्वच्छता का कोई एक मॉडल लागू नहीं किया जा सकता। हां, हमें ऐसे उपायों को लगातार विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना है, जो किफायती होने के साथ अपनाने में ज्यादा आसान हों और तकनीकी दृष्टि से खामियां कम-से-कम हों। ग्रामीण भारत को स्वच्छ बनाने के लिए मनरेगा की क्रांतिकारी पहल और मौजूदा सरकार द्वारा इसके प्रभावी कार्यान्वयन के रचनात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं।

नए भारत के निर्माण की ओर

वास्तव में, ग्रामीण विकास मंत्रालय की समग्र स्वच्छता संबंधी इस अभिनव पहल से पारिस्थितिकीय संतुलन में सुधार आ रहा है और देश की ग्रामीण आबादी को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण की ओर ले जाने में उल्लेखनीय मदद मिल रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने 15 सितंबर, 2018 से 2 अक्टूबर, 2018 तक 'स्वच्छता ही सेवा' कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम में लोगों का उत्साह काबिले तारीफ है। इस बारे में मैं आग्रह और अनुरोध करना चाहूंगा अपने देश के सभी प्रिय ग्रामवासियों से, कि वे इसे केवल 2 अक्टूबर तक ही सीमित न रखकर, अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने और आदत में ढालने का प्रयास करें और नियमित आधार पर श्रमदान कर, अपने गांवों, गलियों, पर्यावरण और परिवेश को स्वच्छ बनाकर ग्रामीण-जीवन को ज्यादा-से-ज्यादा खुशहाल और समृद्ध बनाने में योगदान दें। सचमुच, एक नए भारत के निर्माण में यह उनका अद्वितीय योगदान होगा। ❑

Scanned by CamScanner

स्वच्छता : बदलाव का शंखनाद

धर्मेंद्र प्रधान

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ स्वस्थ तथा स्वच्छ भारत अभियान का समर्थन किया है और इसे सफल बनाने के लिए अपने सभी संसाधनों को लगा दिया है। महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों और संकल्पबद्ध प्रयासों ने स्वच्छ, हरे-भरे तथा स्वस्थ भारत की नींव रखी है

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी तो शायद यह इतिहास के सबसे बड़े सामाजिक अभियानों में से एक अभियान का शुभारंभ था। इससे पहले कभी भी किसी भी उद्देश्य के लिए इतने कम समय में एक अरब से अधिक लोगों ने ऐसी अभिलाषा नहीं की और न ही इसके लिए एक साथ आगे आए। चार साल पहले शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान एक परिकल्पना से आगे बढ़ता हुआ बदलाव का प्रभावशाली माध्यम बन गया। हालांकि, हम अभी पूरी तरह स्वच्छता नहीं ला पाए हैं लेकिन, देशभर में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। भारत में स्वच्छता का स्तर 2014 के 38 प्रतिशत से बढ़कर 2018 में 90 प्रतिशत हो गया है। इस दौरान नौ करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। साढ़े चार लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। आज लाखों लोगों को शौचालय सुविधाएं, साफ पेयजल और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध है जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अक्टूबर 2014 और अक्टूबर 2019 के बीच तीन लाख से अधिक लोगों की मौत को टाला जा सकेगा। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वच्छता भारत में आदतों में बदलाव के लिए एक व्यक्तिगत प्रयास से आगे बढ़कर उत्प्रेरक बन गई है।

मैं, व्यक्तिगत तौर पर और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री के रूप में, दिल से स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ स्वस्थ तथा स्वच्छ भारत अभियान का समर्थन किया है और इसे सफल बनाने के लिए अपने सभी संसाधनों को लगा दिया है। महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों और संकल्पबद्ध प्रयासों ने स्वच्छ, हरे-भरे तथा स्वस्थ भारत की नींव रखी है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए स्वच्छता कार्य योजना के तहत एक अंतर मंत्रालय कार्य योजना के वास्ते पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वर्ष 2017-2018 के लिए 335.68 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। इस कार्य के लिए इतनी बड़ी बजट राशि आवंटित करने वाला यह भारत सरकार का चौथा मंत्रालय है। मंत्रालय ने 402 करोड़ रुपये खर्च कर स्वच्छता का स्तर 120 प्रतिशत पर लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

भारत के सबसे बड़े निगमों में शामिल तेल एवं गैस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और उनके संयुक्त उद्यमों ने न केवल अपने प्रमुख कारोबारी प्रस्तावों के आसपास बहुआयामी परियोजनाओं पर काम किया है तथा स्वच्छता में सहायक बुनियादी ढांचे के निर्माण की कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निभाई है बल्कि स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ इस सामाजिक आंदोलन में हिस्सा लिया है। मुझे आपको यह बताने में खुशी हो रही है कि अक्टूबर 2014 के बाद, इस दिशा में किए गए अपने प्रयासों में हमने किस प्रकार प्रगति की है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के रूप में मैं दिल से स्वच्छ भारत अभियान के

लेखक भारत सरकार में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री हैं। ईमेल: min.png@nic.in

Scanned by CamScanner

उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। स्वस्थ तथा स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की टीम के पुरुषों और महिलाओं ने अपने पक्के इरादे, नवाचार और साहस का परिचय दिया है।

पेट्रोल पंप पर सुविधाएं

राष्ट्रीयकृत तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पम्प देश के सबसे व्यापक खुदरा नेटवर्क में शामिल हैं। हर रोज अनगिनत लोग इन पेट्रोल पम्पों पर अपने वाहनों में पेट्रोल भरवाते हैं इसलिए यहां साफ-सफाई की सुविधाओं से हजारों ग्राहकों को फायदा हो सकता है। इसी के मद्देनजर स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पम्पों पर साफ-सुथरे शौचालय, स्वच्छ पेयजल और कचरा निपटान सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक योजना शुरू की गई है। यह लेख लिखे जाने तक 56,601 पेट्रोल पम्पों में से 55,784 से अधिक में शौच की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी थी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने महिला सुरक्षा और गरिमा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत सितंबर 2018 तक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर, जितने भी पेट्रोल पम्पों पर संभव था वहां लगभग 90 प्रतिशत में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण किया है। देशभर में इन शौचालयों में स्वच्छता की निगरानी, रिपोर्ट और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए Swachhta@petrolpump एप उपलब्ध कराया गया है। समूचे देश में तेल विपणन कंपनियों के प्रत्येक पेट्रोल पम्प पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग, उपयोगकर्ताओं के अनुकूल और उचित रखरखाव वाले शौचालयों के निर्माण का काम जारी है और हम इसे पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

भारतीय महिलाएं हजारों साल से चूल्हे पर खाना पकाती रही हैं और लकड़ियों, कोयले तथा गोबर के उपलों से चूल्हा जलाकर धुएं को झेलती रही हैं। धुएं से घर में प्रदूषण के कारण उनके और परिवार के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और उन्हें श्वास संबंधी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जलाने की लकड़ी के लिए वनों की कटाई के भी विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। चूल्हे पर खाना पकाने में अधिक समय लगने के कारण वे आजीविका कमाने के अवसरों से भी वंचित रह जाती हैं, जिससे सामाजिक असमानता पैदा होती है। प्रधानमंत्री ने देश की ऐसी लाखों वंचित महिलाओं तथा परिवारों की परेशानियों को महसूस किया और इन्हें दूर करने के उपाय किए। उन्होंने इन्हें एलपीजी जैसा स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराने के लिए ब्लू फ्लेम क्रांति के तहत एक मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इसके तहत देशभर में वंचित और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को 5.51 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इन परिवारों के जीवन में आए बदलाव से प्रोत्साहित होकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2020 तक आठ करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। इस उपलब्धि के महत्व को जानने के लिए इस तथ्य पर गौर किया जाना चाहिए कि स्वतंत्रता के बाद 2014 तक जहां एलपीजी की सुविधा केवल लगभग 54 प्रतिशत आबादी को उपलब्ध थी वहीं 2018 में यह लेख लिखे जाने तक यह 88 प्रतिशत आबादी को उपलब्ध करा दी गई थी।

ईंधन दक्षता में सुधार

भारत में जैसे-जैसे आर्थिक विकास तेज हो रहा है, वाहनों की संख्या और पेट्रोलियम ईंधन का इस्तेमाल बढ़ने से इसका सीधा असर पर्यावरण प्रदूषण पर पड़ रहा है। पेरिस में सीओपी 21 में जलवायु परिवर्तन के लिए

Scanned by CamScanner

भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और ईंधन दक्षता में सुधार के लिए कई नीतिगत उपाय और हस्तक्षेप किए हैं। भारत ने भारत स्टेज-बीएस के रूप में परिभाषित ईंधन गुणवत्ता और वाहन उत्सर्जन मानकों के लिए नियामक उपायों का पालन किया है। उसने देशभर के पेट्रोल पम्पों पर अप्रैल 2017 में बीएस-4 मानकों को सफलतापूर्वक लागू किया। इतना ही नहीं सरकार ने ईंधन मानकों को सीधे बीएस-4 से बीएस-6 करने का साहसपूर्ण फैसला भी लिया है। बीएस-6 मानक ईंधन से बीएस-4 की तुलना में बहुत कम प्रदूषण होता है और यह यूरो-6 जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ईंधन का मुकाबला कर सकता है। अप्रैल 2018 से दिल्ली के पेट्रोल पम्पों पर बीएस-6 की बिक्री की जा रही है और अप्रैल 2020 तक इसे समूचे देश में शुरू कर दिया जाएगा।

जैव ईंधन को बढ़ावा

तीव्र आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन के बीच संतुलन की भारत की चुनौती के मद्देनज़र जैव ईंधन बहुत महत्वपूर्ण है। हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से हालांकि बहुत आगे बढ़ चुके हैं लेकिन अब भी कृषि उन लाखों लोगों के जीवन से जुड़ी है जो आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर है। अधिकतर पाठक देश के उत्तरी भागों में शीतकाल में किसानों के पराली (फसल के अवशेष) जलाने के कारण होने वाले घने कोहरे से परिचित होंगे। भारत सरकार ने पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटने और किसानों को आय का साधन मुहैया कराने के लिए 2018 में जैव ईंधन पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी है। दूसरी पीढ़ी की 12 रिफाइनरियां स्थापित करने की योजना है जिनमें पराली से जैव एथनोल बनाया जाएगा। हमने अब तक पेट्रोल में चार प्रतिशत एथनोल मिलाने की क्षमता हासिल कर ली है जिससे विषैली गैसों के उत्सर्जन में 7.8 मिलियन मीट्रिक टन की कमी आई है। ईंधन आयात पर 1520 मिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। हमारा लक्ष्य पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथलोन मिश्रण का है। इस्तेमाल किए जा चुके कुकिंग ऑयल को बायोडीज़ल के लिए संभाव्य फीडस्टॉक के रूप में प्रयोग करने की भी काफी संभावनाएं हैं। इससे न केवल ईंधन उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि कुकिंग ऑयल को खाद्य उद्योग में इस्तेमाल करने पर भी रोक लगेगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में अपनी क्षमताओं के व्यापक विस्तार का काम 2014 से तेजी से आगे बढ़ाया है। तेल एवं गैस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा स्थापित पवन ऊर्जा परियोजनाओं से होने वाला उत्पादन 2014-18 में 369.80 मेगावाट हो गया है जबकि 2010-14 के बीच यह 299.60 मेगावाट था। तेल एवं गैस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं से होने वाला उत्पादन 2014-18 में 70.87 मेगावाट हो गया है जबकि 2010-14 के बीच यह 15.63 मेगावाट था।

तेल एवं गैस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, भारत के सबसे अधिक लाभ कमाने वाले निगमों में शामिल है। इन्होंने अपने सीएसआर कोष का 33 प्रतिशत भारत को स्वच्छ बनाने के कार्यकलापों पर खर्च करने की वचनबद्धता व्यक्त की है। इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई ऐसे कार्य किए हैं जिन्होंने हजारों लोगों के जीवन पर अमिट प्रभाव छोड़ा है। उप-परियोजना स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत तेल एवं गैस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने देशभर के स्कूलों में 21,750 से अधिक शौचालयों का निर्माण किया है। इनमें से 95 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में हैं, जिनका इस्तेमाल 5 लाख से अधिक लड़कियां कर रही हैं। इन स्कूलों में बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में बहुत कमी आई है जिससे यह साबित होता है कि स्वच्छता किस प्रकार शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए दरवाज़े खोलती है।

Scanned by CamScanner

पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता

यद्यपि देश का इतिहास उसके स्मारकों के गौरव में संरक्षित है, लेकिन यहां आने वाले पर्यटक इनकी स्वच्छता की अनदेखी करते हैं और कचरा फैलाकर चले जाते हैं। जहां हर रोज हजारों की संख्या में लोग आते हों वहां स्वच्छता का संदेश फैलाना बहुत जरूरी है। तेल एवं गैस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के ऐसे दस स्थानों की पहचान कर, रखरखाव के लिए गोद लिया है। देश भर में फैले ये स्थल हैं- तिरुपति में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर, आगरा में ताजमहल, कटरा, जम्मू में वैष्णोदेवी, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, गंगोत्री, यमुनोत्री , गया और कालादी।

तेल एवं गैस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा हाथ में ली गई कुछ सर्वाधिक नवोन्मेशी परियोजनाओं में शामिल हैं- इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा तमिलनाडु के तंजावुर में स्थापित किया गया बंदीकूट रोबोटिक मैनहोल क्लीनर। इसने सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त किया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने, इस्तेमाल किए गए सैनेटरी पैड के निपटान के लिए गुजरात और राजस्थान में पर्यावरण के अनुकूल इनसिनेरेटर लगाए, जिनसे हजारों ग्रामीण महिलाओं को लाभ हुआ है। निगम ने असम, झारखंड और त्रिपुरा में पानी के तीन एटीएम और सौर आरओ वाटर प्योरिफायर भी लगाये हैं जिनका इस्तेमाल एक लाख से अधिक लोग कर रहे हैं। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन ने तमिलनाडु के पुनामल्ली और अवाडी में 33 माइक्रो कम्पोस्टिंग सेंटर स्थापित किए हैं। इनमें प्रतिदिन 174 मीट्रिक टन कम्पोस्ट का उत्पादन होता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. ने टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर चार राज्यों के 300 स्कूलों में 50,000 से अधिक विद्यार्थियों के लिए स्नान की सुविधा उपलब्ध कराई है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के साथ जुलाई 2018 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत ट्विन-पिट टॉयलेट के निर्माण के लिए 50 हजार से अधिक राजगीरों को प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। स्किल इंडिया ने कृषि अवशेष समूहक और कचरा प्रबंधन प्रबंधक जैसे कचरा प्रबंधन से संबंधित कौशल विकास के लिए नए कृत्य ईजाद किए हैं।

माननीय प्रधानमंत्री के विज़न के अनुरूप स्वच्छता, सरकार के एक कार्यक्रम से आगे बढ़कर भारत के लिए एक जीवन शैली बन गई है। स्वच्छता ही सेवा और स्वच्छता पखवाड़ा मनाने से स्वच्छ भारत अभियान के मूल संदेश को फैलाने में मदद मिली है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने हजारों लोगों को स्वच्छता अभियान के साथ जोड़ा है। उसने इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर श्रमदान के कार्यक्रम आयोजित किए और वाकाथॉन तथा साइक्लोथॉन रैलियों का आयोजन किया। मुझे यह बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को 2017 के स्वच्छ भारत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वास्तव में स्वच्छ भारत मिशन, लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी से एक जनांदोलन का रूप ले चुका है और इसने समाज में उत्तरदायित्व की भावना पैदा की है, लेकिन हमें अभी इस दिशा में बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अगले वर्ष 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएंगे। देश को खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त बनाकर हम राष्ट्रपिता को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं।

जब तक आप झाड़ू और बाल्टी अपने हाथ में नहीं लेंगे तब तक आप अपने शहरों और कस्बों को साफ नहीं रख सकते- महात्मा गांधी

जय हिंद!

सफलता की कहानी

केरल ने गोबर-धन के तहत पहला बायो-गैस प्लांट शुरू किया

केरल ने गोबर-धन योजना के तहत देश का पहला बायो-गैस प्लांट स्थापित किया है। राज्य के कन्नूर जिले के पण्योनिस्सेरी ग्राम पंचायत में स्थापित थुरुति कचरा ट्रीटमेंट संयंत्र सामुदायिक और बाजार जैसे व्यावसायिक स्थानों समेत सभी सार्वजनिक स्थानों से इकट्ठा किए गए जैविक-कचरे का उपयोग करेगा।

गोबर-धन योजना का मकसद कचरे को बायो ऊर्जा, गैस और कंपोस्ट में बदलना है। इससे न सिर्फ लोगों को फायदा होगा, बल्कि गांव में स्वच्छता भी बनाए रखने में मदद मिलेगी।

कन्नूर के नए संयंत्र की रोजाना 1,000 किलो कचरे के प्रबंधन की क्षमता है। अगर तकनीक की बात करें तो इस संयंत्र में भाभा परमाणु शोध केंद्र (बीएआरसी) द्वारा तैयार निसारगुणा बायोगैस तकनीक का उपयोग किया गया है।

इस संयंत्र से उप-उत्पाद के तौर पर 25 एम3 बायोगैस हासिल होने का अनुमान है। इस गैस का इस्तेमाल पास के एक और संयंत्र में बॉयलर ईंधन के रूप में किया जाएगा।

बायो-गैस जैव-ईंधन का सबसे प्रचलित रूप है और यह जानवरों के गोबर, फसलों के अवशेष, रसोई घर के कचरे आदि से प्राप्त किया जा सकता है।

गोबर-धन से सामान्य तौर पर गांव के लोगों और विशेष तौर पर महिलाओं को लाभ होगा। दरअसल, इससे स्वास्थ्य और गांव में स्वच्छता की स्थिति में सुधार होगा। इस पहल से स्वाभाविक रूप से नष्ट होने वाले कचरे को इकट्ठा कर इसे समृद्ध संसाधन के रूप में बदलने में मदद मिलेगी और किसानों और बाकी लोगों को आर्थिक फायदा मिल सकेगा।

Scanned by CamScanner

स्वच्छता क्रान्ति : बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन

परमेश्वरन अय्यर

> एसबीएम शेष विश्व के सामने सभी के लिए स्वच्छता में सुधार लाने का और मिशन मोड में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी विकास लक्ष्य संख्या 6 को प्राप्त कर लेने का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि अपने सभी प्रकार के व्यवहार परिवर्तन संवाद ही स्थायी परिवर्तन का एकमात्र साधन है

विविधता भरे अपने देश भारत जिसके 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 700 जिलों में 1 अरब, 30 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, जिसमें से लगभग 70 प्रतिशत छह लाख से अधिक गांवों में है। वर्ष 2014 तक देश भर में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या 60 करोड़ थी जो विश्व में ऐसे लोगों की संख्या का 60 प्रतिशत है। ऐसे में बीमारियों के फैलाव, उत्पादक कार्य के घंटों की हानि, मूलभूत सुविधाओं व सम्मान के अभाव और महिलाओं/बच्चों के साथ होने वाले अपराधों और हिंसा का बस अनुमान ही लगाया जा सकता है।

लेकिन 15 अगस्त, 2014 को उस समय सबकुछ बदल गया जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पहले सम्बोधन में देश के लिए एक नई ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत की और यह यात्रा खुले में शौच से मुक्त, स्वच्छ भारत के लिए थी।

अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को राष्ट्रीय विकास के एजेंडा में सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी थी। 60 करोड़ लोगों द्वारा खुले में शौच करना विश्व की स्वच्छता के लिए चिंता का प्रमुख कारण बना हुआ था। उसमें से अब 50 करोड़ की जनसंख्या को अब स्वच्छता क्रांति ने पिछले चार वर्षों में शौचालय उपलब्ध करवा दिए हैं। आज भारत में ग्रामीण स्वच्छता अभियान की पहुंच 95 प्रतिशत से अधिक लोगों तक हो गई है – यह एक ऐसा पड़ाव है जिसकी चार वर्ष पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लगभग 8 करोड़, 70 लाख घरों में

लेखक पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव हैं। ईमेल: param.iyer@gov.in

Scanned by CamScanner

शौचालयों का निर्माण होने से अब 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 529 जिलों के 5.1 लाख गांव अब खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। साथ ही विश्व बैंक की सहायता से कराए गए घरों के व्यापक स्वतंत्र सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि जिन घरों में शौचालय बने हुए हैं वहां 93 प्रतिशत लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान ने लोगों की सोच बदली है।

इस समूची प्रक्रिया में स्वच्छ भारत अभियान घर-घर में एक जाना पहचाना नाम बन गया, जिसमें सभी वर्गों के लोगों -विद्यार्थियों, अध्यापकों, व्यावसायिक घरानों, नागरिक संगठनों और सरकारी तंत्र ने इस देश को स्वच्छ और हराभरा बनाने में अपना योगदान दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आंदोलन से उस समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ जिसने आयु, जाति , लिंग, धर्म और शारीरिक क्षमता पर ध्यान दिए बिना समाज के सभी वर्गों तक अपनी पहुंच बनाई।

खुले में शौच करने की आदत में अग्रणी भारत विश्व में ऐसी मनोवृत्ति या व्यवहार बदलने की सबसे बड़ी योजना का हिस्सेदार कैसे बना? पिछले कई वर्षों से स्वच्छता पर विश्व के जाने-माने विशेषज्ञ बार-बार इस बात को रेखांकित कर रहे थे कि स्वच्छता के लिए सामुदायिक पहल (सीएएस) और समुदाय निर्देशित सम्पूर्ण स्वच्छता (सीएलटीएस) ही प्रवृत्ति में बदलाव की प्रमुख कुंजी है; यद्यपि 2014 आते-आते यह स्पष्ट हो गया था कि भले ही ऊपर वर्णित कुछ उपाय अनिवार्य थे लेकिन वे इतनी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसलिए स्वच्छ भारत अभियान की रणनीति में बदलाव आवश्यक हो गया था, जिससे विभिन्न चुनौतियों से निपटा जा सके। इन चुनौतियों में पैमाना या अनुपात, गति, मिथक और निरंतरता शामिल हैं।

पैमाना या अनुपात

60 करोड़ लोगों की मनोवृत्ति या व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान को अपने मापन मानकों को उचित मानते हुए स्वच्छ भारत मिशन की राष्ट्रीय टीम से अपनी व्यक्ति एवं समुदाय की मनोदशा और सोच में बदलाव ला सकने की क्षमता के अनुसार सम्पर्क और आदान-प्रदान करना था। आज 12 करोड़ स्कूली छात्र, 10 लाख कार्यकर्ता (जिसमें एक लाख महिलाएं हैं), 5 लाख स्वच्छाग्रही (जिसमें एक लाख महिलाएं हैं), ढाई लाख सरपंच, 700 जिला उपायुक्त, 400 जिला स्वच्छ भारत प्रेरक और 20 जाने-माने ब्रांड एम्बैसेडर शामिल हैं। इस टीम का नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे हैं।

गति

इस अभियान को प्रारम्भ करने और सुचारू ढंग से चलाने के लिए तात्कालिकता की आवश्यकता महसूस की गई। प्रधानमंत्री जी ने भी इस अभियान को छोटे-छोटे टुकड़ों में चलाने की कार्यविधि से बचने और भारत के स्वच्छता अभियान को गति देने के उद्देश्य से ही 2 अक्टूबर, 2019 को इस अभियान का समापन करने का आह्वान किया है।

टीम के गठन में तेजी लाने की भी आवश्यकता समझी गई क्योंकि इस अभियान की यह सबसे कमजोर कड़ी थी। इसे जमीनी स्तर से शुरू कर खड़ा करने में एसबीएम को यह सुनिश्चित करना था कि टीम का प्रत्येक सदस्य विश्वसनीय हो। हर नेतृत्व का यही वास्तविक व्यवहार (मनोवृत्ति) परिवर्तन होता है जो अभियान को आगे बढ़ाकर पीएम -सीएम-डीएम-वीएम मॉडल का स्वरूप देता है। प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच से मुक्त का संकल्प दिया। राज्यों में मुख्य मंत्रियों ने इसे आगे बढ़ाया। जिलाधिकारियों ने स्वच्छता की प्राथमिकताएं निर्धारित कीं और अभियान पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। इसके लिए उन्होंने ग्रामीण प्रेरकों और स्वच्छाग्रहियों को अधिकार दिए ताकि वे लोगों से व्यक्तिगत परस्पर संवाद करें और ग्रामीण क्षेत्रों की मनोदशा में बदलाव लाएं।

मिथक

विभिन्न समुदायों के अंदर स्वच्छता को लेकर सदियों से चले आ रहे मिथकों को स्वीकारे बिना एसबीएम आम लोगों की आदतों और मनोवृत्तियों को बदलने का अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता था। स्वच्छता को लेकर ग्रामीण भारत में बहुत-सी अवधारणाएं बनी हुई हैं - शौचालय केवल महिलाओं और बच्चों के काम के होते हैं, घर के अंदर शौचालय बनाने से वह अपवित्र हो जाता है, शौचालय की सफाई करना अपना काम नहीं है; इत्यादि।

इन समस्याओं का जमीनी स्तर पर समाधान करने के साथ ही केंद्रीय स्तर पर व्यापक प्रचार अभियान चलाए गए। प्रत्येक अभियान का मिथक तोड़ने के लिए अलग संदेश बनाया गया। बॉलीवुड की हस्तियों -अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा अभिनीत प्रचार अभियान **दरवाज़ा बंद** से शौचालयों के निर्माण में आशातीत सफलता मिली और इससे यह संदेश दिया गया कि शौचालय की जरूरत न केवल महिलाओं और बच्चों को बल्कि बड़ों और परिवार के हर सदस्य को पड़ती

Scanned by CamScanner

है। मीडिया ने भी अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म 'टॉयलेट एक प्रेमकथा' पर काफी कुछ चर्चा की। इस फिल्म में महिलाओं को खुले में शौच के लिए जाने पर होने वाली समस्याओं और परेशानियों का समग्र खाका खींचे जाने के साथ ही शौचालय बनाकर उससे होने वाले लाभों का अच्छा प्रस्तुतीकरण दिया गया था।

निरंतरता या दीर्घकालिकता

स्वच्छता अभियान के लय में आते ही एसबीएम ने अपना ध्यान जन आंदोलन को लगातार चलाने पर देना और इसमें हो रही ज़मीनी प्रगति पर भी देना शुरू किया। निरंतरता नीति के मुख्य घटक इस प्रकार थे :

खुले में शौच से मुक्त - गुणवत्ता (क्वालिटी) के अनुसार अभियान के अंतर्गत बनाए गए हर शौचालय की भूगर्भिक-पहचान (जीओ-टैगिंग) करनी होगी। सभी गांव दोहरी सत्यापन प्रणाली के अंतर्गत लाए गए हैं। इसमें स्वयं-प्रमाणन के साथ ही किसी अन्य पक्ष (थर्ड पार्टी) द्वारा प्रमाणन करने का प्रावधान है। घटिया किस्म का निर्माण पता चलने पर राज्य सरकार द्वारा तत्काल रिपोर्ट मंगवाए जाने और कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।

खुले में शौच से मुक्त - दीर्घकालिकता (ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी) में ओडीएफ की उपलब्धियों के बाद भी उसकी प्रासंगिकता को जारी रखने के प्रयास के रूप में आदतों और मनोवृत्ति में स्थायी बदलाव के लिए परस्पर संवाद चलाते रहें। इसके लिए संचालन और निगरानी (ओ एंड एम) का अपना महत्व है और एसबीएम सुरक्षित स्वच्छता गतिविधियों की निरंतरता के लिए संचालन कार्यप्रणाली को आगे भी समर्थन देने के साथ ही वित्तीय प्रोत्साहन भी देता है। इसके अलावा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भी एसबीएम पश्चात् दीर्घकालिकता के लिए इस समय एक दस वर्षीय स्वच्छता रणनीति पर भी कार्य कर रहा है।

ओडीएफ प्लस : एसबीएम शौचालयों से भी आगे जाकर स्वच्छ ग्राम बनाने के लिए कार्यरत है। इसके लिए यह खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट (कचरा और मलमूत्र) प्रबंधन उपायों को प्राथमिकता देने के अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के साथ मिलकर ओडीएफ ग्रामों में ग्रामीण पेयजल योजना को भी प्राथमिकता दे रहा है।

पिछले चार वर्षों के दौरान पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय सरकार के अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, गैर-सरकारी तथा अर्ध-शासकीय एजेंसियों, व्यावसायिक घरानों (कॉर्पोरेट्स), गैर-सरकारी संगठनों, धार्मिक संगठनों, समाचार माध्यमों (मीडिया) और अन्य संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि स्वच्छता केवल स्वास्थ्य विभागों की ज़िम्मेदारी न रहकर सभी का कर्तव्य बन जाए। इसके लिए बड़े स्तर से विशेष नवाचार एवं परियोजनाओं को लागू किया गया है।

इनके अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा (जिस अवधि में सभी केंद्रीय मंत्रालय/विभाग स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम एक पखवाड़े के लिए चलाते हैं), स्वच्छ प्रख्यात स्थान : (एक बहु-पक्षीय पहल जिसके अंतर्गत भारत के 100 से अधिक उन प्रख्यात स्थानों में स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता है जो अपनी विरासत, धार्मिक एवं/अथवा सांस्कृतिक पहचान के चलते प्रसिद्ध हैं।); स्वच्छता कार्य योजना (जिसके अंतर्गत 76 मंत्रालयों/विभागों को उनके स्वच्छता कार्य योजनाओं के लिए 5248 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है) एवं गंगा नदी के स्वच्छ प्रख्यात स्थान : (एक बहु-पक्षीय पहल जिसके अंतर्गत भारत के 100 से अधिक उन प्रख्यात स्थानों में स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता है जो अपनी विरासत, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान के चलते प्रसिद्ध हैं) एवं गंगा नदी के तटों पर बसे गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) करना सबसे नई पहल थी। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 जिसके अंतर्गत देश के 698 जिलों के 6980 गावों में एक स्वतंत्र सर्वेक्षण करवाया गया था।

यह कहना अतिशयोक्ति बिलकुल भी नहीं है कि यह मिशन विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान बन चुका है। वस्तुतः अब यह एक जन आंदोलन है, जिसमें सभी स्तरों पर देशवासी अनथक प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों की आदतों और व्यवहार में बदलाव लाकर वांछित लक्ष्य हासिल हो सके। महिलाओं के योगदान का तो कहना ही क्या? जो अभी तक सबसे अधिक इसलिए नहीं रहा कि अभियान से उन्हें जिस सम्मान और सुरक्षा की आवश्यकता थी वह मिला बल्कि इस वजह से कि यह अभियान उन्हें अपने परिवार की भलाई के साथ ही सामाजिक सुरक्षा का मिलना भी सुनिश्चित कर रहा है और महिलाओं ने अपने बचे हुए समय का त्याग करके, अपने परिवार की देखरेख के अतिरिक्त स्वच्छता कार्यों में बढ़-चढ़ कर भाग लेकर, प्रशासन को चुनौती देकर और शौचालय निर्माण जैसे पुरुषों के लिए निर्धारित माने गए कामों को पूरा करके चुनौतियों का सीधे सामना किया है।

गांवों में खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) की इस यात्रा में हमारी प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत, व्यवहार और आदतों में बदलाव की वे कहानियां हैं उन लोगों की जो इस कार्य के लिए आगे आये और जिन्होंने स्वच्छता के अधिकार तक पहुंच की मांग उठाई। हमारे स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के कुछ नायक इस प्रकार हैं :

'राज मिस्त्री के कार्य का महिलाओं को प्रशिक्षण देते समय सुनीता देवी ने पूरे मनोयोग से इसमें भाग लिया और दो गड्ढों वाले शौचालय का सही प्रकार से निर्माण करना सीखा। उसकी प्रतिभा को देखकर जिला प्रशासन ने उसे प्रमुख प्रशिक्षक नियुक्त किया। आज वह एक गांव से दूसरे गांव जाकर अन्य रानी मिस्त्रियों को प्रशिक्षित करती है। अभी तक वह 1600 से अधिक रानी मिस्त्रियों को प्रशिक्षण दे चुकी है।

'अपने आठ सदस्यीय परिवार की जिम्मेदारियों से परेशान हुए बिना राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की करजी पंचायत से आने वाली शंकरी मावी ने अपने घर का शौचालय बनाने के लिए राज मिस्त्री और मजदूर दोनों का काम किया। किसी से मदद लिए बिना रात में वह अपने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में हाथों में औजार लेकर शौचालय बनाती

सफलता की कहानी

खुले में शौच से मुक्त के अभियान में मुर्शीदाबाद की बड़ी छलांग

खुले में शौच से मुक्त हो चुके गांवों में किसी समुदाय के फिर से खुले में शौच के प्रचलन की तरफ लौट जाना काफी आम है। इसे रोकने के लिए पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद जिला प्रशासन ने खुले में शौच से मुक्त को टिकाऊ बनाने और इन गतिविधियों की फिर से जांच-पड़ताल के लिए जबरदस्त तैयारी की है।

पिछले कुछ महीनों के दौरान तकरीबन 5,000 वॉलंटियरों ने घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात की है और शौचालयों की वास्तविक स्थिति की भी जांच की है। इसके अलावा, इन वॉलंटियरों ने पूर्व में खुले शौचालय के लिए आम जगह रहे इलाकों का भी निरीक्षण किया है। इन अभियानों में 80 लाख से भी ज्यादा की आबादी समीक्षा के दायरे में आ गई और उनके व्यवहार में बदलाव दर्ज किया गया।

अहम बात यह है कि लोगों को अपने शौचालय का डिजाइन तैयार करने की स्वतंत्रता दी गई, बशर्ते वे उप-ढांचे को मंजूर डिजाइन के मुताबिक रखें। इससे लोगों में अपने शौचालय को लेकर काफी हद तक स्वामित्व की भावना विकसित करने में मदद मिली। फिलहाल, 3,88,758 घरों में शौचालय है, जो लोगों के अपने प्रयासों, पैसों और उनकी पसंद, संस्कृति और विरासत के हिसाब से तैयार किया गया है।

शौचालय को लेकर स्वच्छता टीमों द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई:

नजरदारी और गांधीगीरी: नेताओं और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ नजरदारी टीम का गठन किया गया। इस टीम ने निगरानी के लिए सुबह और शाम खुले में शौच की आशंका वाले क्षेत्रों का दौरा किया।

सभी के लिए शौचालय: समुदायों के बीच काम करने वालों ने घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात की और उन्हें परिवार के हर सदस्य (बच्चे और बुजुर्ग समेत) द्वारा शौचालय के उपयोग के महत्व के बारे में बताया। दिव्यांगों की मदद के लिए सीढ़ी या पट्टी जैसी चीजें बनाने का सुझाव दिया गया। बच्चों के मल-मूत्र का सुरक्षित से निपटारे पर भी विशेष ध्यान था।

कच्चा शौचालय तोड़ो अभियान: पूरे जिले में एक सप्ताह तक 'कच्चा शौचालय तोड़ो अभियान' चलाया गया। इस दौरान हजारों ऐसे शौचालय तोड़े गए और इससे संबंधित क्षेत्रों को साफ किया गया।

शैक्षणिक संस्थानों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर फोकस: इसके तहत 2,633 स्कूलों के करीब 8 लाख छात्र-छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इसका मकसद उनकी सोच को बदलना था। यह अभियान इतना ताकतवर था कि छात्र-छात्राओं ने शौचालय की खातिर अपने माता-पिता को चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी। ग्राम पंचायत टीमों का गठन किया गया, जिसमें नेता और शिक्षक शामिल थे। इन टीमों ने गांव और स्कूल स्तर पर शपथ लेने, भूमिका अदा करने और सामूहिक फैसले जैसी गतिविधियों की शुरुआत की, जिससे सामुदायिक सहमति बनाने में मदद मिली।

स्वच्छता कार्ड: शौचालय का इस्तेमाल करने वाले हर घर को स्वच्छता कार्ड जारी किया गया।

मुक्ति: मुक्ति परियोजना के तहत जिले में खुले शौच वाली जगहों की पहचान की गई और उन जगहों पर मनरेगा के जरिये जमीन पर पौधा लगाने और हरियाली विकसित कर उसमें बदलाव करने की योजना तैयार की।

बाल कैबिनेट: सभी स्कूलों में बाल कैबिनेट बनाया गया और इसमें छात्र-छात्राओं की मौजूदगी के जरिये उनके बीच स्वच्छता के प्रचलन की पड़ताल की गई। साथ ही, इन छात्र-छात्राओं को पास के गांवों में जाने और सुरक्षित शौचालयों के सतत इस्तेमाल को बढ़ावा देने को कहा गया।

बाढ़ की आशंका वाले इलाकों से निपटना: बाढ़ के दौरान आम लोगों द्वारा हाई स्कूल या सामुदायिक हॉल में शरण लेना आम बात है। ऐसे में जिला प्रशासन ने बाढ़ के दौरान शौचालय का उपयोग करने के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालय बनाना शुरू किया है।

Scanned by CamScanner

और दिन के समय अपने खेतों में फसल की देखरेख करती। इस तरह उसने अपनी खेती-बाड़ी के काम के साथ भी न्याय किया और अपने घर की स्वच्छता जरूरतें पूरी करने के लिए शौचालय भी बना लिया।

'मुर्शीदाबाद जिले की रहने वाली एसबीएम-जी की सक्रिय प्रचारक शमशल बेगम का निकाह तय हो गया था। उन्हें जब एक मोबाइल फोन विक्रेता तौसीफ रजा अहमद के घर से विवाह का प्रस्ताव आया तो उन्होंने रजामंद होने के साथ भी कुछ शर्तें रखीं-जिसमें उनके दूल्हे के मुर्शिदाबाद जिले के गांव वाले घर में अच्छे शौचालय का निर्माण करना भी था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक उत्साहित करने वाली रिपोर्ट के अनुसार एसबीएम के कारण वर्ष 2014 से अक्टूबर, 2019 की अवधि में अतिसार (डायरिया) और प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण से होने वाली तीन लाख मौतों से बचा जा सकेगा। इसका कारण देश में खुले में शौच करने वालों की संख्या में कमी आना और शौचालयों की संख्या का बढ़ना है। इसी के साथ ही यूनिसेफ के एक अनुमान के अनुसार किसी भी खुले में शौच करने से मुक्त समुदाय में चिकित्सा पर होने वाले व्यय से बचने, समय की बचत और मौतों से बचने की लागत पर विचार किया जाए तो यह प्रत्येक घर के लिए लगभग 50,000 रुपये प्रतिवर्ष की बचत के बराबर होता है और समाज के सबसे निर्धन तबके के लिए ये लाभ सबसे बढ़कर हैं।

अभियान के अब तक हुए प्रभाव के अतिरिक्त इस अतुल्य उद्यम ने समग्र विकास एजेंडा के लिए कई सबक दे दिए हैं कि बड़े पैमाने पर व्यवहार एवं मनोवृत्ति में परिवर्तन के कार्यक्रम कैसे चलाए जाने चाहिए? अनुपात, गति, मिथक और दीर्घकालिक आवश्यकताएं पूरी करते हुए एसबीएम ने 4 अन्य बिन्दुओं के महत्व से जुड़े अनुभवों का निरूपण किया है। ये हैं-

राजनैतिक नेतृत्व : सर्वोच्च स्तर पर राजनैतिक इच्छाशक्ति, नेतृत्व क्षमता अत्यधिक महत्व रखते हैं।

लोक वित्त पोषण : अभियान के लिए धन की कमी न हो इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने एसबीएम के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का वित्तपोषण किया है।

सहभागिता : विकास सहयोगियों, गैर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी और मीडिया के साथ निरंतर सम्पर्क।

जन सहयोग : स्वच्छता सरकारी कार्यक्रम न होकर एक जन आंदोलन है।

अपने स्वयं के परिवेश और स्वच्छता के कार्य का उत्तरदायित्व लेते हुए ग्रामीण भारत 2 अक्टूबर, 2019 तक पूरे होने वाले स्वच्छ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। एसबीएम शेष विश्व के सामने सभी के लिए स्वच्छता में सुधार लाने का और मिशन मोड में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी विकास लक्ष्य संख्या 6 को प्राप्त कर लेने का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि अपने सभी प्रकार के व्यवहार परिवर्तन संचार ही स्थायी परिवर्तन का एक मात्र साधन है। इस तथ्य को 59 देशों के उन सभी मंत्रियों ने तब स्वीकार किया जब वे 29 सितंबर, 2018 से 2 अक्टूबर, 2018 तक नई दिल्ली में आयोजित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए। स्वच्छता के स्वच्छ भारत मॉडल ने भारत में ऐसी स्वच्छता क्रांति का सूत्रपात किया है जो विश्व को अपने प्रभावों से अभिभूत कर रही है। ❑

Scanned by CamScanner

स्वच्छता ही सेवा

15 सितंबर, 2018 को शुरू हुए 'स्वच्छता ही सेवा 2018' अभियान के तहत देश भर के लाखों-करोड़ों लोग साफ-सफाई संबंधी गतिविधियों से जुड़ रहे हैं। इन गतिविधियों में अलग-अलग समूहों ने जिस तरह से हिस्सा लिया है, उसके आधार पर इस अभियान को स्वच्छता के लिए 'जन आंदोलन' कहना अनुचित नहीं होगा। यह अभियान स्वच्छ भारत अभियान की चौथी वर्षगांठ (2 अक्टूबर, 2018) से ठीक पहले शुरू किया गया था।

महबूबाबाद में संकल्प लेते छात्र

स्वच्छता ही सेवा अभियान का मकसद कुछ इस तरह है:

- स्वच्छ भारत जन आंदोलन को नई ऊर्जा से लैस करना
- स्वच्छ भारत अभियान को अंतिम चरण में रफ्तार देना
- स्वच्छता को 'हर किसी की ज़िम्मेदारी' के तौर पर आगे बढ़ाना

स्वच्छ भारत अभियान की चौथी वर्षगांठ से ठीक पहले के पखवाड़े में तकरीबन 20 करोड़ लोगों को स्वच्छता अभियान के लिए सक्रिय किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, संबंधित अवधि में बड़ी संख्या में एनजीओ, स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक नेताओं, उद्योग जगत, सरकारी अधिकारियों, जिलाधिकारियों और सरपंचों ने श्रमदान गतिविधियों में हिस्सा लिया। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों की बड़े पैमाने पर सफाई, कचरा हटाना और कचरा प्रबंधन की अन्य गतिविधियों पर काम, घर-घर जाकर स्वच्छता संबंधी जागरूकता फैलाना, नुक्कड़ नाटक और लोक गीतों के जरिये सूचना, शिक्षा और जागरूकता मुहैया कराना, स्वच्छता रैलियों, दीवारों पर पेंटिंग आदि गतिविधियों के जरिये प्रयास किए गए। साथ ही, शौचालय निर्माण और पुराने शौचालयों में नई सुविधाएं जोड़ने, कंपोस्ट गड्ढे का निर्माण जैसी गतिविधियों को भी अंजाम दिया गया।

मदुरै में छात्र-छात्राएं

तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में ग्राम पंचायत के सभी कर्मियों द्वारा श्रमदान किया गया। जिला प्रशासन ने जहां स्वच्छता ही सेवा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया और ऑटो पर जागरूकता के मकसद से पोस्टर चिपकाए, वहीं स्कूली छात्रों ने स्वच्छता का संकल्प लिया और साफ-सफाई संबंधी में भागीदारी भी की।

इसके अलावा, तमिलनाडु के मदुरै पूर्व प्रखंड में सरकारी ओथाकडाई प्राथमिक स्कूल के छात्र-छात्राओं व शिक्षकों ने स्वच्छता का संकल्प लिया और इसके बाद अपनी कक्षा और विद्यालय के अहाते की सफाई की। साथ ही, हर कक्षा में एक कचरे का डब्बा भी रखा गया। स्कूल में प्रार्थना के दौरान छात्रों के कपड़ों की सफाई की निगरानी की गई और दोपहर में भोजन करने से पहले सभी छात्र-छात्राएं हाथ धोने के लिए कतार में इकट्ठा हुए। हर शौचालय में साबुन और तौलिया रखा गया। इस बीच, मदुरै जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वच्छता सैनिकों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों ने भी आम लोगों के साथ स्वच्छता का संकल्प लिया। तूतीकोरिन यानी थुथुकुडी में जिलाधिकारी ने 'स्वच्छता ही सेवा-2018' अभियान के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हस्ताक्षर अभियान के साथ थुईमाई (Thooimai) रथम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

जम्मू-कश्मीर में 15 सितंबर, 2018 को राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य को खुले में शौच से मुक्त करने का ऐलान करते हुए 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान की शुरुआत की। युवाओं को इस अभियान से जोड़ने और स्वच्छता पर उनके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मंच मुहैया कराने की खातिर जम्मू के एक स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही, जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले की मानसबल झील में जंगली घास और अन्य गंदगी को साफ किया गया। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक के वित्तीय समावेशन और बीमा विभाग ने नाबार्ड के साथ मिलकर जम्मू, राजौरी, पुंछ, कठुआ, सांबा, बांदीपुर, बारामुला और कुपवाड़ा समेत राज्य के विभिन्न जिलों में 'स्वच्छता ही सेवा' से जुड़े 56 कार्यक्रमों का आयोजन किया।

Scanned by CamScanner

अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग के बुद्धा पार्क में 15 दिनों तक चलने वाले 'स्वच्छता ही सेवा' कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दूसरी तरफ, 'स्वच्छता ही सेवा' के दूसरे दिन पश्चिम सियांग जिले के सरकारी अधिकारी श्रमदान के लिए एकजुट हुए।

इंफाल (मणिपुर) में पीएचईडी और मेडिलेन की अगुवाई में डॉक्टरों, नर्सों और पारामेडिकल स्टाफ ने यहां के सेंचियो इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल में मोबाइल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में तकरीबन 300 छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। इसके बाद हाथ धोने के संबंध में भी प्रदर्शन कर बताया गया। मणिपुर में विष्णुपुर की जिला जल और स्वच्छता कमेटी ने 17 सितंबर को इंफाल के पास पंचायत संसाधन केंद्र 'स्वच्छता ही सेवा' कार्यक्रम का आयोजन किया।

मणिपुर में छात्र-छात्राएं

मेघालय में दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स के उपायुक्त ने 17 सितंबर, 2018 को 'स्वच्छता ही सेवा' और स्वच्छता श्रमदान की शुरुआत की। इसके बाद मवक्यर्वत के लैत्लावसांग इलाके में सड़क के दोनों तरफ सफाई अभियान चलाया गया। इस बीच, दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स ने जिला खेल कार्यालय और टूरा धावक क्लब के साथ 22 सितंबर, 2018 को मिलकर स्वच्छता ही सेवा दौड़ का आयोजन किया। इस दौड़ के आयोजन का मकसद गांवों को साफ और हरा-भरा बनाने के लिए जागरूकता फैलाना था। इस कार्यक्रम का आयोजन दो श्रेणियों में किया गया- हाफ मैराथन और विशेष दौड़। इसके अलावा, 15 दिनों तक चले इस अभियान के तहत बाजार और भीड़-भाड़ वाली सभी जगहों पर स्वच्छता, स्वास्थ्य, शौचालय निर्माण, कचरा प्रबंधन और समूह सफाई अभियान पर आधारित नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए गए।

उत्तर प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 'स्वच्छता ही सेवा 2018' अभियान के उद्घाटन के मौके पर कहा, 'यह अभियान अब सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं रह गया है, बल्कि ऐसे जन आंदोलन में बदल गया है जिसे देश के लोगों ने दिल से स्वीकार किया है।' साथ ही, सोनोवाल ने कामरूप के बोको में पाइप के जरिये पानी की आपूर्ति वाली योजना, 'मिशन 100' की भी शुरुआत की।

पंजाब में दोरांगला प्रखंड में सरकारी हाई स्कूलों के छात्र-छात्राओं को खुले में शौच के बुरे असर के बारे में बताया गया। छात्र-छात्राओं को व्यक्तिगत स्वास्थ्य और घर व स्कूल के आसपास साफ-सफाई रखने की जरूरत के बारे में भी प्रेरित किया गया। उन्हें साफ पीने का पानी इस्तेमाल करने और प्लास्टिक व थर्मोकॉल वाली चीजों के उपयोग से बचने को भी सलाह दी गई। एसबीएस नगर जिले के खालसा कॉलेज में स्वच्छता संबंधी संकल्प भी लिए गए।

अन्य गतिविधियां

- हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्कूली बच्चे स्वच्छ भारत अभियान की आवाज बन रहे हैं। ये बच्चे स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रैली में भी शामिल हुए।
- उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में शामिल होने और स्वच्छता का संदेश फैलाने के लिए कई समूह और समुदाय के लोग इकट्ठा हुए।
- महाराष्ट्र के सोलापुर में गड्ढों वाले शौचालयों को खाली किया गया।
- झारखंड की राजधानी रांची में स्कूली छात्रों ने स्वच्छता संबंधी विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया।
- बिहार के मधेपुरा में श्रमदान के लिए लोग अपने-अपने घरों से निकले।
- बड़ी संख्या में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने देशभर में स्वच्छता अभियान चलाया। ❑

जम्मू-कश्मीर में झील की सफाई

Scanned by CamScanner

स्वास्थ्य सेवाओं में साफ-सफाई

प्रीति सूदन

स्वच्छता और साफ-सफाई की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिये भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बहुआयामी नीति अपनाई है और समग्र रूप से स्वच्छता और साफ-सफाई में सुधार के लिये अनेक पहलें शुरू की हैं। 2015 से इसने विशेष तौर पर स्वच्छता को हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य और सेहत में सुधार के अपने प्रयासों का केंद्र बिंदु बना दिया है। इन पहलों ने स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ समुदाय में उसके अपने कार्यक्रमों के जरिए तथा अन्य मंत्रालयों की साझेदारी में भी इस मामले के व्यापक हल के लिये स्वच्छता और साफ-सफाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है

प्रत्येक व्यक्ति की एक स्वच्छ और सुखद वातावरण में रहने और काम करने की इच्छा होती है। बीमार और घायल का इस तरह के परिवेश में तेज़ी से उपचार होता है। प्राचीन काल में सर्जरी प्रक्रियाएं प्रातःकाल के समय नदियों के किनारे स्वच्छ जल और वायु तथा आसपास की साफ-सफाई का लाभ उठाने के लिये ही संचालित की जाती थीं। समय बीतने के साथ-साथ शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे प्राकृतिक संसाधन लुप्त होते जा रहे हैं, जिसका मानव स्वास्थ्य और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। लिक्विड ग्रुप कार्पोरेशन, वॉटर एअर एंड ऑक्सफोर्ड इकोनोमिक्स ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया है कि 2015 में स्वच्छता की कमी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को करीब 222.9 अरब अमरीकी डॉलर की क्षति हुई। यह 2010 में हुई क्षति का लगभग 1.2 गुणा थी, जिसमें मात्र पांच वर्षों में 40 अरब अमरीकी डॉलर का इज़ाफा हो गया।

स्वच्छता और साफ-सफाई की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिये भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बहु आयामी नीति अपनाई है और समग्र रूप से स्वच्छता और साफ-सफाई में सुधार के लिये अनेक पहलें शुरू की हैं। 2015 से इसने विशेष तौर पर स्वच्छता को हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य और सेहत में सुधार के अपने प्रयासों का केंद्र बिंदु बना दिया है। इन पहलों ने स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ समुदाय में उसके अपने कार्यक्रमों के जरिए तथा अन्य मंत्रालयों की साझेदारी में भी इस मामले के व्यापक हल के लिये स्वच्छता और साफ-सफाई में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की कायाकल्प पहल 2015 में सभी 36 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में केंद्रीय सरकार के संस्थानों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बुनियादी ढांचे के बेहतर रखरखाव, स्वच्छता और साफ-सफाई, तथा संक्रमण नियंत्रण उपायों में सुधार के उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। स्वास्थ्य सुविधाओं का अनेक मापदंडों के साथ मूल्यांकन किया जाता है और अंक प्रदान किये जाते हैं, तथा हर वर्ष प्रत्येक स्तर पर उच्चतम स्कोर हासिल करने वाली सुविधाओं को कायाकल्प पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है, जिसमें प्रशस्ति-पत्र के अलावा नकद पुरस्कार दिये जाते हैं। कायाकल्प योजना के परिणामस्वरूप

लेखिका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव हैं। ईमेल: secyhfw@nic.in

Scanned by CamScanner

सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में स्वच्छता, साफ-सफाई और संक्रमण नियंत्रण व्यवहारों के स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है तथा साफ-सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये नियमित मूल्यांकन तथा स्थिति की समीक्षा की संस्कृति को प्रोत्साहित किया गया है। कायाकल्प योजना की उपलब्धियों से प्रोत्साहित होकर निजी क्षेत्र भी आगे आया है और सरकार के प्रयासों में शामिल हो गया।

अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिये राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड (एनएबीएच) ने कायाकल्प के मापदंडों के अनुरूप निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का मूल्यांकन करने पर विचार करने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों (वीएचएसएनसी) तथा कमज़ोर शहरी समुदायों में स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) के अधीन महिला आयोग समितियों (एमएएस) के मंचों का प्रयोग किया है। कई राज्यों ने वीएचएसएनसी और एमएएस को प्रभावी बनाने में अभिनव व्यवहारों को अपनाया है। समुदाय को शौचालयों के निर्माण और इस्तेमाल के लिये एकजुट करने के वास्ते आशा कार्यकर्ता भी वीएचएसएनसी के साथ मिलकर काम करती हैं। एमएएस ने हाल में करीब 12 से 20 सामुदायिक समूहों की स्थापना की है।

एमएएस ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों में मुख्यत: ग़रीब और कमज़ोर लोगों में से करीब 12 से 20 महिलाओं के सामुदायिक समूहों का गठन किया है और स्वच्छता सहित विभिन्न मुद्दों पर समुदायों को एकजुट करने का काम कर रही है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर अपने प्रयासों के जरिये भी स्वच्छता में सुधार के लिये काम कर रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के बीच ऐसी एक संयुक्त पहल स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र है जो कि ग्राम पंचायतों को, जहां पर कायाकल्प पुरस्कृत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित हैं, खुले में शौच से मुक्त बनाने के वास्ते उन्हें धनराशि प्रदान करने में सहायता करते हुए स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) और कायाकल्प के बीच तालमेल बिठाने का एक प्रयास है।

विश्वास

स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता

पर साथ-साथ काम के लिए ग्राम आधारित पहल

विश्वास के अधीन 11 मासिक अभियान दिवस

1. स्वच्छता अभियान के लिये वार्षिक योजना दिवस
2. ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता दिवस (ग्राम स्वच्छता के घटक तथा साफ-सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच संबंध)
3. खुले में शौच मुक्त ग्राम दिवस
4. हाथ धुलाई दिवस
5. स्कूल और आंगनवाड़ी स्वच्छता दिवस
6. तरल और ठोस कचड़ा प्रबंधन दिवस
7. व्यक्तिगत और आवास सफाई दिवस (सुरक्षित जल और खाद्य रखरखाव, पेयजल का बेहतर रखरखाव)
8. स्वास्थ्य जागरूकता दिवस/स्वस्थ जीवनचर्या दिवस
9. वेक्टर नियंत्रण दिवस
10. स्वच्छता चैंपियन्स के लिये सभारोही दिवस
11. स्वच्छता और साफ-सफाई पर ग्राम सभा।

2017 में, स्वच्छता और साफ-सफाई कार्यों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के अपने प्रयासों के भाग के तौर पर एनएचएम ने विश्वास-स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता के तालमेल के लिये एक नए अभियान की शुरुआत की। ग्राम आधारित यह पहल-वीएचएसएनसी द्वारा जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर कार्रवाई हेतु सामुदायिक जागरूकता के निर्माण और स्थानीय चैंपियन्स तैयार करने तथा स्वच्छ भारत मिशन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के बीच समन्वय के निर्माण के लिये एक मंच तैयार करने के लिए थी। इन पहलों के अधीन अपनाई गई प्रमुख रणनीतियों का विवरण निम्नलिखित खण्डों में दिया गया है:-

स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये कायाकल्प- कायाकल्प कार्यक्रम का

Scanned by CamScanner

कचरों का वर्गीकरण

उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता, स्वास्थ्य और साफ-सफाई से संबंधित नियमित मूल्यांकन और कार्यनिष्पादन की समीक्षा की संस्कृति का विकास करना और वर्धित स्वच्छता से संबंधित सतत व्यवहारों का आदान-प्रदान और सकारात्मक स्वास्थ्यकर परिणामों के साथ उन्हें जोड़ना है।

योजना के अधीन, स्वास्थ्य सुविधाएं अपना स्वयं का मूल्यांकन करती हैं, सुविधाओं में सुधार, जैव-चिकित्सा कचड़ा नियमों के कार्यान्वयन, संक्रमण नियंत्रण व्यवहारों के सुदृढ़ीकरण और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों/नागरिक समाज के साथ साझेदारी के लिये काम करती हैं। सुविधा के भीतर और 'चारदीवारी' के बाहर भी 'स्वच्छता' के प्रत्येक परिमाण के लिये पूर्वनिर्धारित मूल्यांकन मापदंड हैं। तदुनसार सुधार दर्शाने वाली सुविधाएं कठोर मूल्यांकन से गुजरती हैं, जिसके बाद कायाकल्प स्कोर के वैधीकरण के लिये बाह्य मूल्यांकन होता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के उत्कृष्ट प्रयासों के लिये सुविधाओं के प्रत्येक स्तर पर कायाकल्प पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का चयन राज्य स्तर पर विकेंद्रीकृत किया जाता है जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिये यह जिला स्तर पर होता है।

एक निर्धारित मापदंड के आधार पर, विजेता सुविधा को प्रशस्ति-पत्र के साथ नकद पुरस्कार प्राप्त होता है। इसके अलावा कायाकल्प मापदंड के अधीन 70 प्रतिशत से अधिक स्कोर प्राप्त करने वाली सभी सुविधाओं को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है ताकि बड़ी संख्या में सुविधाओं को प्रेरणा मिल सके। योजना के अधीन केंद्रीय सरकार के संस्थान को 2.5 करोड़ रुपये तक की नकद राशि प्राप्त होती है जबकि विजेता जिला अस्पताल को 50 लाख रुपये, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 15 लाख रुपये और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 2 लाख रुपये प्राप्त होते हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में, सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कार्यक्रम की शुरूआत कर दी गई और जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों / उपजिला अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित 28,000 से अधिक सुविधाओं का मूल्यांकन किया गया, जिसमें से 2970 सुविधाओं-11 केंद्रीय सरकार के संस्थानों, 289 जिला अस्पतालों, 760 उप जिला अस्पतालों / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 1729 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 181 शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कृत किया गया।

राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के भाग के तौर पर 'कायाकल्प' पहल की शुरूआत के लिये संपूर्ण सहयोग प्रदान किया जाता है और पुरस्कारों, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, अस्पताल सुधार और तकनीकी सहायता के लिये धनराशियां प्रदान की जाती हैं। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कायाकल्प के विभिन्न आयामों को लेकर प्रशिक्षण संचालित किये गये हैं। सुविधाओं का मूल्यांकन सात व्यापक विषयागत क्षेत्रों में (और इनमें से प्रत्येक के भीतर विनिर्दिष्ट मानदंड तथा जांच बिंदुओं के निर्धारण के अधीन) संचालित किया जाता है, ये हैं: क) अस्पताल/सुविधा का रखरखाव, ख) स्वच्छता और साफ-सफाई, ग) कचड़ा प्रबंधन, घ) संक्रमण नियंत्रण, ड़) समर्थन सेवाएं, च) स्वास्थ्य प्रोत्साहन, छ) अहाते के बाहर कायाकल्प।

कायाकल्प पहल के अधीन गतिविधियों को सोशल मीडिया पर भी साझा किया जाता है:- https://www.facebook.com/pages/Kayakalp/586316831510706.

कायाकल्प कार्यक्रम का प्रभाव:- कायाकल्प की शुरूआत के बाद, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ-सफाई, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण के स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। कार्यक्रम ने साफ-सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये संचालित मूल्यांकन और कार्यनिष्पादन की समीक्षा की एक संस्कृति का भी निर्माण किया है। इसने स्वास्थ्य प्रणालियों के सुधार के लिये विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय बढ़ाने के वास्ते अवसर और प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराये हैं।

स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र

स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र, वर्धित स्वच्छता के जरिए बेहतर स्वास्थ्यप्रद परिणाम हासिल करने और स्वस्थ जीवनचर्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा पेयजल

Scanned by CamScanner

एवं स्वच्छता मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य दो पूरक कार्यक्रमों-स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) और कायाकल्प के बीच अधिक समन्वय रखना है।

इस योजना के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं:-

1. उन ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त बनने में सहयोग करना, जहां कायाकल्प पुरस्कृत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित है।
2. खुले में शौच से मुक्त खण्डों में स्वच्छता के उच्च स्तर हासिल करने के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन 10 लाख रुपये की सहायता से कायाकल्प मानदंड पूरा करने के वास्ते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सुदृढ़ीकरण करना।
3. ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से नामांकित व्यक्तियों को जल, स्वच्छता और साफ-सफाई (धुलाई) में प्रशिक्षण के जरिए क्षमता निर्माण।

इस पहल के अधीन, तकनीकी सहायता और 10 लाख रुपये की सहायता के जरिए स्वच्छता के मानदंडों का पालन करते हुए कायाकल्प पुरस्कार के लिये कार्य में सहायता करने के लिये खुले में शौच से मुक्त खण्डों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिये धनराशि आवंटित की गई है। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में साफ-सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता हेतु कार्य करने की अपेक्षा होती है ताकि पंचायतें खुले में शौच का दर्जा हासिल करने के लिये सामूहिक प्रयास करें।

ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समितियां

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वच्छता और साफ-सफाई की पहलों को सदैव प्रोत्साहित और समर्थन किया है तथा इन्हें सामुदायिक स्तर के स्वास्थ्य संवर्द्धन उपायों से संबद्ध किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, 2005 में इसकी शुरुआत से, स्वच्छता में सुधार लाने और स्वास्थ्य परिणाम हासिल करने में समुदायों को एकजुट करने की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट तौर पर उल्लेखित करते हुए 'स्वास्थ्य पर सामुदायिक कार्रवाई हेतु मंच' के तौर पर सभी राज्यों में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समितियों का गठन किया है। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समितियां ग्राम स्तर पर गठित की गईं और स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य से जुड़े अन्य सामाजिक कार्यों पर सम्मिलित कार्रवाई के लिये समुदाय की स्वयं की पहलों में सहयोग के लिये प्रति वर्ष 10000 रुपये की 'मुक्त राशि' उपलब्ध कराई गई। बाद में इन समितियों के लिये पोषण को केंद्र बिंदु बनाते हुए इनका नाम बदलकर ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समितियां (वीएचएसएनसी) कर दिया गया। वीएचएसएनसी साथ में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, वर्तमान में एनआरएचएम के अधीन सामुदायिकता रणनीति के प्रमुख घटक बन गये। 2013 में जारी वीएचएसएनसी के लिये संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक गांव में समुदाय और पंचायत प्रतिनिधियों की अधिक सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये स्थानीय ग्राम पंचायत सदस्य को वीएचएसएनसी का अध्यक्ष बना दिया गया (इससे पहले यह ग्राम पंचायत सरपंच होता था)।

वर्तमान में करीब 5.2 लाख वीएचएसएनसी कार्यरत हैं (लक्ष्य के मुकाबले 92 प्रतिशत वीएचएसएनसी गठित किये गये जिनमें से 97 प्रतिशत के बैंक खाते हैं)। राज्यों ने अपने वीएचएसएनसी को प्रभावी बनाने के लिये अभिनव व्यवहारों को अपनाया है। उदाहरण के लिये छत्तीसगढ़ ने अपने वीएचएसएनसी को आशा कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी के जरिए सुदृढ़ किया है तथा वीएचएसएनसी को स्वस्थ ग्राम पंचायत योजना का हिस्सा बना दिया है, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को हर वर्ष रैंक प्रदान किया जाता है और स्वास्थ्य तथा इसके सामाजिक निर्धारकों से संबंधित मापदंडों के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है। राज्य की वीएचएसएनसी को मुद्दों और योजनागत कार्रवाइयों पर अधिक प्रभावी वार्तालाप करने में समर्थन करने के लिये स्थानीय स्तर के परिसंघों के तौर पर भी एकजुट किया गया है। ओडिशा में प्रत्येक ग्राम पंचायत तिमाही में वीएचएसएनसी को एक बार बैठक आयोजित करती है और उनके समर्थन और निगरानी में सक्रिय

Scanned by CamScanner

भूमिका निभाती हैं। अन्य राज्यों ने भी अपने वीएचएसएनसी को प्रभावी बनाने के लिये अपने स्वयं की पहलें शुरू की हैं।

आशा कार्यकर्ता वीएचएसएनसी की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और न केवल समुदाय स्तर पर जागरूकता में सुधार के लिये काम करती हैं और वीएचएसएनसी को उनके गांवों में गतिविधियों के लिये समर्थन और सहयोग प्रदान करती हैं बल्कि समुदाय को शौचालयों का निर्माण करने और उनका इस्तेमाल करने के लिये भी एकजुट करती हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा पेयजल आपूर्ति मंत्रालय के आशा कार्यकर्ताओं का इस भूमिका को निभाने के लिये सशक्तिकरण करने के लिये जारी संयुक्त निर्देशों से (प्रति शौचालय 75 रुपये के प्रोत्साहन का प्रावधान करके) ज़मीनी स्तर पर उनके प्रयासों को बल मिला है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन राज्यों के लिये अपने वार्षिक कार्यक्रम की स्वीकृति के ज़रिए वीएचएसएनसी के क्षमता निर्माण और सुदृढ़ीकरण की गतिविधियों का निरंतर समर्थन किया है। वीएचएसएनसी के संचालन के लिये राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण भी समय-समय पर संचालित किये गये हैं। प्रशिक्षकों के राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के हाल के दौर 2016 और 2017 में संचालित किये गये।

एनयूएचएम के अधीन महिला आरोग्य समितियां (एमएएस)

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) में भी स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी प्रयासों पर समान रूप से ज़ोर दिया जाता है। वीएचएसएनसी की तरह एनयूएचएम के अधीन शहरों में महिला आरोग्य समिति (एमएएस) गठित की गई हैं। एमएएस किसी शहरी क्षेत्र में मुख्यतः ग़रीब और कमज़ोर वर्गों के समुदाय में करीब 12 से 20 महिलाओं के समूह होते हैं। एनयूएचएम के अधीन, एमएएस के गठन और प्रशिक्षण की प्रक्रियाओं का सक्रियता के साथ समर्थन किया जा रहा है। प्रत्येक एमएएस को वीएचएसएनसी की तरह प्रति वर्ष 5000 रुपये मुक्त राशि उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में विभिन्न राज्यों में करीब 74000 एमएएस गठित किये गये हैं परंतु कार्यक्रम अब भी जारी है। यद्यपि एमएएस अपेक्षाकृत हालिया पहल है, वे समुदायों को विशेषकर स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों में एकजुट करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

विश्वास (स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता के संयोजन के लिये ग्राम आधारित पहल) अभियान

2017 में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने स्वच्छता और साफ-सफाई संबंधी उपायों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के अपने प्रयासों के भाग के तौर पर एक नया अभियान, विश्वास-स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता के संयोजन के लिये ग्राम आधारित पहल की शुरूआत की, जो कि वीएचएसएनसी

सफलता की कहानी

कलबुर्गी के लिए स्वच्छ स्वतंत्रता दिवस

कर्नाटक के कलबुर्गी जिला पंचायत ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता को जीवन शैली बनाने के लिए अलग तरीके से लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया। इसके तहत स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पुलिस परेड मैदान में 5,000 से भी ज्यादा लोगों को प्रदर्शन के जरिये हाथ धोने के तौर-तरीके बताए गए।

पूरे जिले के आवासीय स्कूलों के 600 से भी ज्यादा छात्र-छात्राओं द्वारा हाथ धोने के बेहतर तरीकों के बारे में प्रदर्शन के जरिये जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम इस लिहाज से अनोखा था कि इसके दौरान गांधी के स्वच्छता संबंधी आह्वान पर जोर दिया गया। इस अवसर पर 72वें स्वतंत्रता दिवस को दर्शाने के लिए तिरंगे में 72 की संख्या जैसी आकृति भी नजर आ रही थी। इस कार्यक्रम की थीम **स्वच्छमेव जयते** थी और इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण का लोगों भी शामिल था।

कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय बोली में एक छोटे से नाटक से हुई और छात्र-छात्राएं मिठाई खाकर स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे थे। हालांकि, मिठाई खाने से पहले उन्होंने अपने-अपने हाथ धोए। इसके बाद छात्र-छात्राओं ने वहां मौजूद लोगों को हाथ धोने से जुड़े 8 कदमों का नमूना पेश किया। इसमें हाथ साफ करने के लिए साबुन के इस्तेमाल से लेकर तौलिए से हाथ सुखाने जैसी चीजें भी शामिल थीं।

इसके बाद हाथ धोने के महत्व के बारे में बताया गया। इसका मकसद इस जगह पर मौजूद लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना था। कार्यक्रम के माध्यम से इस बात को रेखांकित किया गया कि खुले में शौच से मुक्त अभियान को टिकाऊ बनाने में छात्र-छात्राएं अहम हैं और स्वच्छता राष्ट्र निर्माण का अटूट हिस्सा है।

Scanned by CamScanner

द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है।

विश्वास के अधीन, प्रत्येक वीएचएसएनसी द्वारा जल स्वच्छता और स्वास्थ्य पर जागरूकता निर्माण और सामाजिक एकजुटता, कार्रवाई हेतु सामुदायिक चैंपियन्स तैयार करने और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बीच समन्वय का निर्माण करने के लिये एक मंच के सृजन पर फोकस के साथ अपने क्षेत्र में वर्ष भर का अभियान संचालित किया जाना है। अभियान, साथ में स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), 11 माह के अभियान दिवस के तौर पर संचालित किया जाना है, जो कि निम्नलिखित प्रत्येक चयनित विषयों पर केंद्रित होगा।

विश्वास अभियान मॉड्यूल मंत्रालय द्वारा अभियान के संचालन के लिये निर्देशक टिप्पणी के साथ तैयार किया और जुलाई 2017 में राज्यों के साथ साझा किया गया। प्रशिक्षकों का राष्ट्रीय प्रशिक्षण नई दिल्ली और गुवाहाटी में क्रमशः जून और सितंबर 2017 में संचालित किया गया। मॉड्यूल को ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया और अक्टूबर, 2017 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में पंचायती राज संस्थाओं के करीब 5000 निर्वाचित सदस्यों को वितरित किया गया। अनेक राज्यों जैसे कि छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, गोवा और महाराष्ट्र तथा चार उत्तर पूर्वी राज्यों, नामतः मेघालय, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम ने अपने जिला प्रशिक्षकों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किये तथा कुछेक ने खंड स्तर पर भी प्रशिक्षकों के लिये प्रशिक्षण का आयोजन किया। कुछ राज्यों जैसे कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा ने अभियान की शुरूआत के लिये वीएचएसएनसी सदस्यों के लिये प्रशिक्षण का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश ने पांच चयनित जिलों (वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ और कानपुर) में विश्वास अभियान की शुरूआत की है। इसने राज्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित कर लिया है और खण्ड प्रशिक्षकों तथा वीएचएसएनसी सदस्यों का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। राज्य गोरखपुर जिले में जापानी बुखार के उन्मूलन के लिये चलाये जा रहे समुदाय स्तर के अभियान के साथ विश्वास अभियान को संबद्ध किया है। जम्मू और कश्मीर ने विश्वास मॉड्यूल प्रशिक्षण को वीएचएसएनसी के साथ संबद्ध किया है। इसने जुलाई में तीन दिवसीय जिला प्रशिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जिनमें विश्वास अभियान पर सत्र शामिल थे।

स्वच्छता ही सेवा 2017 अभियान

भारत सरकार ने 15 सितंबर से 2 जुलाई 2017 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान संचालित किया। स्वास्थ्य सुविधाओं और समुदायों (ग्रामीण और शहरी) में स्वच्छता और साफ-सफाई संबंधी गतिविधियों के आयोजन के लिये सभी राज्यों में अभियान चलाये गये। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों की सहायता से 1.2 लाख से अधिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किये और स्वच्छता ही सेवा अभियान के संचालन में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में यह अग्रणी रहा। वर्ष 2018 के लिये स्वच्छता ही सेवा अभियान सभी राज्यों में वर्तमान में जारी है।

स्वच्छता पखवाड़ा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल के अंतर्गत हर वर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा और समुदाय स्तर पर स्वच्छता और साफ-सफाई के लिये अभियान चलाया जाता है। इस पहल के अधीन भारत सरकार का प्रत्येक मंत्रालय भारत सरकार के वार्षिक कैलेंडर में यथा निर्धारित अवधि के लिये स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित करता है

स्वच्छता पखवाड़ा

स्वच्छता पखवाड़ा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल के अंतर्गत हर वर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा और समुदाय स्तर पर स्वच्छता और साफ-सफाई के लिये अभियान चलाया जाता है। इस पहल के अधीन भारत सरकार का प्रत्येक मंत्रालय भारत सरकार के वार्षिक कैलेंडर में यथा निर्धारित अवधि के लिये स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित करता है। इस वर्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 1 से 15 अप्रैल, 2018 तक की अवधि आबंटित की गई और यह अभियान सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर संचालित किया गया।

निष्कर्ष

ऊपर किये गये उल्लेख के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित विविध गतिविधियों का स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर पर निर्णायक प्रभाव पड़ रहा है और इससे स्वच्छता और साफ-सफाई व्यवहार परिवर्तन के लक्ष्यों को मौजूदा कार्यक्रमों से कहीं अधिक हासिल करने के लिये समुदाय स्तर पर अनुकूल और सहयोगपूर्ण वातावरण भी बना है। कायाकल्प और स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र से न केवल सुविधाओं की स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ है बल्कि इन्होंने इन विषयों के बारे में सामुदायिक जागरूकता के केंद्र बनने में भी सुविधाओं की सहायता की है। वीएचएसएनसी और एमएएस तथा नये अभियान विश्वास की शुरूआत से सामुदायिक मंच स्वच्छता और साफ-सफाई के विषय में सामूहिक सामुदायिक प्रयासों के निर्माण और स्वास्थ्य परिणामों के साथ उनके संबंधों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और स्थाई व्यवहार परिवर्तन लाने में योगदान कर रहे हैं। स्वास्थ्य प्रणाली के अग्रणी पंक्ति के कार्यकर्ताओं की व्यापक पहुंच, उपलब्धता और भरोसे तथा वीएचएसएनसी और एमएएस के समुदाय आधारित संस्थान स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के निर्माण में सहायता कर रहे हैं, जिसके लिये हम सब काम कर रहे हैं। ❑

योजना
आगामी अंक
दिसंबर 2018
डिजिटल इंडिया

Scanned by CamScanner

महिलाओं व बच्चों के लिए साफ-सुथरा, आरोग्यमय वातावरण

राकेश श्रीवास्तव

"किसी समाज में स्वच्छता, स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे जैसे समाज में तो स्वच्छता एक साझा आध्यात्मिक प्रयास की तरह है और यह एक मूल अधिकार है।"

– महात्मा गांधी

महिलाएं समाज में व्यवहार संबंधी परिवर्तन लाने का सक्रिय माध्यम बन सकती हैं। वे बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाओं को संस्कृति, परम्परा और इतिहास की संवाहक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे ही बच्चों के व्यवहार और चरित्र का निर्माण करती हैं। बच्चों को जन्म देने के साथ ही उनमें संस्कृति के निर्माण की भी क्षमता होती है। इसलिए माताओं और बच्चों, दोनों ही को सुरक्षित और आरोग्यमय माहौल मिले यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय जोरदार प्रयास कर रहा है

गांधी जी के इस उद्धरण से पता चलता है कि बापू मानव जाति के अस्तित्व के लिए स्वच्छता की आवश्यकता पर कितना अधिक जोर देते थे। स्वच्छता की अवधारणा बड़ी विस्तृत है और इसमें मानव द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का कारगर प्रबंधन (उसे इकट्ठा करना, उपचार करना और निपटान करना/पुनर्प्राप्ति, फिर से इस्तेमाल और पुनर्चक्रण समेत) शामिल है। इसके अलावा ठोस अपशिष्ट (जिसमें सड़कर नष्ट होने वाले जैव-अपघटनशील और अपघटित न होने वाला कचरा, कूड़ा-करकट और मलबा समेत), अवजल, जलमल, औद्योगिक कचरे का निस्तारण और खतरनाक कचरे (जैसे अस्पतालों का कचरा, रासायनिक अपशिष्ट, रेडियोएक्टिव अपशिष्ट, प्लास्टिक व इसी तरह का अन्य कचरा शामिल है) का प्रबंधन भी शामिल है। किसी समाज में स्वच्छता के मानदंड उसमें आरोग्य और जन-स्वास्थ्य के स्तर के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। समाज में बीमारियों के प्रकोप, नागरिकों की औसत अनुमानित आयु संबंधी मानदंडों और इस तरह समाज के उत्पादकता के स्तर के साथ भी इनका सीधा संबंध है। स्वच्छता की कमी के न सिर्फ भारी आर्थिक दुष्परिणाम सामने आते हैं, बल्कि इसके गंभीर सामाजिक नतीजे भी भुगतने पड़ते हैं और इससे सामाजिक तथा आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर हमारा जीवन ठप्प पड़ सकता है। स्वच्छता की कमी के अंतर्गत पर्याप्त साफ-सफाई का न होना और कूड़ा-करकट तथा प्रदूषण फैलाना भी शामिल है।

महात्मा गांधी को अपने जीवन के शुरुआती दौर में ही तब के भारत में स्वच्छता और साफ-सफाई की खराब स्थिति का, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय सुविधाओं की भारी कमी अहसास हो गया था। उनका मानना था कि जिस तरह से स्वराज हासिल करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे, उसी तरह स्वच्छता की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता थी। इसीलिए देश की स्वतंत्रता के आंदोलन का नेतृत्व करने के साथ-साथ उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता, साफ-सफाई और हर तरह के कूड़े-कचरे के कारगर निपटान के लिए हमेशा सफाई के आंदोलन का भी नेतृत्व किया। उन्होंने स्वच्छता के लगभग तमाम पहलुओं, जैसे तकनीकी, सामाजिक और आर्थिक के साथ-साथ इसके अन्य पक्षों जैसे व्यक्तिगत, घरेलू और कार्पोरेट पर भी ध्यान दिया। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद स्वच्छता के विषय की ओर तत्कालीन सरकारों का ध्यान कभी-कभार ही गया[1]।

महात्मा गांधी के आदर्शों का अनुसरण करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2018 को राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य 2 अक्टूबर, 2019 यानि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक देश के हर नागरिक को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति, शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली और ग्रामीण स्वच्छता संबंधी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराना था।

जल, स्वच्छता और आरोग्य तीन ऐसे मूल मुद्दे हैं जिन्हें समेकित कर दिया गया है ताकि यह इस उभरते कार्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके। वैसे तो इनमें से प्रत्येक एक अलग क्षेत्र है मगर हर एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर निर्भर

लेखक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव हैं। ईमेल: secy.wcd@nic.in

Scanned by CamScanner

स्वच्छ भारत के तहत बालिकाओं के लिए भी गतिविधियां संचालित की गयीं। उन्हें साफ-सफाई के साथ खाना पकाने के तौर-तरीकों की जानकारी प्रदर्शन करके दी गयी। मंत्रालय ने देश भर में बच्चों की देखभाल करने वाले केन्द्रों के बच्चों में स्वास्थ्य और आरोग्य के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से चलाए जाने वाले राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों के आयोजन का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया है।

है। उदाहरण के लिए शौचालयों के न होने से जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं और बिना स्वच्छ जल के आरोग्य संबंधी बुनियादी गतिविधियां संभव नहीं है। बच्चों के विकास और उनकी दीर्घायु के लिए स्वच्छ जल, बुनियादी शौचालय सुविधाएं और आरोग्य संबंधी अच्छे तौर-तरीकों का होना बहुत जरूरी है। आज करीब 2.4 अरब लोग ऐसे हैं जो स्वच्छता संबंधी बेहतर साधनों का उपयोग नहीं करते और इसी तरह बेहतर जल स्रोत 66.3 करोड़ लोगों की पहुंच से बाहर हैं। इन बुनियादी सुविधाओं के बिना करोड़ों बच्चों का जीवन खतरे में है। पानी और स्वच्छता संबंधी बीमारियां पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे प्रमुख कारण है। रोजाना 800 से अधिक बच्चे खराब पानी तथा स्वच्छता व आरोग्य संबंधी कमियों के कारण ऐसी बीमारियों से मौत का शिकार हो जाते हैं जिनकी रोकथाम करना असंभव नहीं है। करीब 56.4 करोड़ लोग, यानी भारत की आबादी के करीब आधे के बराबर लोग, खुले में शौच करते हैं। दक्षिण एशिया में खुले में शौच करने वालों की कुल संख्या का 90 प्रतिशत भारत में है और पूरे विश्व में खुले में शौच करने वाले 1.1 अरब लोगों में से 59 प्रतिशत हमारे देश के लोग हैं।

महिला और बाल विकास मंत्रालय स्वच्छता आंदोलन को इसके उच्चतर स्तर पर ले जाने के प्रयास में लगा अग्रणी मंत्रालय रहा है। यह भारत सरकार के उन मंत्रालयों में से है जिन्होंने स्वच्छ भारत पहल के क्रियान्वयन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है। खुले में शौच की बुराई के उन्मूलन के लिए मंत्रालय राज्यों, जिलों और ग्राम स्तर पर अपनी टीमों के साथ कार्य कर रहा है। इसके तहत न सिर्फ घरेलू शौचालयों की समस्या के समाधान के प्रयास किये जाते हैं बल्कि स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनवाड़ियों, पंचायत भवनों, हाट-बाजारों में इनके निर्माण तथा ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाता है। देश ने जल्द-से-जल्द खुले में शौच की कुप्रवृत्ति से पूरी तरह मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया है और यह एक ऐसी चुनौती है जिसे बुनियादी ढांचे, व्यवहार परिवर्तन और व्यापक सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से निपटा जाना है।

देश के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वच्छता और आरोग्य का वातावरण बनाने के लिए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को आंगनवाड़ियों की सफाई, खेलकूद के मैदान की सफाई, अपनी सफाई (व्यक्तिगत स्वच्छता/बाल स्वास्थ्य), स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पेयजल, 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत स्वच्छ शौचालय और 'बाल स्वच्छता मिशन' जैसे विभिन्न विषयों पर 14 से 19 नवंबर, 2014 तक गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिये गये।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में साफ-सफाई और स्वच्छता तथा सुरक्षित स्वच्छ पेयजल को लेकर संचालित विभिन्न गतिविधियों के बारे में बाल स्वच्छता मिशन के तहत सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए एक पुस्तिका भी जारी की गयी।

2016 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायत राज मंत्रालय के साथ मिलकर मनरेगा के तहत आंगनवाड़ियों की 4 लाख इमारतों के निर्माण की दिशा में संयुक्त पहल की।

2016 में ही ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्रों की पहचान के लिए भी अभियान चलाया जहां शौचालयों और स्वच्छ पेयजल का इंतजाम करना जरूरी था। सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ियों और उनके आस-पास के क्षेत्र को स्वच्छ और आरोग्यमय बनाए रखने की जिम्मेदारी करीब 24 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायकों के अलावा 3.86 करोड़ महिलाएं और बालिकाएं भी निभा रही हैं।

महिला और बाल विकास विभाग ने 1 मार्च, 2017 से 15 मार्च, 2017 तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों में स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जागरूकता पैदा करना और 2019 तक भारत को खुले में शौच की कुप्रवृत्ति से मुक्त कर सर्वत्र स्वच्छता और आरोग्य के लक्ष्य को प्राप्त करना था। पखवाड़े के दौरान मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और उसके सहयोगी कार्यालयों तथा राज्य सरकारों के समकक्ष वरिष्ठ अधिकारियों ने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और मंत्रालय के क्षेत्रीय संगठनों का निरीक्षण किया। इन अधिकारियों ने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों और बाल विकास परियोजना अधिकारियों को साफ-सफाई के महत्व के बारे में बताया। मंत्रालय के अधिकारियों ने आंगनवाड़ी केन्द्रों, बच्चों की देखभाल करने वाली संस्थाओं, स्वाधार गृहों, कामकाजी महिलाओं के हॉस्टलों और वन स्टॉप सेंटरों जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में स्वच्छता संबंधी विभिन्न गतिविधियां संचालित कीं। स्थानीय समुदायों की मदद से बिना पैसा खर्च किये आंगनवाड़ी केन्द्रों की पुताई, उनकी दीवारों में सुंदर चित्र और प्रतीक चिह्न बनाने तथा केन्द्रों को साफ-सुथरा रखने के कार्यक्रम आयोजित किये गये। मंत्रालय ने दिव्यांगों के लिए शौचालयों सुविधाओं की समीक्षा की और स्वच्छ भारत मिशन के तहत उनके लिए बनाए गये शौचालयों का भी जायजा लिया। कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी कंपनियों के सामाजिक दायित्व के तहत निजी कंपनियों को स्वच्छता अभियान से जोड़ा गया। स्वच्छता

Scanned by CamScanner

विषय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं, जैसे बच्चों के लिए चित्र बनाने की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ताकि उनमें बचपन से ही साफ-सफाई और आरोग्य की आदत का विकास हो सके।

2017-18 के दौरान 70,000 आंगनवाड़ियों में शौचालयों का निर्माण किया गया और 20,000 में स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था की गयी। बच्चों की देखभाल करने वाली संस्थाओं में भी स्वच्छता के इंतजाम किये गये और शौचालयों की व्यवस्था की गयी। 2018-19 में 70,000 और शौचालय बनाये जा रहे हैं और 20,000 स्थानों पर स्वच्छ पेयजल का इंतजाम किया जा रहा है। मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2018 में देश में शौचालय की सुविधा वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या 9,29,339 तक पहुंच चुकी है।

स्वच्छ भारत के तहत बालिकाओं के लिए भी गतिविधियां संचालित की गयीं। इन्हें साफ-सफाई के साथ खाना पकाने के तौर-तरीकों की जानकारी प्रदर्शन करके दी गयी। मंत्रालय ने देश भर में बच्चों की देखभाल करने वाले केन्द्रों के बच्चों में स्वास्थ्य और आरोग्य के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से चलाए जाने वाले राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों के आयोजन का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया है।

मंत्रालय ने 15 सितंबर, 2018 से 2 अक्टूबर, 2018 तक 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान का आयोजन किया जिसमें उसी तरह की स्वच्छता गतिविधियों का संचालन किया गया जैसी स्वच्छता पखवाड़े में की जाती है। इसका उद्देश्य सरकारी संस्थाओं/संगठनों/मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में साफ-सफाई और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का संचालन करना था ताकि उनके माध्यम से स्वच्छता के संदेश को अधिक से अधिक महिलाओं और बच्चों तक पहुंचाया जा सके। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की देखभाल से जुड़ी संस्थाओं और आंगनवाड़ी केन्द्रों को गांव की गतिविधियों का केन्द्र माना जाता है। बच्चे और महिलाएं लगभग हर रोज इन केन्द्रों में पहुंचती हैं जिससे इन दिनों ये स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने और साफ-सफाई के संदेश को आम आदमी तक संप्रेषित करने वाले केन्द्र बन गये हैं। एक अरसे से ग्रामीण महिलाएं मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता की कमी से होने वाली समस्याओं से जूझती आ रही हैं। अब इनके माध्यम से मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बरतने का संदेश फैलाने और मासिक धर्म के दौरान काम आने वाले उत्पादों के वितरण का कार्य किया जा रहा है। स्वच्छता संबंधी सही तौर-तरीके न अपनाने से महिलाएं मासिक धर्म संबंधी बीमारियों से पीड़ित रहती हैं। इसका असर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। मंत्रालय ने मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता के बारे में महिलाओं को संदेश देने लिए अलग जागरूकता अभियान चलाया है। 2018 में 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्रों और समन्वित बाल विकास सेवा कार्यकर्ताओं को ग्राम स्तर पर श्रमदान के कार्य में लगाया गया। मंत्रालय ने 'स्वच्छता हम सब की जिम्मेदारी' की अवधारणा को और सुदृढ़ करने के प्रयास किये हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक स्वच्छता गतिविधियों में भागीदार बने यह सुनिश्चित करने के लिए साफ-सफाई के अभियानों में श्रमदान को प्रोत्साहित किया जाता है। श्रमदान कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया एक अभिनव प्रयास है जिसमें माननीय मंत्री जी से लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तक साफ-सफाई की गतिविधियों में हिस्सेदारी निभाते हैं और अपने घर तथा आस-पड़ोस एवं कार्यालयों में स्वच्छता रखते हैं। मंत्रालय के अधिकारी कार्यकर्ताओं और आम जनता को श्रमदान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

बच्चों को स्वच्छता का संदेश देने के लिए कठपुतली शो, दीवार चित्रकारी और नुक्कड़ नाटक जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इससे उनका मनोरंजन भी होता है और अभियान के मुख्य विषय में उनकी रुचि पैदा होने से वे इसे आसानी से ग्रहण कर पाते हैं।

खुले में शौच की कुप्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए जनमत तैयार करने वाले प्रभावशाली लोगों, जैसे सरकारी कर्मचारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत राज संस्थाओं के लोगों, मीडिया आदि को एकजुट हो जाना चाहिए क्योंकि वे देश के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्पूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देश, राज्य और लोगों के स्तर पर स्वच्छता की चुनौती से निपटने में जो एक ताकत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है वह है आंगनवाड़ी केन्द्र। केन्द्र सरकार राज्यों और जिला टीमों के साथ मिलकर खुले में शौच की कुप्रथा के उन्मूलन की योजना पर कार्य कर रही है। इसके लिए किराये की इमारतों में चल रहे ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्रों को जिनमें शौचालय की सुविधा नहीं है, उन्हें पास के स्कूलों में चलाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वच्छ शौचालय उपलब्ध हो जाएंगे। सरकार ने साफ-सफाई और आरोग्य संबंधी गतिविधियों को महिलाओं और बच्चों के सामने प्रदर्शित करने के लिए जोरदार पहल की है। इसके लिए पोषण माह, 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान और स्वच्छता पखवाड़े जैसे कार्यक्रमों के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकों का सहारा लेकर हाथों को साफ रखने के तौर-तरीकों का प्रदर्शन किया जाता है।

स्वच्छता विषय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं, जैसे बच्चों के लिए चित्र बनाने की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ताकि उनमें बचपन से ही साफ-सफाई और आरोग्य की आदत का विकास हो सके।

Scanned by CamScanner

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की देखभाल से जुड़ी संस्थाओं और आंगनवाड़ी केन्द्रों को गांव की गतिविधियों का केन्द्र माना जाता है। बच्चे और महिलाएं लगभग हर रोज इन केन्द्रों में पहुंचते हैं जिससे इन दिनों ये स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने और साफ-सफाई के संदेश को आम आदमी तक संप्रेषित करने वाले केन्द्र बन गये हैं।

गरीबी और कुपोषण से शिशुओं और बच्चों के पेचिश तथा न्यूमोनिया जैसी कई संक्रामक बीमारियों की चपेट में आने का खतरा और भी बढ़ जाता है। इससे उनकी मृत्यु की आशंका भी बढ़ जाती है, खास तौर पर जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों को तो यह खतरा और भी अधिक होता है। जनसांख्यिकीय और महामारी विज्ञान संबंधी आंकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि परिवार की खराब आर्थिक स्थिति, महिलाओं में शिक्षा की कमी, माताओं के पोषण के खराब स्तर, बाल विवाह, परिवारों के बड़ा आकार, महिलाओं को अपनी पहल पर निर्णय लेने की आजादी न होने और स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधाओं तक पर्याप्त पहुंच न होने जैसे कारणों से माताओं और उनके बच्चों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे असामान्य रूप से बढ़ जाते हैं। अध्ययनों से माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य में कई सामाजिक-आर्थिक और अंतर-राज्यीय अंतर भी देखे हैं। यह बात व्यापक तौर पर मानी जाती है कि भारत में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की डायरिया से मौत की दर सबसे अधिक होने का मुख्य कारण खुले में शौच की कुप्रवृत्ति ही है। बार-बार पेचिश होने से बच्चों का शरीर कमजोर हो जाता है और उनके कुपोषण, शारीरिक वृद्धि रुक जाने और न्यूमोनिया की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, भारत के ग्रामीण इलाकों के उपेक्षित वर्गों के बच्चों में कुपोषण की समस्या बड़ी आम है। बच्चों में अल्प-पोषण की इस समस्या से निपटने और इसे कम करने के लिए सरकार ने पोषण संबंधी संसाधन जुटाने और उन्हें समेकित करके पोषण अभियान प्रारंभ किया है। मंत्रालय देश में माताओं और बच्चों में पोषण के स्तर में सुधार के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय होकर प्रयास कर रहा है। मंत्रालय ने बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाने, अल्प पोषण, एनीमिया और शिशु के जन्म के समय कम वजन जैसी समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए हैं। विभिन्न स्तरों पर किये जा रहे प्रयासों में समन्वय करने, निगरानी के कार्य में सुधार, आवश्यक कदम उठाने के लिए समय पर चेतावनी जारी करने जैसे कार्यों में तालमेल कायम किया जा रहा है और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं, ए.एन.एम. और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार के महत्व के बारे में जानकारी का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

माननीय प्रधानमंत्री और पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय के निर्देश पर महिला और बाल विकास मंत्रालय ने स्वच्छता को अपने कार्यक्षेत्र के दायरे में ले लिया है और बड़े जोरदार तरीके से इस पर कार्य किया जा रहा है। स्वच्छता का सीधा असर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर, खास तौर पर जच्चा-बच्चा की मृत्यु दर पड़ता है। इस तरह मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों को स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण के बारे में जागरूक बनाकर लोगों को स्वच्छता और आरोग्य के प्रति संवेदनशील बनाया है।

महिलाएं समाज में व्यवहार संबंधी परिवर्तन लाने का सक्रिय माध्यम बन सकती हैं। वे बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाओं को संस्कृति, परम्परा और इतिहास की संवाहक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे ही बच्चों के व्यवहार और चरित्र का निर्माण करती हैं। बच्चों को जन्म देने के साथ ही उनमें संस्कृति के निर्माण की भी क्षमता होती है। इसलिए माताओं और बच्चों, दोनों ही को सुरक्षित और आरोग्यमय माहौल मिले यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय जोरदार प्रयास कर रहा है।

भारत अनोखी सांस्कृतिक विविधता वाला देश है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं के लोग शांति और सद्भाव के साथ मिलकर रहते हैं। भारतीय समाज के हर हिस्से में पायी जाने वाली हर संस्कृति के साथ अनेक मिथक और किंवदंतियां जुड़ी रहती हैं। अधिकतर वर्जनाएं या तो महिलाओं के लिए हैं या उनके विरुद्ध जाती हैं। इस तरह महिलाएं और उनके साथ ही बालिकाएं इनका शिकार बनती हैं। यही वजह है कि भारत में नीति संबंधी किसी उपाय को सही अर्थों में लागू करना सचमुच एक चुनौती है। देश की विशाल जनसंख्या और विविधतापूर्ण संस्कृति तथा सोच की वजह से मंत्रालय के लिए हर व्यक्ति और उसके मन-मस्तिष्क तक पहुंचना अपने आप में चुनौती के समान है। मंत्रालय अपनी राज्य और जिला टीमों के साथ मिलकर बड़े यत्नपूर्वक शिशु और बालिका मृत्यु दर में कमी लाने और उन्हें स्वास्थ्यवर्धक, सुरक्षित और निरापद माहौल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास कर रहा है। ❑

संदर्भ

1. डॉ. वाई.पी. आनंद, क्रोनोलॉजिकल, सेनिटेशन : गांधियन मूवमेंट एंड स्वच्छ भारत अभियान, बॉम्बे सर्वोदय मंडल और गांधी रिसर्च फाउंडेशन।

Scanned by CamScanner

स्वच्छता क्रांति : शहरी भारत की सफाई

दुर्गा शंकर मिश्र

जहां तक स्वच्छता का सवाल है शहरी स्वच्छता मिशन खुले में शौच से मुक्त के लक्ष्यों की प्राप्ति की सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि शहरी स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने में क्रांतिकारी बदलाव के रूप में हुई है। अब बनाए गये शौचालयों की संख्या गिनने की बजाय इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि किस तरह शहरों और कस्बों को स्थायी रूप से खुले में शौच से मुक्त बनाए रखा जाए

'स्वच्छ भारत अभियान' पर अमल की दिशा में सरकार की पहल की सबसे बड़ी विशेषता वह बहुआयामी दृष्टिकोण है जिसके तहत नीतिगत और विनियामक परिवर्तन किये जा रहे हैं, चिरस्थायी अवसंरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर जनता को स्वच्छता कार्यक्रमों से जोड़कर लोगों में व्यवहार और दृष्टिकोण संबंधी बदलाव लाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

स्वच्छता की कमी की कीमत

सतत विकास लक्ष्यों में स्वच्छता, साफ-सफाई और आरोग्य पर काफी जोर दिया गया है। विश्व भर में इस बात के पक्के प्रमाण मिले हैं कि बेहतर स्वच्छता, आरोग्य के उपायों और साफ-सफाई रखने से रोगवाहकों से होने वाली बीमारियों, परजीवियों से फैलने वाले संक्रमण और पोषाहार संबंधी कमियों को दूर करने में मदद मिलती है। अध्ययनों में पाया गया है कि स्वच्छता और आरोग्य संबंधी नियमों का पालन करने से सांस के रोगों, पेट की बीमारियों (खास तौर पर डायरिया), मनोवैज्ञानिक समस्याओं और एलर्जी आदि की रोकथाम में मदद मिलती है। यूनिसेफ की रिपोर्ट (2011) के अनुसार डायरिया से होने वाली बच्चों की लगभग 90 प्रतिशत मौतों का सीधा संबंध प्रदूषित जल, स्वच्छता की कमी या आरोग्य के नियमों का पूरी तरह पालन न किया जाना है। स्वच्छता, आरोग्य के नियमों और कूड़े-कचरे के निपटान की बेहतर व्यवस्था होने से गर्भवती महिलाओं में अचानक गर्भपात, प्रसव के समय शिशुओं के वजन के कम होने की समस्या और जन्मजात शारीरिक विकृतियों में कमी लायी जा सकती है। विभिन्न अध्ययनों से यह बात भी साबित हो गयी है कि जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर और शहरी इलाकों में जनसंख्या का दबाव बढ़ने से ठोस कचरे के निपटान की समस्या और भी जटिल हो जाती है। ऐसा ठोस कचरा जिसका निपटान नहीं हो पाता, खास तौर पर मल-मूत्र और घरों से निकलने वाला तरल व ठोस कचरा स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है और इनसे संक्रामक बीमारियां भी फैलती हैं। बिखरा हुआ कूड़ा-कचरा मक्खियों, चूहों और दूसरे जीवों को आकृष्ट करता है जो संक्रमित होकर बीमारियां फैलाते हैं।

अध्ययनों से यह भी सिद्ध हो गया है कि स्वच्छता और आरोग्य में सुधार से स्वास्थ्य संबंधी बेहतर नतीजे सामने आते हैं। 'इंडिया हैल्थ रिपोर्ट फॉर न्यूट्रीशन सिक्योरिटी इन इंडिया' (पीएचएफआई, 2015) के अनुसार 2006 से 2014 के बीच पूर्वोत्तर के मिजोरम राज्य में स्वच्छता सुविधाओं तक लोगों में पहुंच बढ़ने से बच्चों की शारीरिक बढ़ोतरी रुक जाने के मामलों में 13 प्रतिशत-अंकों की और कम वजन व कद वाले बच्चों के मामलों में 5 प्रतिशत-अंकों की कमी दर्ज की गयी। स्वच्छता में सुधार से न केवल स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ते देखा गया है बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है और यह बात विकासशील देशों में खास तौर पर देखी गयी है। उदाहरण के लिए यूनिसेफ द्वारा भारत में अगस्त 2017 में कराये गये एक स्वतंत्र अध्ययन से यह साबित हो गया है कि अगर देश को खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्ति मिल जाए तो प्रत्येक परिवार को सालाना 50,000 रुपये की बचत हो सकती है।

स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ

कई दशक पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता के मुकाबले स्वच्छता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस विकराल स्वास्थ्य समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत भारत के

लेखक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव हैं। ईमेल: secyurban@nic.in

Scanned by CamScanner

लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। इसने स्वच्छता के मुद्दे को सरकार के विकास के एजेंडा के केन्द्र में ला दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक जबरदस्त संदेश भी दिया **"न गंदगी करेंगे, न करने देंगे"** और ऐसा करके उन्होंने देश के हर नागरिक को स्वच्छता की यात्रा में बराबरी का भागीदार भी बना दिया। आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (चित्र-1) का उद्देश्य 2 अक्टूबर, 2019 तक देश के सभी कस्बों और शहरों को कूड़े-करकट और खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त कराना है और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर यह बापू को देश की सबसे श्रेष्ठ श्रद्धांजलि होगी।

अब तक का सफर

स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत से अब तक का सफर बड़ा शानदार रहा है। हालांकि इसमें उतार-चढ़ावों की भी कमी नहीं रही है। इसमें अनेक चुनौतियां आई हैं और कई सुखद सफलताएं भी मिली हैं। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के पहले दो वर्षों में सरकार का जोर ऐसा अनुकूल माहौल बनाने पर रहा है जिसमें मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ये लक्ष्य हैं : सभी कस्बों को खुले में शौच से मुक्त करना और नगरपालिकाओं के ठोस कचरे का शत प्रतिशत वैज्ञानिक प्रबंधन। यह कार्य जहां एक ओर कचरे से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए उपयुक्त नीतिगत बदलावों के जरिए किया गया वहीं दूसरी ओर स्वच्छता कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर जनता की भागीदारी के लिए अनुकूल माहौल भी बनाया गया। इन सब प्रयासों के आशाजनक परिणाम सामने आये हैं (देखिए चित्र 2)। ये परिणाम जमीनी हकीकत के रूप में साफ दिखाई देने लगे हैं जिससे स्वच्छता मिशन की रफ्तार को तेज करने में मदद मिली है। अब जबकि स्वच्छता मिशन का आखिरी वर्ष पूरा होने को है तो हम संतोष के साथ पीछे मुड़ कर देख सकते हैं और अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर सकते हैं। इन उपलब्धियों ने भारत को न्यू इंडिया की दिशा में जबरदस्त बदलाव के चौराहे पर ला खड़ा किया है।

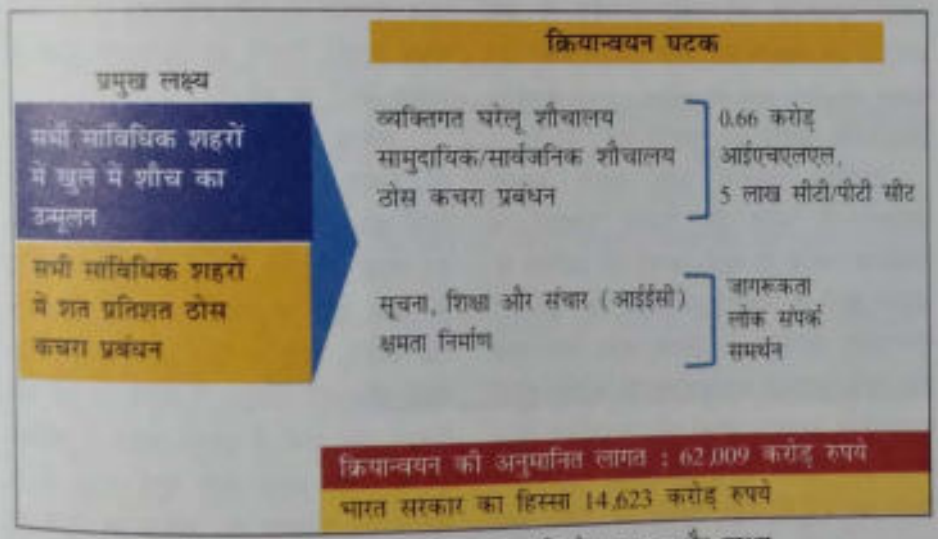

चित्र 1 : स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के घटक और लक्ष्य

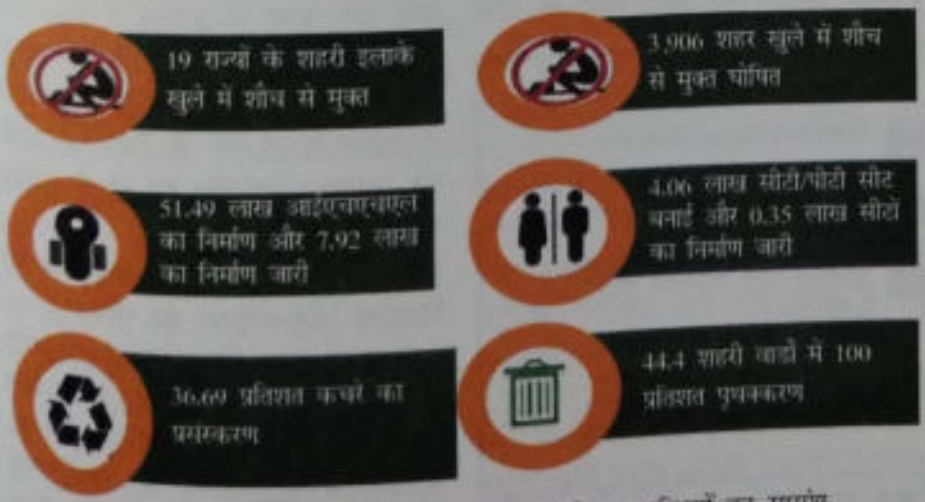

चित्र 2 : स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत उपलब्धियों का सारांश

स्वच्छता : खुले में शौच से मुक्त की यात्रा

जहां तक स्वच्छता का सवाल है शहरी स्वच्छता मिशन खुले में शौच से मुक्त के लक्ष्यों की प्राप्ति की सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि शहरी स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने में क्रांतिकारी बदलाव के रूप में हुई है। अब बनाए गये शौचालयों की संख्या गिनने की बजाय इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि किस तरह शहरों और कस्बों को स्थायी रूप से खुले में शौच से मुक्त बनाए रखा जाए। जब यह अभियान शुरू किया गया था तब भारत का कोई भी शहर या कस्बा खुले में शौच की बुराई से मुक्त नहीं था। हमने महसूस किया है कि शहरों की स्वच्छता की तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए सिर्फ खुले में शौच से मुक्त हो जाना काफी नहीं है। उदाहरण के लिए घर में जगह की कमी की समस्या से जूझ रहा परिवार या झुग्गी-झोंपड़ी बस्ती के रहने वाले, बाहर से किसी शहर में आने वाले या अस्थायी रूप से आने-जाने वालों की शौच संबंधी जरूरतें किस तरह पूरी होंगी। उन्हें शहर में साफ-सुथरा, इस्तेमाल किया जा सकने वाला शौचालय चालू हालत में किस तरह मिल पाएगा। इसलिए हमने सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के संचालन और रखरखाव के लिए स्वच्छ भारत मिशन ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस मानकों की शुरुआत की है। इसके अलावा सर्वांगीण स्वच्छता के मुद्दे पर भी ध्यान दिया जा रहा है जिसमें जल-मल का प्रबंधन भी शामिल है। इससे ओडीएफ के जिन मानकों को प्राप्त किया जा चुका है उन्हें चिरस्थायी बनाया जा सकेगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने गूगल के साथ सहयोग से शहरों के सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों को गूगल मैप्स पर प्रदर्शित करने का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है (देखिये चित्र-3) जिसकी मदद से नागरिक और आगंतुक अपने आस-पास के शौचालयों की जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब तक देश के

Scanned by CamScanner

चित्र 3 : गूगल मैप्स पर सार्वजनिक शौचालय (स्वच्छ भारत मिशन शौचालय)

550 शहरों/कस्बों में यह सुविधा उपलब्ध है जिनमें से 179 शहर/कस्बे 1,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन – बहुआयामी दृष्टिकोण

यह बात स्वीकार करनी ही होगी कि जहां भारत ओडीएफ के लक्ष्य को हासिल करने के बहुत करीब पहुंचाया है, वहीं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या से निपटना और भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। भारत में शहरी इलाकों में रहने वाले करीब 40 करोड़ लोग हर साल करीब 6.5 करोड़ टन ठोस शहरी कचरा उत्पन्न करते हैं। (देखिए चित्र 4)। अनुमान है कि 2030 तक सालाना 16.5 करोड़ टन और 2050 तक 45 करोड़ टन शहरी ठोस कचरा पैदा होने लगेगा जिससे जनस्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी चुनौतियां भी उसी अनुपात में बढ़ जाएंगी। इस अप्रसंस्कृत ठोस शहरी कचरे को फेंकने के लिए हमें हर साल 1,250 हैक्टेयर बेशकीमती जमीन को गंवाना पड़ रहा है।

इसलिए आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने भारत के शहरी इलाकों में वैज्ञानिक तरीके से कूड़े-कचरे के प्रबंधन के जटिल मुद्दे से निपटने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इसके तहत जहां एक ओर कूड़े-करकट का प्रसंस्करण करके उससे मूल्यवर्धित उत्पादन बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों और विनियमों में बदलाव किये जा रहे हैं वहीं मिशन के तहत कुछ नयी पहल भी की गयी हैं। उदाहरण के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण के जरिए शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा रहा है कूड़े-करकट से मुक्त शहरों को 'स्टार रेटिंग' देकर उनकी स्थिति को चिरस्थायी बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के समय विभिन्न प्रक्रियाओं के जरिए कूड़े-कचरे के प्रसंस्करण की वार्षिक क्षमता 95 लाख टन की थी। इसमें कूड़े-कचरे से कम्पोस्ट खाद बनाना, जैव कचरे से मीथेन गैस बनाना, कूड़े से ईंधन और बिजली बनाने जैसी प्रक्रियाएं उपयोग में लायी जा रही थीं। पिछले चार वर्षों में इसकी क्षमता में बढ़ोतरी हुई है और आज कुल कूड़े-कचरे में से करीब 37 प्रतिशत का प्रसंस्करण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़, केरल और गोवा जैसे राज्य ठोस कचरे के प्रबंधन में अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। इसी तरह इंदौर, नवी मुंबई, अलीगढ़, ससवाड और बेंगलुरु ठोस कचरे के प्रबंधन के नये-नये और चिरस्थायी उपायों को अपनाकर मार्गदर्शन कर रहे हैं (देखिए बॉक्स 1)।

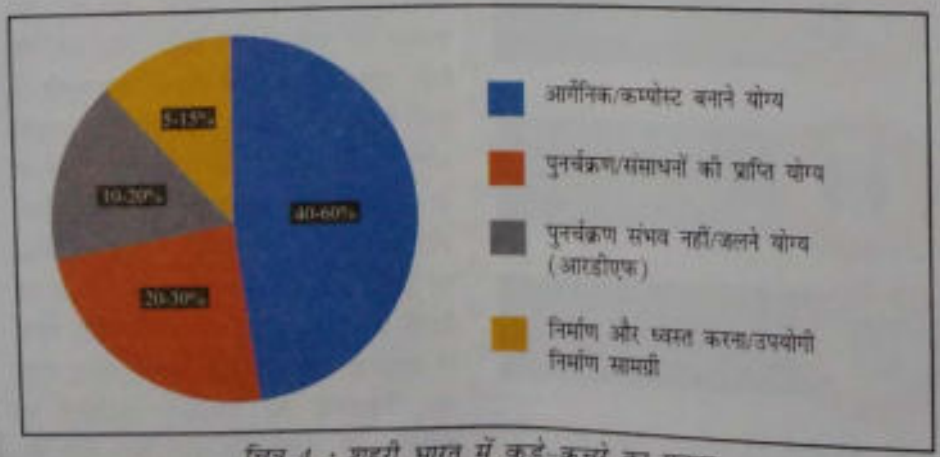

चित्र 4 : शहरी भारत में कूड़े-कचरे का प्रकार

स्वच्छ सर्वेक्षण : स्वच्छता अभियान की निगरानी और प्रशासन का साधन

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय स्वच्छ सर्वेक्षण कराता है (देखिए चित्र 5) । इसके अंतर्गत स्वच्छता और साफ-सफाई के विभिन्न मानकों के आधार पर शहरों का

Scanned by CamScanner

बॉक्स 1 : राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से यश गाथाएं

छत्तीसगढ़ के शहरों में जीरो वेस्ट यानी कोई भी अपशिष्ट न छोड़ने वाला मॉडल अपनाने से यह राज्य शून्य लैंडफिल वाला राज्य बनने की राह पर है। राज्य में अंबिकापुर में कूड़ा-करकट डालने के लिए कोई जगह निर्धारित नहीं की गयी है। यहां कूड़े-करकट में से 90 प्रतिशत को छांट लिया जाता है और ठोस-द्रव अपशिष्ट प्रबंधन विधि का उपयोग करते हुए हर महीने 13 लाख रुपये की आमदनी होती है।

केरल विकेन्द्रित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अपनाने से इस क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। राज्य के लगभग सभी शहरों में घरेलू स्तर पर पाइप के जरिए काम करने वाली कम्पोस्ट या बायोगैस प्रणाली स्थापित कर दी गयी है। असल में केरल में अलप्पुझा दुनिया के चोटी के उन पांच शहरों में शामिल है जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ठोस कचरे की समस्या के समाधान के प्रयासों में लगा है।

- गोवा ने साबित कर दिया है कि किस तरह स्रोत पर ही कूड़े की पांच हिस्सों में छंटाई कर देने से कूड़ा-कचरा संपत्ति में बदल जाता है। यहां के बारे में दावा किया जाता है कि यहां घर-घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करने का कार्य शत-प्रतिशत पूरा किया जाता है। ज्यादातर आवासीय सोसाइटियों में कम्पोस्ट खाद बनाने वाली इकाइयां और किचन गार्डन बने हुए हैं जिनमें कम्पोस्ट के उत्पादों का उपयोग होता है।
- गंगटोक में कूड़े को शत-प्रतिशत स्रोत पर ही अलग करने के बाद उसका प्रसंस्करण किया जाता है।
- मध्य प्रदेश में इन्दौर, भोपाल और जबलपुर में भी कूड़े की शत-प्रतिशत छंटाई स्रोत पर ही कर दी जाती है।
- नवी मुंबई भी अपने 88 प्रतिशत ठोस कचरे की स्रोत पर ही छंटाई कर लेता है।
- बैंगलुरु में एक नये तरह का ऑनलाइन पोर्टल है जो बड़े पैमाने पर कूड़ा पैदा करने वालों को ठोस कचरे के निपटान के तौर-तरीकों के बारे में बताता है।
- नागपुर में नयी तरह की एक घड़ी बनायी गयी है जो शहरी स्थानीय निकायों को स्वच्छता कर्मचारियों के काम के घंटों के दौरान उनकी उपस्थिति पर जीओ-टैगिंग के जरिए नजर रखती है।
- अलीगढ़ में सूखे कूड़े से 'जादुई ईंट' की शुरुआत की गयी है, जिनका उपयोग निर्माण कार्यों में किया जा सकता है।
- महाराष्ट्र में ससवाड में अलग-अलग तरह के कूड़े को छांट कर अलग नहीं रखने वालों, कभी-कभी ऐसा करने वालों और हमेशा ऐसा करने वाले घरों की पहचान के लिए क्रमशः लाल, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल किया जाता है।
- झारखंड में खुले में शौच करने वालों और ऐसा न करने वालों की पहचान के लिए रंगों का उपयोग किया जाता है। जो घर खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं उन्हें हरा, घर पर शौचालय के बावजूद कभी-कभार खुले में शौच करने वालों के लिए पीला और नियमित रूप से खुले में ही शौच करने वालों के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है।

वार्षिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें रैंक या दर्जा दिया जाता है। इस सर्वेक्षण से शहरों के बीच स्वच्छता को अवधारणा को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हुई है। इसके अलावा सर्वेक्षण अभियान पर कारगर निगरानी रखने और उसका विनियमन करने वाला औजार भी साबित हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण के पहले दौर में 2016 में भारत के 10 लाख से अधिक आबादी वाले 73 शहरों और राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में सर्वेक्षण कराया गया। 2017 में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 434 शहरों में यह सर्वेक्षण कराया गया। 2018 के सर्वेक्षण में 4,302 शहरी स्थानीय निकाय शामिल किये गये। यह करीब 40 करोड़ जनता पर असर डालने वाला पहला अखिल भारतीय स्वच्छता सर्वेक्षण था जो संभवतः दुनिया में अपनी तरह का इतना बड़ा पहला सर्वेक्षण रहा होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण-2019 जिसमें नवाचार, स्वच्छता को चिरस्थायी बनाने, नागरिकों की भागीदारी और कूड़ा-करकट मुक्त दर्जे पर ध्यान केन्द्रित किया जाना है, अगले वर्ष जनवरी में देश के सभी कस्बों और शहरों में आयोजित किया जाएगा.

कूड़ा-करकट मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग

मंत्रालय ने एक और पहल की है जिसके अंतर्गत शहरों के कूड़ा-करकट मुक्त होने के दर्जे का आकलन किया जाएगा और इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को 'गार्बेज फ्री सिटी स्टार' का दर्जा दिया जाएगा। बारह मानदंडों पर आधारित इस स्मार्ट (सिंगल मीट्रिक-एकल पैमाने पर आधारित, मेजरेबल-मापनीय, अचीवेबल-प्राप्य, रिगरस-कठोर और टारगेटेड-लक्षित) मूल्यांकन प्रणाली में समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तमाम पहलुओं जैसे सार्वजनिक स्वच्छता, घर-घर जाकर कूड़ा एकत्र करने, स्रोत पर ही अलग-अलग किस्म के कूड़े को अलग करने, प्रसंस्करण, नालों तथा जलाशयों की सफाई, प्लास्टिक के कचरे का प्रबंधन और निर्माण व तोड़-फोड़ से उत्पन्न मलबे के निस्तारण का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। शहरों को कूड़े-करकट से मुक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व हैं। असल में स्टार रेटिंग के मानदंडों पर अगर समुचित तरीके से अमल किया जाए तो इससे स्वच्छता के क्षेत्र में पासा पलट सकता है और भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तौर-तरीकों में क्रांति आ सकती है। दरअसल, जब बड़ी संख्या में शहरों को 'स्टार' का दर्जा मिल जाएगा और स्वच्छता के बारे में 'जनता' की आकांक्षाएं बढ़ेंगी तो इससे देश के प्रशासनिक और राजनीतिक ताने-बाने में भी बदलाव आएगा। ऐसा होने पर किसी शहर को मिले 'स्टार' की संख्या के आधार पर ही यह आकलन किया जाएगा कि उस शहर का प्रशासन और वहां के निर्वाचित प्रतिनिधि स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने में कितने कारगर रहे हैं।

जनांदोलन की दिशा में प्रगति

मिशन ने जिस तरह से समूची जनता-बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है वह वह इसकी

Scanned by CamScanner

सबसे शानदार उपलब्धि कहा जा सकता है। पिछले चार वर्षों में बुनियादी ढांचे और विनियामक परिवर्तनों के साथ-साथ एक समानांतर सामाजिक आंदोलन जनता में लगातार जोर पकड़ रहा है। 2 अक्टूबर, 2017 को प्रधानमंत्री ने कहा, ".....अगर एक हजार महात्मा गांधी आ जाएं, एक लाख नरेन्द्र मोदी आ जाएं तो भी स्वच्छता का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन अगर सवा सौ करोड़ देशवासी आ जाएं तो देखते ही देखते सपना पूरा हो जाएगा।

स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ करते समय प्रधानमंत्री ने नौ जानी-मानी हस्तियों को 'स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेस्डर' नामजद किया था ताकि वे स्वच्छता की दिशा में अपने प्रयासों से आम नागरिकों के लिए रोल मॉडल का कार्य करें। आज हमारे पास इस तरह के 150 से अधिक ब्रांड एम्बेस्डर हैं जो स्वच्छता की दिशा में हमारी सामूहिक यात्रा में देशवासियों को सरकार का हाथ बंटाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

नागरिकों की भागीदारी से खास विषयों पर चलाए जाने वाले अभियानों, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन के माध्यम के रूप में विद्यार्थियों और स्वयं-सहायता समूहों को अभियान से जोड़ने, स्वच्छता संबंधी विभिन्न बदलाव लाने के लिए देश भर में स्वच्छाग्रहियों को जिम्मेदारी सौंपने, 'स्वच्छता' के संदेश वाले मल्टी-मीडिया प्रचार अभियानों के आयोजन, देश में ठोस कचरे के प्रबंधन के बेहतरीन तरीकों के बारे में रेडियो पर 'स्वच्छता सेल्फी' धारावाहिकों और स्वच्छता अभियान में नागरिकों की व्यापक भागीदारी और उन्हें इससे जोड़े रखने के लिए सूचना और संचार टेक्नोलाजी तथा मोबाइल एप जैसे साधनों के उपयोग से जनता में स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ी है। लोग अब यह महसूस करने लगे हैं कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति अपने आस-पास की सफाई के लिए समान रूप से उत्तरदायी है (देखिए बॉक्स 2)। स्वच्छता के जनांदोलन बनने की भावना का सबसे अच्छा प्रदर्शन इस साल गांधी जयंती के सिलसिले में (2 अक्टूबर) देश भर में आयोजित कार्यक्रमों और उनमें नागरिकों की भागीदारी में देखा जा सकता है। इनमें करीब 40 लाख लोगों ने हिस्सा लिया जिनमें स्कूलों के बच्चे, विद्यार्थी, गृहणियां, रेजीडेंट वैलफेयर एसोसिशन, धार्मिक नेता, कंपनियां, स्थानीय व्यापारी और गण्यमान्य लोग शामिल हुए। 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़े के दौरान शहरी भारत के कस्बों और नगरों में करीब 25,000 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

नागरिकों की भागीदारी की कुछ प्रेरक गाथाएं

- चलापल्ली जिले के एक डाक्टर दंपति साल भर रोजाना स्वच्छता अभियान चला रहे हैं।
- कर्नाटक में रामकृष्ण मिशन के संन्यासी अपने आस-पास के इलाकों को स्वच्छ रखने के लिए नागरिक स्वयंसेवकों के साथ मिलकर नियमित स्वच्छता अभियान चलाते हैं।
- स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विंग कमांडर परमवीर सिंह ने तीन तैराकों और नाविकों के साथ 'गंगा आह्वान' का आयोजन किया और देवप्रयाग (उत्तराखंड) से गंगासागर (प.बंगाल) तक गंगानदी में 2800 कि.मी. की दूरी तैर कर पार की।
- महाराष्ट्र की तीन उद्यमी महिलाओं ने - नाशिक जिले के सिन्नार की सुवर्णा लोखंडे, वाशिम जिले में साईखेडा की संगीता अहवाले और यवतमाल जिले में मोज़र की चैताली राठौर ने अपने और अपने परिवार के सम्मान के लिए शौचालय बनाने में पहल की।
- सुवर्णा ने शौचालय के निर्माण के लिए स्वयं सहायता समूह 'बचत घर' से कर्ज लिया, संगीता ने इसके लिए अपना मंगलसूत्र बेच दिया और चैताली ने शादी में अपने माता-पिता से और कोई उपहार लेने की बजाय ससुराल में शौचालय बनाने की मांग की।
- दुर्ग में सभी उम्र के लोगों का एक संगठन **कोशिश** अपने आस-पास के सभी पार्कों की रोजाना सुबह को सफाई करता है ताकि वरिष्ठ नागरिक उनका उपयोग कर सकें.
- संत निरंकारी मंडल सड़कों, गलियों, पार्कों, धरोहर स्थलों, तालाबों और रेलवे स्टेशनों की सफाई के लिए नियमित रूप से अभियान चलाता है।
- आगरा का एक संगठन इंडिया राइजिंग शहर में कई स्थानों पर नागरिक स्वयंसेवकों के साथ साप्ताहिक स्वच्छता अभियान चलाता है।

Scanned by CamScanner

स्वच्छ भारत अभियान के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव : कुछ उदाहरण

इंदौर नगर निगम द्वारा हाल में कराए गये एक सर्वेक्षण (जागरण 2017) से पता चला कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत साफ-सफाई के लिए उठाए गए कदमों से परजीवियों से पैदा होने वाली बीमारियों में 70 प्रतिशत की कमी आयी। इंदौर में जून से अगस्त, 2017 के दौरान पीलिया, डायरिया, हैपेटाइटिस और मलेरिया के रोगियों की संख्या घटकर 35,000 रह गयी जबकि इससे पहले साल इसी अवधि में यह संख्या 1,00,000 रही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि इस अवधि में इंदौर में दवाओं की बिक्री में 20 करोड़ रुपये की कमी आयी जिससे शहर में चिकित्सा संबंधी लागत को कम करने में मदद मिली। छत्तीसगढ़ में भी प्रदूषण का प्रकोप काफी कम हो गया और पिछले दो साल में डायरिया, टायफाइड जैसी बीमारियों के मामले बहुत कम हो गये हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के अच्छे परिणाम व्यापक रूप से सामने आये हैं। उदाहरण के लिए देश भर में 74,000 से अधिक अनौपचारिक कार्यकर्ताओं को कूड़े-कचरे के प्रबंधन की शृंखला से जोड़ा गया है जिससे उन्हें लगातार आजीविका मिली है। ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन के अम्बिकापुर मॉडल ने स्वयं सहायता समूहों की हजारों महिला सदस्यों को रोज़गार उपलब्ध कराए हैं जिससे ऐसे प्रत्येक सदस्य को 10 हजार रुपये से 15 हजार रुपये तक की आमदनी हो रही है जिससे उनका जीवनस्तर उन्नत हुआ है। नागरिकों में सामाजिक उद्यमिता और नवसृजन की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है और इस क्षेत्र में कूड़े-करकट से मूल्यवर्धित पदार्थ बनाने वाले स्टार्ट अप्स यानी नये उद्यम उभर कर सामने आये हैं। इस तरह के उद्यमों में मंदिरों के बेकार फूलों और अन्य पूजा सामग्री से अगरबत्ती बनाना, बेकार टायरों से घर का फर्नीचर तैयार करना, ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण कर हस्तशिल्प वस्तुएं, सजावटी सामान/मूर्तियां, आकर्षक कपड़ा/जूट के थैले तैयार करना (प्लास्टिक की थैलियों की जगह

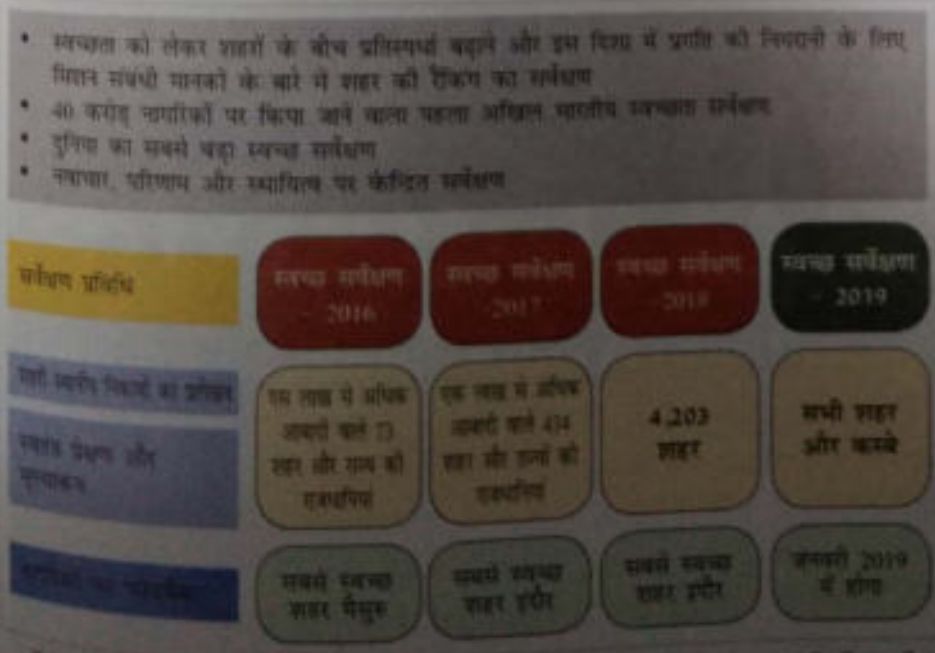

चित्र 5 : स्वच्छ सर्वेक्षण – मिशन की उपलब्धियों और उसके संचालन की निगरानी

सफलता की कहानी

प्लास्टिक मुक्त सीतामढ़ी

सीतामढ़ी बिहार का पहला जिला था जो 17 जुलाई, 2018 को खुले में शौच से मुक्त हुआ और अब चरणबद्ध तरीके से बहुचर्चित 'प्लास्टिक से मुक्त' की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण/लोहिया स्वच्छ योजना के तहत की जा रही इस पहल के पीछे स्वच्छ सीतामढ़ी, सुंदर सीतामढ़ी की परिकल्पना की गयी है।

इसके अंतर्गत सभी प्रकार की प्लास्टिक थैलियां (हैंडल वाली या बिना हैंडल वाली), प्लास्टिक या थर्मोकोल की बनी प्लेटों, चम्मचों, पॉली प्रोपेन की सादी थैलियों, खाने के सामान के कंटेनरों, प्लास्टिक की पैकेजिंग और प्लास्टिक की बोतलों (पीईटी और पीईटीई) पर पाबंदी लगायी जा रही है।

प्रोजेक्ट जीविका के कई स्वयं सहायता समूहों की ग्रामीण महिला उद्यमियों से अब तक करीब 10 लाख कपड़े के थैले लोगों को बांटने के लिए खरीदे जा चुके हैं। प्लास्टिक मुक्त सीतामढ़ी अभियान से न केवल खाद्य शृंखला में प्लास्टिक की सूक्ष्म मात्रा को कम किया जा सकेगा बल्कि सीतामढ़ी जिले में ग्रामीण महिला उद्यमियों को भी बढ़ावा मिलेगा। यह जिले में हाल में शुरू किये गये स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम-जीविका के लक्ष्यों के अनुरूप है और सामाजिक उद्देश्य के लिए महिला सशक्तीकरण में सहायक साबित होगा।

Scanned by CamScanner

इस्तेमाल के लिए), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नये और किफायती उपकरण बनाना और कूड़ा-करकट इकट्ठा करने, उसके पुनर्चक्रण और उससे उपयोगी सामग्री अलग करने के लिए नया बिजनेस मॉडल विकसित करने जैसे कार्य शामिल हैं।

एक मोटे अनुमान के अनुसार आज ठोस अपशिष्ट से 20,000 करोड़ रुपये लागत के मूल्यवर्धित पदार्थ बनाये जा रहे हैं (यह मानते हुए कि 1 मीट्रिक टन कूड़े से 3,000 रुपये का उपयोगी सामान बन सकता है)। अगर समुचित तरीके से उपयोग करके फायदा उठाया जाए तो इसे कई खरब रुपये के कारोबार में बदला जा सकता है जिसका अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हो सकता है।

आगे का रास्ता

स्वच्छता पर दिये जा रहे ज़ोर से राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और नगर प्रशासकों तथा आम नागरिकों में जो उत्साह पैदा हुआ है उससे आगे का कार्यक्रम तो एक तरह से तय हो ही चुका है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में पुनर्जीवन और आमूल परिवर्तन के लिए अमृत नाम का (अटल मिशन फॉर रीज्यूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मेशन) अभियान प्रारंभ किया है जिसके अंतर्गत गंदे पानी और मल-मूत्र आदि का प्रबंधन किया जाता है। स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट (एस.सी.एम.) में भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को विकास का एक मानदंड माना गया है। इन कार्यक्रमों से स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) को स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के अपने दायित्व को पूरा करने की दिशा में मदद मिली है। इन कार्यक्रमों ने जो रफ्तार पकड़ ली है अब उसे बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा, बल्कि इसे नवाचार और पासा पलटने वाले तरीके अपनाकर और भी तेज करने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही मजबूत विनियामक और कानूनी ढांचा खड़ा करने तथा कड़ाई से अमल सुनिश्चित करने पर भी जोर रहेगा। मुझे आशा है कि आवास और शहरी मामलों मंत्रालय और केन्द्र/राज्य सरकारों/स्थानीय प्रशासनों ने हाल में जो पहल की हैं और राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जो पहल की हैं उससे हमारी प्रगति की रफ्तार और सुदृढ़ और तेज होगी।

निष्कर्ष

आज स्वच्छता और साफ-सफाई की अवधारणाएं अधिकार संपन्नता और जीवन की गुणवत्ता की भावना को साकार कर रही हैं। स्वच्छता और शहरों को कूड़े-कचरे से मुक्त बनाने के कार्य में निवेश से लोगों के जीवन पर असर पड़ने के साथ ही पर्यावरण पर भी व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। इससे सबको, खास तौर पर समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों को बेहतर जीवन मिलने के साथ ही महिलाओं और बच्चों की गरिमा व सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। इसका एक और अच्छा परिणाम परजीवियों के माध्यम से फैलने वाली बीमारियों के प्रकोप को कम करने के रूप में सामने आ सकता है। साथ ही कूड़ा बीनने वालों और अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों को आजीविका के अच्छे अवसर और बेहतर आमदनी मिल सकती है। इससे अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में उद्यमिता के नये अवसर उत्पन्न हो सकते हैं और पर्यटन क्षेत्र की क्षमता में सुधार से विदेशी मुद्रा की अधिक आमदनी से देश के सकल घरेलू उत्पाद पर अच्छा असर पड़ सकता है। इन सबके परिणामस्वरूप पर्यावरण को और अधिक स्वच्छ बनाने में मदद मिल सकती है। स्वच्छ पर्यावरण से 'स्वस्थ, स्वच्छ, समर्थ और समृद्ध' भारत का निर्माण होगा और 2022 तक नये भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। ❑

संदर्भ

1. यूनीसेफ, http://www.unicef.org/media/media_68359.html ls izklr
2. http://www.edugreen.teri.resin/explore/solwaste/health.htm
3. PHFI (2015). इंडिया हैल्थ रिपोर्ट- न्यूट्रीशन 2015. http://www.transformnutrition.org/wp-content/uploades/sites/3/2015/12/INDIA-HEALTH-REPORT-NUTRITION_2015_for_Web.pdf
4. http://www.mowQs.gov.insites/default/files/UNICEF_Economic_impact_study.pdf
5. द कस्तूरिरंगन रिपोर्ट
6. जागरण। (2017, सितंबर)। जागरण नेशनल से http://www.jagran.com/news/national-swachh-bharat-abhiyan-effects-illness-70-percent-decreased-in-indore-16744224-html

गूगल मैप्स में सार्वजनिक शौचालय खोजिए

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत गूगल के साथ शौचालयों में साफ-सफाई की स्थिति की समीक्षा के लिए एक अभियान छेड़ा है। इसके अंतर्गत भारत में सभी स्थानीय गाइडों को गूगल मैप पर शौचालयों की समीक्षा करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह अभियान गूगल मैप्स की एक विशिष्टता का एक हिस्सा है जिसके तहत सभी नागरिकों को अपने शहर के शौचालयों को गूगल मैप्स, सर्च एंड असिस्टेंट में खोजने तथा उनके बारे में फीडबक देने का अवसर प्रदान करता है। इस समय गूगल मैप्स पर भारत के 500 से अधिक शहरों के 30 हजार से ज्यादा शौचालय 'स्वच्छ भारत मिशन शौचालय' के नाम से देखे जा सकते हैं।

अक्टूबर से नवंबर 2018 तक चलाए जा रहे इस संयुक्त अभियान में देश भर में सार्वजनिक शौचालयों के बारे में सूचना और आसानी से उन्हें खोजने, उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान में स्थानीय गाइडों से गूगल मैप्स पर हैशटैग लू रिव्यू (#LooReview) के जरिए इन शौचालयों का मूल्यांकन और समीक्षा करवाई जाएगी जिसे गूगल लोकल गाइड्स नाम के सोशल चैनल पर प्रदर्शित किया जाएगा। लोकल गाइड वो लोग हैं जो गूगल मैप्स पर सूचनाएं, फोटो और समीक्षा साझा करते हैं ताकि लोगों को दुनिया को खोजने में मदद मिले।

कोई भी व्यक्ति लोकल गाइड समुदाय में शामिल हो सकता है और गूगल मैप्स पर स्थानों की समीक्षा कर सकता है। किसी भी स्थान पर जाने और उसके बारे में समीक्षा लिखने के लिए गूगल मैप्स पर जाकर 'पब्लिक टॉयलेट नियर मी' (मेरे आस-पास सार्वजनिक शौचालय) खोजें।

लोकल गाइड समुदाय में ऑनलाइन शामिल हों:

फेसबुक : गूगल लोकल गाइड्स, ट्विटर - @googlelocalguides यू-ट्यूब : Google Local Guides ❑

Scanned by CamScanner

स्वच्छता सबकी ज़िम्मेदारी

अक्षय राउत

राजनीतिक इच्छाशक्ति, जन नीति, निवेश और भागीदारी - सबको एक साथ आना होगा तभी ऐसा अनुकूल माहौल तैयार होगा जिसमें जनता की भागीदारी से स्वच्छता की कमी और आरोग्य की उपेक्षा का हमेशा के लिए खात्मा करने वाला आखिरी प्रहार किया जा सकेगा

जैसा हम सभी जानते हैं, स्वच्छता का मतलब होता है साफ-सफाई। साफ-सफाई अपने शरीर की, अपने आस-पड़ोस की और कुछ लोग तो यहां तक कहना चाहेंगे कि साफ-सफाई अपने मन-मस्तिष्क और आत्मा की। स्वच्छता हम सबके निजी और सामाजिक जीवन को किसी न किसी तरह से प्रभावित करती ही है। कई अध्ययनों में स्वच्छता और लोगों के स्वास्थ्य तथा समृद्धि के बीच संबंध स्थापित किया गया है। इसलिए यह कहना एकदम उपयुक्त है कि स्वच्छता संबंधी मानदंडों पर अमल सुनिश्चित करना और उन्हें बनाए रखना हममें से हर एक का निजी और सामूहिक दायित्व है। यह किस तरह से होगा, इसका क्या पैमाना और क्या असर होगा यह, स्वाभाविक रूप से व्यक्ति या समूह के संदर्भ के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। मगर एक बात निश्चित है - इसमें हर एक की भागीदारी आवश्यक है। निस्संदेह स्वच्छता सबकी ज़िम्मेदारी है।

स्वच्छता के लिए सब कुछ

राजनीतिक इच्छाशक्ति, जन नीति, निवेश और भागीदारी - सबको एक साथ आना होगा। तभी ऐसा अनुकूल माहौल तैयार होगा जिसमें जनता की भागीदारी से स्वच्छता की कमी और आरोग्य की उपेक्षा का हमेशा के लिए खात्मा करने वाला आखिरी प्रहार किया जा सकेगा। इन सबके समन्वय से क्या प्राप्त किया जा सकता है, इसके ज्वलंत उदाहरण लेसोथो, कोरिया और मलेशिया हैं।

15 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री ने यही किया। महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर उन्होंने 'स्वच्छता' जैसे ताक पर रख दिये गये

लेखक भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में महानिदेशक हैं। ईमेल: akshay.rout@gmail.com

Scanned by CamScanner

विषय को सबके सामने लाकर रख दिया। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया कि वे अपने गांवों, शहरों, गलियों, मोहल्लों, स्कूलों, मंदिरों और अस्पतालों आदि को साफ-सुथरा रखें। इस पर अमल करने के लिए 2 अक्टूबर, 2014 को 'स्वच्छ भारत मिशन' का शुभारंभ किया गया। यह भी फैसला किया गया कि संपूर्ण राष्ट्र 2 अक्टूबर, 2019 को गांधीजी की 150वीं जयंती पर उनके सपनों का स्वच्छ भारत उन्हें समर्पित करने के लिए एकजुट होकर कार्य करेगा। पेयजल और ग्रामीण स्वच्छता मंत्रालय को ग्रामीण भारत को खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्ति दिलाने तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट के उपयुक्त विधियों से निपटान की ज़िम्मेदारी देने के साथ ही साफ-सफाई की दिशा में की जा रही अन्य मंत्रालयों, विभागों, अन्य संबद्ध क्षेत्रों व पक्षों द्वारा की गई पहल में तालमेल रखने का काम भी सौंपा गया। पेयजल और ग्रामीण स्वच्छता मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए राष्ट्र के तमाम संसाधनों और पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जाए।

प्रत्येक विभाग की ज़िम्मेवारी

सबकी ज़िम्मेदारी के रूप में साफ-सफाई स्वच्छ भारत मिशन का एक सुंदर नारा भर नहीं है। यह स्वच्छता को मुख्यधारा में लाने गंभीर प्रयासों की आधारशिला है और नीतियों को परियोजनाओं में बदलने का एक व्यवस्थित आंदोलन भी है। स्वच्छता से सीधे न जुड़ें असंबद्ध मंत्रालयों और विभागों द्वारा भी अपने मुख्य कार्य के अतिरिक्त साफ-सफाई के इस काम के लिए संसाधन जुटाने और समय निकालने से इस बात का पक्का आश्वासन मिलता है कि स्वच्छता का यह सफर आगे बढ़ता ही चला जाएगा और इसमें पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। केन्द्रीय मंत्रालयों की योजनाओं और नीतियों में स्वच्छता का समावेश करने के लिए सुनिश्चित परिणाम देने वाली विशेष परियोजनाएं तैयार की गयी हैं। इनके परिणामस्वरूप स्वच्छ भारत मिशन सभी संबद्ध पक्षों के प्रयासों में तालमेल कायम करने वाला सर्वसमावेशी आंदोलन बन गया है।

स्वच्छता कार्य योजना

स्वच्छता कार्य योजना 1 अप्रैल, 2017 को प्रारंभ की गयी। इसके अंतर्गत मंत्रालय और विभाग स्वच्छता संबंधी कार्य योजनाओं की ज़िम्मेदारी लेकर और अपने बजट में इसके लिए प्रावधान करके इसे अपनी मुख्य ज़िम्मेदारियों में शामिल करते हैं। स्वच्छता कार्य योजना सरकारी कामकाज में नयी तरह की एक शुरुआत है जिसमें सभी पक्ष अपने पूर्वनिर्धारित कार्यों के बावजूद स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर कार्य करते हैं। यह बात बड़ी उत्साहवर्धक है कि सभी मंत्रालयों/विभागों ने 2017-18 और 2018-19 में स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए निश्चित धनराशि का प्रावधान रखा है। वित्त वर्ष 2017-18 में 18,179 करोड़ रुपये रखे गए थे जबकि 2018-19 में 17,000 करोड़ रुपये खर्च करने का वादा किया गया है।

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा साल भर में आयोजित की जाने वाली स्वच्छता गतिविधियों और उनके लिए आवंटित धनराशि के बारे में एक विवरण तैयार किया गया है। स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत सचिवों की एक

स्वच्छता कार्य योजना के उदाहरण

- पेट्रोल पम्पों और सर्विस स्टेशनों पर स्वच्छता की निगरानी और इसमें सुधार के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक मोबाइल एप Swachhta@Petrol Pump तैयार किया है।
- स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी स्कूलों में बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।
- नागर विमानन, विद्युत और ग्रामीण विकास मंत्रालयों ने जल संरक्षण, बायो-ईंधन, अपशिष्ट पुनर्चक्रण और कूड़े-करकट से ऊर्जा प्राप्त करने की दिशा में पहल की है।
- रेलवे अक्टूबर 2019 तक बायो-डाइजेस्टर शौचालयों के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए फाइव-एस (सॉर्ट-छांटो, सेट इन ऑर्डर-व्यवस्थित करो, शाइन-चमकाओ, स्टैंडर्डाइज-मानकीकृत करो और सस्टेन-चिरस्थायी बनाओ) नाम की पहल की है और स्वच्छ-स्वस्थ-सर्वत्र पर अमल में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित कर रही है।

Scanned by CamScanner

समिति इसकी त्रैमासिक समीक्षा करती है।

वर्ष 2018 में जिन मंत्रालयों ने स्वच्छता कार्य योजना में बेहतरीन कार्यनिष्पादन के लिए पुरस्कार प्राप्त किये हैं उनमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय शामिल हैं।

स्वच्छता पखवाड़ा

घर में दिया जला दो तो मंदिर में भी दिया जला मिलेगा। इसी कहावत पर अमल करते हुए देश के तमाम नागरिकों को स्वच्छता आंदोलन में भागीदार बनाने की योजना बनायी गयी है और इसकी शुरुआत एक मिसाल पेश करके दी गयी है। प्रधानमंत्री की पहल पर अप्रैल 2016 में स्वच्छता पखवाड़ों के आयोजन का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत पहले से तय साल भर के कार्यक्रम के अनुसार चार-पांच मंत्रालयों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में स्वच्छता को बढ़ावा देने की देशव्यापी मुहिम चलाने के लिए 15 दिन यानी एक पखवाड़े का समय दिया गया। अब तक इस तरह के 92 पखवाड़ों का आयोजन किया जा चुका है। एक पखवाड़े की इस अवधि में संबंधित मंत्रालय स्वच्छता संबंधी अपनी दैनिक गतिविधियों की जानकारी एक पोर्टल http://swachhbharat mission.gov.in/SwachhSamiksha/index.aspx पर रोजाना ऑनलाइन पोस्ट करते हैं। स्वच्छता पखवाड़े के अमल पर नजर रखने और उसकी समीक्षा के लिए मंत्री और सचिव तैयारी बैठकें करते हैं और किये गये कार्य की समीक्षा भी की जाती है। पखवाड़े की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए अंत में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। असल में पखवाड़े के दौरान 15 दिन तक संबंधित मंत्रालय को स्वच्छ भारत मंत्रालय माना जाता है। पखवाड़े के दौरान किये गये कार्यों के बारे में जानकारी भेजी जाती है जिसकी सर्वोच्च स्तर पर निगरानी की जाती है।

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने प्रत्येक मंत्रालय के लिए पुरस्कार भी प्रारंभ किये हैं जो उस मंत्रालय की संस्थाओं/संगठनों/प्रभागों को उनकी आंतरिक प्रतियोगिताओं तथा रैंकिंग के आधार पर दिये जाते हैं। स्वच्छता पखवाड़ों की शुरुआत के बाद से यह कार्यक्रम रोज़मर्रा की गतिविधियों वाले कार्यक्रम की बजाय चिरस्थायी और रचनात्मक पहल वाले कार्यक्रम में परिवर्तित हो चुका है जिसमें सभी सरकारी कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने पिछले दो वर्षों के दौरान स्वच्छता पखवाड़े की गतिविधियों को ईयर बुक यानी वार्षिकी के रूप में संकलित भी किया है। वर्ष 2017 में स्वच्छता पखवाड़े के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए रेल मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालयों को पुरस्कृत किया गया।

2018-19 में 76 मंत्रालय और विभाग स्वच्छता पखवाड़ों के आयोजन में भागीदार हैं।

स्वच्छ आइकॉनिक स्थल

प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार यह भी फैसला किया गया कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के धरोहर स्थलों तथा ऐसे तीर्थस्थानों में जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं, साफ-सफाई का खास ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि उनमें स्वच्छता का स्तर स्पष्ट रूप से नजर आए। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ ऐसे स्थानों को साफ-सुथरा रखने बल्कि उनके आस-पास के क्षेत्र की सफाई की भी बार-बार सलाह दी है। स्वच्छ भारत मिशन के एक भाग के रूप में स्वच्छ स्मारक स्थल परियोजना का उद्देश्य इसी लक्ष्य को प्राप्त करना है।

इस पर अमल के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने सहयोगी मंत्रालयों जैसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के साथ-साथ इन स्थानों की देखरेख के लिए उत्तरदायी राज्यों, स्थानीय निकायों, न्यासों और प्रबंधन समितियों के साथ तालमेल कायम किया है। इन स्वच्छ स्मारक स्थलों की साफ-सफाई की कार्ययोजना में मदद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रम और निजी कार्पोरेट घराने भी आगे आये हैं और वित्तीय, तकनीकी तथा प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों में सहायता कर रहे हैं।

परियोजना के तहत इस समय 30 स्थलों में काम हाथ में लिया गया और यह क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। चरणबद्ध तरीके से ऐसे 100 स्थलों में कार्य शुरू कर उनमें स्वच्छता के स्तर में सुधार लाने की योजना है ताकि उन्हें देखने आने वाले पर्यटक सुखद अनुभवों के साथ लौटें।

गंगा ग्राम परियोजना का उद्घाटन 12 अगस्त, 2017 को इलाहाबाद में सरपंचों के महा-सम्मेलन में किया गया। इसमें गंगा तट

Scanned by CamScanner

पर स्थित 4,475 गांवों को खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त घोषित किया गया। बाद में संबंधित राज्य सरकारों ने भी 24 गांवों की पहचान की जिनको गंगा ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा और खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त गांव का दर्जा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत इन गांवों में तालाबों और जल स्रोतों के जीर्णोद्धार, छिड़काव विधि से सिंचाई को बढ़ावा देने, पर्यटन के विकास, आधुनिक शवदाह गृहों के निर्माण, केन्द्र व राज्य की योजनाओं में तालमेल, गंदे पानी और ठोस कचरे के उचित निपटान के साथ ही जल संरक्षण परियोजनाओं, ऑर्गेनिक खेती, बागवानी और औषधीय पौधों की खेती जैसी गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी।

खुले में शौच और कूड़े-कचरे का ठीक से निपटान न करने से सिर्फ नदी पर ही नहीं बल्कि सारे गांव पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में ग्रामवासियों को जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों को गंगा ग्राम गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी सौंप कर उनमें सक्रिय भूमिका निभाने के लिए अधिकार संपन्न बना दिया गया है। जनता की भागीदारी गंगा ग्राम परियोजना का महत्वपूर्ण घटक है।

विद्यार्थियों और युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका

स्वच्छ भारत अभियान में विद्यार्थियों और युवाओं की सबसे उपयोगी भागीदारी है। शिक्षा संस्थाओं के परिसरों और उसके आस-पास के इलाकों की सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही वे बदलाव के माध्यम भी बन रहे हैं। स्कूलों और उनके आस-पास अपनी दैनिक स्वच्छता गतिविधियों के साथ-साथ वे स्वच्छता ऑलिम्पिक्स, स्वच्छता चुनाव और रैलियों में हिस्सा लेकर इस अभियान के सबसे बड़े संदेशवाहक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वे चित्रकारी करते हैं, निबंध और पत्र लिखते

हैं, फिल्म शूट करते हैं और अपने परिवार तथा समाज को स्वच्छता के महत्व के बारे में आश्वस्त करते हैं। जिन घरों में शौचालय नहीं है वहां वे इनके निर्माण की आवाज उठाते हैं।

स्कूलों के बच्चों की ही तरह युवा भी घर-घर जाकर जागरूकता पैदा कर रहे हैं। वे दीवारों पर प्रेरक चित्रकारी करते हैं, सार्वजनिक स्थानों की सफाई करते हैं और स्वच्छता के संदेश का प्रचार-प्रसार करते हैं। स्वच्छता स्वयंसेवकों के रूप में वे जबरदस्त ताकत के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं।

कालेज के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कम से कम 100 घंटे का स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम इस साल गर्मियों में शुरू किया गया है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने मानव संसाधन मंत्रालय और युवा कार्य तथा खेल मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया। मई और जुलाई के दौरान जब अधिकतर विद्यार्थियों की छुट्टियां रहती हैं, यह कार्यक्रम संचालित किया गया। इसकी शुरुआत युवाओं को प्रधानमंत्री के सीधे आह्वान के साथ हुई और उत्साही स्वच्छता इंटर्न गांवों में स्वच्छता गतिविधियों में स्थानीय लोगों का हाथ बंटाने के लिए निकल पड़े। इस कार्य में भाग लेने वाले युवाओं को इंटर्नशिप प्रमाणपत्र देकर करिअर संबंधी प्रोत्साहन भी प्रदान किया गया। प्रतियोगिता के जरिए उन्हें शैक्षिक क्रेडिट्स और पुरस्कार भी दिये गये। इस अभियान की विशालता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 4 लाख युवाओं ने स्वच्छता श्रमदान और व्यवहार परिवर्तन पहल में हिस्सा लिया।

कारपोरेट भागीदारी

स्वच्छ भारत मिशन को कारपोरेट क्षेत्र की ओर से भी जोरदार समर्थन मिला। लोगों से व्यक्तिगत चंदा लेने के साथ-साथ कंपनियों से वित्तीय अंशदान प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत कोष की स्थापना की गयी जिसमें मार्च 2018 तक 839.3 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके थे। इस धनराशि का उपयोग चुने हुए क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी मानदंडों को और उन्नत बनाने में खर्च किया जा रहा है।

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय तथा टाटा ट्रस्ट के बीच भागीदारी जनादेश पर अमल के कार्य में कार्पोरेट घरानों की ताकत का लाभ उठाने का शानदार उदाहरण है। इस साझेदारी में कौशल संपन्न ऐसे युवा विशेषज्ञों का वर्ग तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया जो जिला स्वच्छ भारत प्रेरक के रूप में कार्य कर सकें। टाटा ट्रस्ट ने स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत इन 475 पेशेवर युवा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया ताकि वे इस अभियान के तहत जिलों को विभिन्न स्वच्छता कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने, उन पर अमल करने और उनकी निगरानी का कार्य

Scanned by CamScanner

कर सकें। वे अब स्वच्छ भारत कार्यान्वयन परिवार के सक्रिय सदस्य बन चुके हैं। इंडिया सेनीटेशन कोअलिशन जैसे अन्य संगठनों ने अनेक कारपोरेट घरानों को एकजुट किया है जो देश के स्वच्छता परिदृश्य में सुधार के कार्य में लगे हैं और स्वच्छ भारत मिशन को सुदृढ़ कर रहे हैं। कुछ कारपोरेट घरानों ने स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के संचार अभियानों में बड़ा योगदान किया है।

मीडिया का सहयोग

मीडिया ने भी लोगों को स्वच्छता में कमी के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक बनाने का बीड़ा उठाया है और व्यवहार परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मीडिया ने स्वच्छ भारत की आवाज को और बुलंद करने में मदद की है और यह सुनिश्चित किया है कि समाचार-रिपोर्टों, विशेष रिपोर्टों, संपादकीय और वार्ताओं जैसे विभिन्न रूपों में यह समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारतीय मीडिया की भूमिका नियमित रूप से हर स्तर पर प्रशंसा हो रही है और वह इसका सचमुच हकदार है।

स्वच्छता दूत

इसमें कोई शक नहीं कि स्वच्छ भारत मिशन को करोड़ों भारतवासियों का दृढ़ समर्थन मिला है। गरीब-अमीर, नौजवान-बुजुर्ग, सुप्रसिद्ध-जनसामान्य, सबने इसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान दिया है जिससे समाज में बदलाव स्पष्ट नजर आता है। बॉलीवुड, खेल जगत और जीवन के अन्य क्षेत्रों के जाने-माने लोगों ने स्वच्छता के संदेश को बढ़ावा देने में अपना समय और शक्ति लगाई है। इन हस्तियों को लेकर बनाए गये अनेक कई दृश्य-श्रव्य विज्ञापनों ने आम लोगों को प्रभावित किया है। हाल में बनी 'टॉयलेट-एक प्रेम कथा', 'पैडमैन' तथा 'हलका' और 'गुटर गू' जैसी कई फीचर फिल्मों ने भी स्वच्छता के संदेश को शानदार तरीके से लोगों तक पहुंचाया है।

जन-जन की ज़िम्मेदारी

अंततोगत्वा स्वच्छता की इस लड़ाई का नेतृत्व आम लोगों ने ही किया है। स्वच्छता के समर्थन में अभूतपूर्व जनांदोलन स्वस्थ और स्वच्छ राष्ट्र के निर्माण की दिशा में किये जा रहे वर्तमान प्रयासों को मजबूत आधार प्रदान करता है। यह इस आंदोलन का एक ऐसा पहलू है जो हाल में संपन्न महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में चर्चा का मुख्य विषय रहा। स्वच्छ भारत का जिक्र आते ही अब हमारे मन में स्वत: ही 'जनांदोलन' का सुंदर चित्र उभर कर सामने आ जाता है।

स्वच्छत भारत अभियान के तहत चलाए गए विशेष अभियानों जैसे 'स्वच्छता ही सेवा' (2017 और 2018), चलो चंपारण, खुले में शौच से मुक्त सप्ताह व पखवाड़े ने देश के करोड़ों लोगों को एकजुट किया है और अनगिनत लोग चिरस्थायी स्वच्छता के उपाय अपनाने को प्रेरित हुए हैं। जानी-मानी हस्तियों, अधिकारियों और आम लोगों ने स्वच्छता अभियानों में समान रूप से श्रमदान किया है और गड्ढा खोदने, उसे खाली करने जैसे कार्यों को लोगों के सामने करके दिखाया है। इससे स्वच्छता कार्यों को लेकर लोगों की गलत धारणाओं को दूर करने इनके साथ जुड़े कलंक को मिटाने में मदद मिली है। विभिन्न धर्मों और पंथों के प्रमुख भी स्वच्छता अभियान के समर्थन में आगे आए हैं और उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया है।

महिलाएं तो स्वच्छ भारत अभियान की चैम्पियन ही रही हैं और कोई भी अन्य समूह इसमें उनकी बराबरी नहीं कर सकता। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन के सिलसिले में 2017 और 2018, दोनों ही वर्षों में 'स्वच्छ शक्ति' का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में अनोखा कार्य करने वाली महिला चैम्पियनों को सम्मानित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किये गये। इस साल जुलाई में 'स्वच्छ जीविका' और 'स्वच्छ विहार' नाम के दो विशेष अभियान भी प्रारंभ किये गये जिनमें महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों (दीदियों) के घरों में स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध करायी गयीं। जीविका बहनों के नेतृत्व में दो गड्ढे वाले 10 लाख शौचालयों का निर्माण पहले ही पूरा किया जा चुका है।

एकजुट कार्रवाई

इस विवरण के जरिए यह बताने का प्रयास किया गया है कि व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए देश में चलाया गया दुनिया का सबसे बड़ा अभियान - स्वच्छ भारत मिशन- संयोगवश नहीं शुरू किया गया बल्कि यह एक सुचिंतित अभियान है जिसमें सभी संबद्ध पक्षों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। इससे यह भी साबित हो गया है कि चिरस्थायी स्वच्छता की इमारत के निर्माण के लिए हममें से हर एक को अपने प्रभाव क्षेत्र के दायरे में एक ईंट रखनी होगी।

इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वच्छता सबकी ज़िम्मेदारी है। ❑

Scanned by CamScanner

स्वच्छता से शुचिता तक

सुदर्शन अय्यंगर

देश के 15वें प्रधानमंत्री ने करीब चार साल पहले 15 अगस्त, 2014 को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए ये बातें कही थीं-

'भाइयो और बहनो, 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती होगी... महात्मा गांधी को सफाई सबसे प्रिय थी। इसलिए मैं इस साल 2 अक्टूबर से 'स्वच्छ भारत' शुरू करने जा रहा हूं और इसे अगले 4 साल तक आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं आज से इसकी शुरुआत करना चाहता हूं और वह यह है कि देश के सभी स्कूलों में शौचालय हो और लड़कियों के लिए अलग शौचालय होना चाहिए। ऐसा होने पर ही हमारी बेटियां बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर नहीं होंगी।

26 जनवरी, 1950 को अपने संविधान की प्रस्तावना में हमने अपने आप से जो वादा किया था, उसे पूरा करने में हमें लंबा सफर तय करना है। हमने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाई चारा हासिल करने का वादा किया था। जब तक हर नागरिक के पास साफ पीने का पानी और पर्याप्त स्वच्छता संबंधी सुविधाएं नहीं होंगी, तब तक हमारे समाज में असमानता और अन्याय का सिलसिला जारी रहेगी। जल और स्वच्छता देश के हर नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दरअसल, स्वच्छ भारत की दिशा में बढ़ने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

स्वच्छ हिंदुस्तान का गांधी जी का सपना

स्वच्छ हिंदुस्तान को लेकर गांधी जी का सपना शौचालय बनाने और खुले में शौच से मुक्त से कहीं ज्यादा व्यापक है। हालांकि, ये दोनों चीजें इस दिशा में पहला और काफी महत्वपूर्ण कदम हैं। गांधी जी हिंदुस्तान को स्वच्छ देखना चाहते थे। वह तन और मन दोनों की स्वच्छता के हिमायती थे। उन्हें देश के लोगों के रहन-सहन की स्थिति और घरों-मोहल्लों में साफ-सफाई की हालत को देखकर काफी पीड़ा होती थी। उन्हें कचरा और मल-मूत्र की सफाई करने वाले समुदायों के साथ होने वाले बर्ताव को लेकर भी दुःख होता था। गांधी जी को इस बात का भी अहसास था कि बीतते वक्त के साथ स्वच्छता को लेकर भारतीय लोगों का रवैया काफी अवैज्ञानिक हो गया। कचरे और मल-मूत्र की सफाई करने वाले लोगों और अन्य के बीच खाई पैदा करने के लिए यही रवैया ज़िम्मेदार था।

सफाई का काम करने वाले समुदाय को उस वक्त मुख्य बस्ती के बाहर और गरीबी में रहने के लिए मजबूर रहना पड़ता था। उन्हें शारीरिक और मानसिक स्तर पर बेहद अमानवीय परिस्थितियों से गुजरना पड़ता था।

ऐसे समय में गांधी जी ने घर, आश्रम, आस-पड़ोस, गलियों और शौचालयों को साफ करने के लिए अपने हाथ में झाड़ू उठाई। जब उन्होंने साफ-सफाई की स्थिति सुधारने का आह्वान किया तो उनके दिमाग में बिना किसी तरह के भेदभाव के इन वंचित समुदायों को बाकियों से जोड़ना और बराबरी का दर्जा मुहैया कराना था।

झाड़ू सिर्फ भौतिक स्तर पर सफाई का प्रतीक नहीं था। उन्होंने झाड़ू को अंत्योदय का प्रतीक बनाया। जाहिर तौर पर उन्होंने अंत्योदय से लेकर सर्वोदय तक लोगों के कल्याण की यात्रा का नेतृत्व किया और इस संबंध में सलाह जारी की। सफाई का काम सिर्फ शरीर और पर्यावरण तक सीमित नहीं था।

गांधी जी के लिए मन या आत्मा की शुद्धि किसी भी मानव का अंतिम लक्ष्य था। उनके लिए चरित्र निर्माण की खातिर सत्य का अनुसरण ही जीवन का लक्ष्य था। उनके मुताबिक, अहिंसा को ताकत के रूप में स्वीकार करना आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी। गांधी ने महसूस किया था कि हमारे लोगों में एक तरह का संकट है। यह आत्म विश्वास

> गांधी जी ने निजी साफ-सफाई, गांव और शहर के स्तर पर स्वच्छता कार्यों को रचनात्मक कार्य की तरह पेश किया। छुआछूत यानी अस्पृश्यता हटाना रचनात्मक कार्यक्रम के अलावा उन 11 संकल्पों में भी शामिल था, जिसका पालन हर सत्याग्रही को करना पड़ता था

लेखक गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद के पूर्व कुलपति और गांधी हेरिटेज मिशन के सदस्य हैं। ईमेल: sudarshan54@gmail.com

Scanned by CamScanner

का संकट है। उनका मानना था कि भारत के लोगों ने अपनी मौलिकता का त्याग कर दिया है और ब्रिटिश हुकूमत के तहत चापलूस बन गए हैं। गांधी जी ने अपना पूरा जीवन खुद और अपनी आत्मा के शुद्धिकरण में लगाया और अपने सार्वजनिक जीवन और समाज सेवा में भी इस पर अमल किया। गांधी जी ने इस तरह से हिंदुस्तान को स्वच्छ भारत बनाने का अपना देखा था, जहां हर नागरिक शारीरिक, सामाजिक और दिल से स्वच्छ और पवित्र हो।

दक्षिण अफ्रीका में स्वच्छता को लेकर गांधी जी का काम

गांधी जी दादा अब्दुल्ला की कंपनी में नौकरी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के कुछ ही दिनों के भीतर उन्हें वहां भारतीयों के प्रति ब्रिटिश और यूरोपीय लोगों का अपमानजक और अहंकार भरा रवैया देखने को मिला। जब उनके साथ ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे से जबरन निकाले जाने की घटना हुई, तो उन्होंने भारत के अस्पृश्य समुदाय से होने वाला बर्ताव जैसा महसूस हुआ। उन्होंने सुन रखा था कि गोरा समुदाय सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाता है कि भारतीय मूल के लोग गंदगी में रहते हैं और साफ-सफाई नहीं रखते हैं।

गांधी जी ने भी यह पाया कि भारतीय मूल के लोग बेहतर साफ-सफाई नहीं रखते हैं। गांधी जी का मुख्य लक्ष्य वहां मौजूद भारतीय लोगों के लिए शहरों और अन्य जगहों में वैसे ठिकाने ढूंढना था, जहां साफ-सफाई की अच्छी व्यवस्था हो। गांधी जी ने पहले भारतीय मूल के लोगों में साफ-सफाई की स्थिति को सुधारने के लिए उनके साथ काम किया। उसके बाद उन्होंने नगर निकाय अधिकारियों के सामने यह मुद्दा उठाया और आधारभूत ढांचे को सुधारने पर जोर देने लगे। उसके बाद उन्होंने नगर निकाय इकाइयों और उनके अधिकारियों की उपेक्षा और उदासीनता का मुद्दा उठाने के लिए अफ्रीका और भारत में राज्य सरकारों और उपनिवेशों के सचिवों के कार्यालय तक अपनी बात पहुंचाई। सार्वजनिक जीवन में गांधी जी अनोखी शख्सियत हैं, जिन्होंने निजी और सार्वजनिक स्तर पर स्वच्छता के मामले को आगे बढ़ाया।

जब गांधी जी को भारत में गंदगी से रूबरू होना पड़ा

दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारत भ्रमण किया। अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने गंदगी, अस्वास्थ्यकर माहौल और पूरे देश में धूल और कचरे का सामना किया। वह और उनका ग्रुप पहले टैगोर के शांतिनिकेतन में ठहरा। वहां पर उन्होंने पाया कि ब्राह्मण रसोइए शुद्धता और अशुद्धता की परंपरा का तो पालन करते हैं, लेकिन बेहद गंदगी भरे माहौल में काम करते हैं। साफ-सफाई की हालत बुरी थी। गांधी जी और उनकी टीम ने साफ-सफाई और खाना बनाने में शांतिनिकेतन के निवासियों की भागीदारी का नियम शुरू किया।

उन्होंने रेलवे में आम लोगों के साथ तीसरी श्रेणी के डिब्बे और पानी वाले जहाज में भी निचले दर्जे में यात्रा करने का फैसला किया था। पानी वाले जहाज की यात्रा के दौरान उन्होंने पाया कि वह जिस दर्जे में यात्रा कर रहे थे, वहां पर स्नान घर काफी गंदा था, जबकि शौचालय से भारी दुर्गंध आ रही थी। इस दर्जे में शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए किसी शख्स को मल-मूत्र पर से गुजकर जाना पड़ता था और अगर गंदगी और दुर्गंध की तस्वीर पूरी करने में किसी तरह की कमी थी, तो उसकी भरपाई मुसाफिर अपनी लापरवाह आदतों से कर देते थे। वे जहां बैठते थे, वहीं थूक देते थे और इस तरह से आसपास के वातावरण को गंदा कर देते थे। एक ट्रेन की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा था, "हम सफाई के बुनियादी नियमों के बारे में नहीं जानते हैं। हम कहीं पर डिब्बे में इस बात को सोचे-समझे बगैर फर्श पर थूक देते हैं कि इसका इस्तेमाल अक्सर सोने के लिए भी किया जाता है। हम इसका उपयोग करने में जरा भी सावधानी नहीं बरतते और इसके परिणामस्वरूप कंपार्टमेंट में गंदगी की भरमार रहती है। कथित तौर पर बेहतर श्रेणी वाले यात्री अपने कम खुशकिस्मत बंधुओं को आकर्षित और प्रभावित करते हैं। इन लोगों में मैंने छात्रों की दुनिया को भी देखा है। कभी-कभी उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं और अच्छी जैकेट पहनते हैं, इसलिए बैठने की जगह का चुनाव अपने हिसाब से करने के अधिकार का दावा करते हैं। मैंने तमाम जगहों पर रोशनी डाली है और जैसा कि आपने मुझे बोलने का विशेषाधिकार दिया है, तो मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं। निश्चित तौर पर हमें स्वशासन की दिशा में अपनी प्रगति को लेकर चीजें दुरुस्त करनी चाहिए।"

लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा

भारतीय शहरों में स्वच्छता

जिन मंदिरों में वह गए, वहां भी हालात ऐसे ही थे। हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा के दौरान उन्होंने पाया कि लोग सड़कों और गंगा के किनारों को गंदा कर देते थे। यहां तक कि लोग गंगा के पवित्र पानी को भी गंदा करने में संकोच नहीं करते थे। उन्हें रास्तों पर और गंगा नदी के किनारे लोगों को पाखाना-पेशाब करते देख काफी कष्ट होता था। वृंदावन-मथुरा, बनारस के विश्वनाथ मंदिर और गुजरात के डाकोर में स्थित कुछ अलग नहीं थी। गांधी जी ने जिन शहरों, कस्बों और गांवों का दौरा किया, वहां भी

Scanned by CamScanner

उन्हें स्वच्छता को लेकर बेहतर स्थिति नजर नहीं आई।

घरों-मोहल्लों में भी हालात भिन्न नहीं थे। जब उन्होंने 1916 में बनारस का दौरा किया तो पाया कि पुराने शहर के मोहल्ले दुर्गंध का अड्डा बने हुए थे और इन जगहों पर स्वच्छता नियमों और नागरिक सुविधा संबंधी परंपराओं का जमकर उल्लंघन हो रहा था। एक मोहल्ले से गुजरते हुए मकान की छत से थूक फेंका जाना देखना या इसका अनुभव काफी आम था। उन्होंने उस वक्त मद्रास शहर में गंदे और अस्वास्थ्यकर परंपराओं और साफ-सफाई करने वाले समुदाय को लेकर सवर्ण जाति के अहंकार भरे रवैये को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। बिहार के पवित्र गया शहर में उन्हें साफ-सफाई की सबसे खराब स्थिति का सामना करना पड़ा। शैक्षणिक संस्थानों और सम्मेलनों जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में गांधी जी ने पहली बार स्वच्छता और स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया। भारत पहुंचने के बाद गांधी जी ने जितने भी कार्यक्रम में भागीदारी निभाई, उसमें सबसे पहले स्वच्छता कमेटी गठित की जाती थी। साथ ही, सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी नेता को अस्थायी शौचालय समेत प्रति दिन की सफाई के काम में अपना योगदान करना होता था। कांग्रेस पार्टी के सत्र में गांधी की मौजूदगी या गैर-मौजूदगी, दोनों परिस्थितियों में भी देश को स्वतंत्रता मिलने तक यह परंपरा बनी। गांधी जी जिन आश्रम में रहे और जहां उन्होंने काम किया तथा उनके द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों में सफाई का काम इन सभी संस्थानों के निवासियों के लिए रोज की दिनचर्या का हिस्सा था।

स्वच्छता को लेकर गांधी जी का कार्यकलाप

गांधी जी और आश्रम में रहने वाले बाकी लोगों के लिए सही विज्ञान और उचित तकनीक की जरूरत थी और उनके द्वारा इस दिशा में काम किया जाता था। उन्होंने लिखा है कि आश्रम में उनके द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक स्वच्छता संबंधी सेवाएं जरूरी और पवित्र मानी जाती थीं। इसके बावजूद समाज में इसे हेय दृष्टि से देखा जाता था और इसके कारण ऐसे कार्यों की उपेक्षा हो जाती थी और इसमें सुधार के लिए काफी गुंजाइश थी। ऐसे में आश्रम ने इस कार्य में बाहरी श्रम को शामिल नहीं करने पर विशेष जोर दिया। इसकी बजाय आश्रम के सदस्य खुद साफ-सफाई का काम करते थे। आम तौर पर आश्रम में आने वाले नए सदस्यों को इस विभाग से जोड़ा जाता था। हमें यहां याद रखना चाहिए कि गांधी जी काफी व्यस्त इंसान थे और वह अपने हर मिनट का ध्यान रखते थे। इसके बावजूद अपने आश्रमों में साफ-सफाई के काम में हिस्सा लेने के लिए उनके पास हमेशा वक्त रहता था। यह हम सब के लिए सबक है। हम शायद शौचालय साफ करने जैसे सांकेतिक कार्य और आसपास के पर्यावरण से ही संतुष्ट हो जाते हैं और बाकी का खयाल रखने की जिम्मेदारी सरकारी व्यवस्था पर छोड़ देते हैं।

वर्धा स्थित सेवाग्राम आश्रम में 1930 के दशक के उत्तरार्द्ध में स्वच्छता को लेकर उनकी दिलचस्पी कम नहीं हुई थी। उन्होंने आश्रम के निवासियों के लिए इसको लेकर कुछ इस तरह से विस्तार से बताया था,

"हर किसी को अपना बरतन धोना चाहिए और इसे सही जगह पर रखना चाहिए। अतिथि और आगंतुकों से अनुरोध है कि वे अपनी प्लेट, पीने के पानी का बरतन, कटोरी, चम्मच के अलावा अपना लालटेन, बिछावन, मच्छरदानी और अंगोछा आदि सब कुछ सही जगह पर रखा जाना चाहिए। तमाम तरह के कचरे को कूड़ेदान में डाला जाना चाहिए। पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया जाता है। पीने के लिए उबला हुआ पानी का इस्तेमाल किया जाता है। बरतन और प्यालों को आखिर में उबले हुए पानी से धोया जाता है। आश्रम के कुओं का बिना उबला हुआ पानी पीने के लिहाज से सुरक्षित नहीं है। हमें सड़क पर थूकना नहीं चाहिए और न ही ऐसी जगहों पर नाक साफ करनी चाहिए। हमें ये काम ऐसी जगह करना चाहिए, जहां कोई चलता-फिरता नहीं हो।

शौच का निपटान उसके लिए तय जगह पर ही किया जाना चाहिए। पाखाना-पेशाब करने के बाद खुद को साफ करना जरूरी है। शौच क्रिया के बाद हमें शुद्ध मिट्टी और शुद्ध पानी से अपना हाथ धोकर उसे साफ अंगोछे से पोंछना चाहिए। मल को पूरी तरह से सूखी मिट्टी से ढक देना चाहिए, ताकि इस पर मक्खियां नहीं आएं। शौचालय की सीट पर सावधानीपूर्वक बैठना चाहिए, ताकि यह सीट गंदी नहीं हो। अगर अंधेरा है तो शौचालय में लालटेन जरूर ले जाना चाहिए। जो चीज अपनी तरफ मक्खियां आकर्षित करती है, उसे ठीक ढंग से ढंकना चाहिए।"

देश के स्वच्छ शख्स का श्रेय इस रूप में भी याद करना चाहिए कि अपने जीवन के आखिरी दिनों तक उन्होंने कभी इस विषय को नहीं छोड़ा। 1947 के आखिर और जनवरी 1948 में प्रार्थना सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कई बार लोगों से साफ-सुथरा रहने, अपने आसपास के वातावरण को साफ करने और स्वास्थ्य और सफाई का बेहतर ढंग अपनाने को कहा।

देश में स्वच्छता की स्थिति

देश में शौचालय के निर्माण को लेकर स्थिति में काफी सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने हाल में एक सार्वजनिक सभा में ऐलान किया कि देश में शौचालय की पहुंच का दायरा 2014 में 40 फीसदी थी, जो अब बढ़कर 90 फीसदी और उससे भी ज्यादा हो गया है। तकरीबन 4.5 लाख गांव शौचालयों के दायरे में हैं। यह आंकड़ा बेहतर है, लेकिन सफाई और स्वास्थ्य के मामले में इसे पहला कदम माना जा सकता है। यहां तक कि पूर्ण स्वच्छता अभियान में निजी घरों में शौचालयों

Scanned by CamScanner

का निर्माण, ग्रामीण स्कूलों में यह सुविधा उपलब्ध कराना और मल संबंधी कचरा प्रबंधन शामिल है। हमें अंतिम दोनों पहलुओं के बारे में बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है।

राज्यों को भी बड़े पैमाने पर सक्रियता दिखानी होगी। भारत में हाथ से मैला ढोने पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद इस व्यवस्था के 2017 में पूरे देश में 300 से भी ज्यादा मौतें हुईं। एक अंतर-मंत्रालय कार्य बल की गणना के मुताबिक, देश में हाथ से मैला ढोने का काम करने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 52,236 हो गई है, जबकि 2017 तक सरकारी रिकॉर्ड में कुल 13,000 ऐसे कामगार थे। कुल 600 में से 121 या इससे भी ज्यादा जिलों में इस तरह का काम करने वाले लोग मौजूद हैं। इस तरह का काम करने वाले सबसे ज्यादा लोगों की संख्या रेलवे में है। इस आंकड़े में वैसे लोग शामिल नहीं हैं, जो नाली और सेप्टिक टैंक को साफ करने का काम करते हैं। देश को तत्काल इस पर सक्रियता दिखानी चाहिए और हाथ से मैला ढोने के काम को खत्म किए जाने को लेकर समर्पण भाव से काम करना चाहिए। सरकार, समाज और नागरिक का लक्ष्य पूर्ण स्वच्छता अभियान होना चाहिए।

अंत:करण को आलोकित करने की जरूरत

स्वच्छता की स्थिति में सुधार और अस्पृश्यता को हटाने के लिए गांधी का अभियान भी स्वयं और समाज के साथ सत्याग्रह का जरूरी तत्व था। सत्याग्रह का निहितार्थ आत्म-शुद्धिकरण था। यहां तक कि इसके लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए जरूरी था। सत्य की खोज में वह इस नतीजे पर पहुंचे कि सभी इंसान और यहां तक कि सभी जीवित प्राणी अंतिम सत्य यानी ईश्वर के सामने बराबर हैं। गांधी जी के लिए स्वयं और पर्यावरण को साफ करना आत्म-शुद्धिकरण की दिशा में पहला कदम था। आत्म-शुद्धिकरण का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दलितों के खिलाफ लंबे समय से चले आ रहे पूर्वाग्रह को छोड़ना था। दलित समुदाय समाज के पीड़ित स्वच्छता कामगार थे। गांधी जी चाहते थे कि हर सवर्ण हिंदू सदियों से दलितों के साथ हुए अन्याय को महसूस करे। दूसरा चरण इसकी स्वीकारोक्ति और पश्चाताप का भाव था। वह चाहते थे कि आखिर में हिंदू धर्म से जुड़ा हर सवर्ण अस्पृश्यता को हटाने और अस्पृश्यों की हालत बेहतर करने के लिए काम करे।

गांधी जी ने निजी साफ-सफाई, गांव और शहर के स्तर पर स्वच्छता कार्यों को रचनात्मक कार्य की तरह पेश किया। छुआछूत यानी अस्पृश्यता हटाना रचनात्मक कार्यक्रम के अलावा उन 11 संकल्पों में भी शामिल था, जिसका पालन हर सत्याग्रही को करना पड़ता था। भारत में स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान में भी अब भी ठोस सुधार की जरूरत है। हमने अब तक पूरी तरह से गांधी जी के आह्वान का पूरी तरह से पालन नहीं किया है। गांधी जी समाजशास्त्र को समझते थे और उन्होंने साफ-सफाई के काम की गरिमा को बताने का प्रयास किया। इस तरह से उन्होंने पारंपरिक सफाईकर्मियों को सम्मान और गरिमा मुहैया कराया, जिनकी इस तरह का काम करने के लिए आलोचना की जाती थी। स्वतंत्रता हासिल करने के बाद हम व्यक्ति और व्यक्तियों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना भूल गए। इसकी बजाय सरकार ने सभी जिम्मेदारी संभाल ली और अभियान को योजनाओं में बदल दिया। योजनाओं का दायरा सीमित कर इसे लक्ष्य, संरचना और संख्या तक सीमित कर दिया है। भारत में हममें से ज्यादातर लोगों को 'शौचालय प्रशिक्षण' और स्वच्छता व स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी शिक्षा की जरूरत है।

इंसान के तौर पर अब तक हमारा व्यवहार जिम्मेदारी भरा नहीं रहा है। लोग अपने विचारों में लापरवाह, अहंकारी और गैर-जिम्मेदार, जबकि आदतों में गंदे और मैले बने हुए हैं। हम अपने शौचालयों, आस-पड़ोस को गंदा छोड़ देते हैं और बस, रेल व जहाज समेत सार्वजनिक स्थानों को जलाते और उसे गंदा करते हैं। स्वच्छ हिंदुस्तान हमारे लिए अब भी एक सपना है और हमें इस सिलसिले में कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। हमारे द्वारा एक समाज के तौर पर सूक्ष्म तरीकों से भेदभाव और छुआछूत की प्रथा जारी है। जातिगत अभिशाप का मामला खत्म नहीं हुआ है। हमारा मन निर्मल नहीं है। स्वशासन और शासन व्यवस्था को आम तौर पर पूरी तरह से नहीं समझा जाता है और लोग सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में स्वच्छ नहीं हैं। अब समय अपने भीतर प्रकाश को फैलाते हुए बेहतर कार्यों के जरिये गांधी जी को श्रद्धांजलि देने और स्वयं व समाज के लिए जिम्मेदारी को महसूस करने का है। ❑

संदर्भ

1. पूर्व कुलपति, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद। यह लेख 'इन द फुटस्टेप्स ऑफ महात्मा' किताब पर आधारित है:- http://www.pmindia.gov.in/en/tag/speech/18December, 2015
2. एम के गांधी, 1955, आश्रम ऑब्जर्वेंस इन एक्शन, वालजीभाईदेसाई द्वारा गुजराती से अनुवाद, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, पृ. संख्या 149-511 इसे यहां भी देखा जा सकता है: www.gandhiheritage portal.org
3. गांधी एंड सैनिटेशन, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, 2016
4. पूरी रिपोर्ट के लिए देखें- https://www.sundayguardianlive.com/news/12448-over-300-manual-scavengers-died-2017
5. पूरी रिपोर्ट के लिए देखें- https://indianexpress.com/article/india/53000-manual-scavengers-in-12-states-four-fold-rise-from-last-official-count-5218032/

सफलता की कहानी

पुणे गांव के लोगों ने वारी के तीर्थयात्रियों को दी अपने शौचालय के इस्तेमाल की इज़ाज़त

प्रसिद्ध तीर्थस्थल वारी के रास्ते में मौजूद घरों के लोगों ने 15 दिनों की इस तीर्थयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को अपने शौचालय के इस्तेमाल की सुविधा दी। ये श्रद्धालु पंढरपुर जाते हैं।

महाराष्ट्र की 333 साल पुरानी शानदार परंपरा के तहत पूरे राज्य में पालकी यात्रा निकाली जाती है। इस साल यह यात्रा 6 जुलाई, 2018 को शुरू हुई और 22 जुलाई, 2018 को खत्म हुई। आम तौर पर इस यात्रा में राज्य के और बाहर से तकरीबन 10 लाख श्रद्धालु इसमें हिस्सा लेते हैं।

पिछले दो साल में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) अभियान के तहत पूरे जिले में 2 लाख से भी ज्यादा शौचालय बनाए गए। हालांकि, इस तीर्थयात्रा के तहत लंबी दूरी तक पैदल सफर करने वालों के लिए यह पर्याप्त नहीं था। हालांकि, इस साल तीर्थयात्रा के रास्ते में सभी निजी घरों के लोगों से अनुरोध किया गया कि वे तीर्थयात्रियों को अपने निजी शौचालय की पेशकश करें। इस बात का संकेत देने के लिए कि ये शौचालय तीर्थयात्रियों के लिए मुफ्त में उपलब्ध हैं, एक सफेद झंडा भी लगाया जाता था। लोगों ने इस अपील पर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। यहां तक कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों ने भी तीर्थयात्रियों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। ❑

Scanned by CamScanner

स्वराज की सीढ़ी : स्वच्छता

डी जॉन चेल्लादुरई

गांधी के लिए स्वच्छता सिर्फ जैविक आवश्यकता नहीं है; यह जीवनशैली है, सत्य की अनुभूति करने का अटूट हिस्सा है। स्वच्छता को लेकर उनकी समझ सत्य को लेकर उनकी सार्वभौमिक अनुभूति से जुड़ा हुआ है। गांधी सत्य को ईश्वर की तरह पूजते थे और उन्होंने इसे पवित्र माना। लिहाजा, उन्होंने 'स्वच्छता' की तुलना 'ईश्वर भक्ति' से की। उन्होंने 'स्वच्छता' को स्वतंत्रता के लिए जरूरी कदम माना और इसे 18 रचनात्मक कार्यक्रमों की सूची में शामिल किया। सत्य के इस अन्वेषी ने जीवन को सत्य का सबसे करीबी स्वरूप माना और इसलिए उन्होंने जीवन की तुलना सत्य या ईश्वर से की

आईसीएस की प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुका महाराष्ट्र का एक युवा गांधी से आशीर्वाद लेने उनके सेवाग्राम आश्रम पहुंचा। गांधी ने इस युवा से पूछा, 'आप आईसीएस क्यों बनना चाहते हैं ?' गांधी ने इस शख्स से कहा, 'गांवों में जाकर स्वच्छता के लिए काम करना भारत के लिए सबसे बड़ी सेवा है' और इस तरह से आईसीएस के आकांक्षी अप्पा पटवर्द्धन 'सफाई' की कला में विशेषज्ञता हासिल करते हुए एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी बन गए। स्वतंत्रता संग्राम के स्कूल में 'सफाई' और 'स्वच्छता' स्नातक के लिए टेस्ट जैसा था। विनोबा भावे, ठक्कर बापा, जे. सी. कुमारप्पा समेत कई प्रतिभाशाली युवकों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेते हुए सफाई और स्वच्छता को स्वतंत्रता का मूल मानकर इस दिशा में काम किया।

सत्य के खोजी के रूप में गांधी ने संयमित जीवनशैली अपनाई और स्वच्छता को सर्वोच्च अहमियत दी। राष्ट्रपिता के रूप में उन्होंने राष्ट्र-निर्माण में स्वच्छता की अनिवार्यता को महसूस किया और स्वच्छता को ईश्वर की भक्ति जैसा बताया।

विकास के लिए जरूरी शर्त

विकास मानव सभ्यता का भरोसेमंद सहयोगी रहा है। पाषाण युग के शिकारी जीवन से लेकर परिष्कृत शहरी इंसान बनने तक के सफर में हमने जीवन में अपने बड़े पैमाने पर बदलाव लाया है। विकास को नवोन्मेष के जरिये जीवन के पहलुओं में बेहतरी के तौर पर देखा जाता है। मानव विकास की धारणा में किसी व्यक्ति के बेहतर जीवन से जुड़े सभी पहलू शामिल हैं: खाद्य सुरक्षा, साफ और ताजी हवा, शुद्ध पीने का पानी, स्वास्थ्य और सफाई, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकल्पों की स्वतंत्रता आदि।

मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो के मुताबिक, विकास के ऐसे ज्यादातर पहलुओं को शारीरिक जरूरतों की पूर्ति की श्रेणी में रखा जा सकता है। विकासशील समुदाय के रूप में हमने शारीरिक जरूरत के एक पहलू- आपूर्ति के लिए तंत्र बनाने के लिए काफी परिश्रम किया है, जबकि दूसरे पहलू निपटारे की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। विकास के एजेंडे में यह नहीं के बराबर दिखता है।

एक कहावत है कि "अच्छी शुरुआत आधी सफलता है" बाकी आधी सफलता को लेकर एक कहावत यह भी है, "आप किस तरह से किसी काम को खत्म करते हैं, यह भी काफी अहम है।"

मानव सभ्यता अगर खाना तैयार करने और विकास के उपकरण बनाने में पारंगत है, तो उसे अपने उपोत्पाद के निपटारे की कला में भी विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए।

चाहे इंसान का मलमूत्र हो, औद्योगिक कचरा, विकास संबंधी गतिविधियों से जुड़े अन्य कचरे हों, दुर्भाग्य से इन तमाम चीजों के निपटारे की तरफ ध्यान नहीं है।

असभ्यता

कचरों के निपटारे की व्यवस्था नहीं होने के कारण हमारे रेलवे स्टेशनों, बस अड्डे, बाजार और यहां तक कि मंदिरों के अहाते में भी मक्खी, मच्छर और चूहा आदि की भरमार देखने को मिलती है। गांधी ने इसे 'दुर्गंध का अड्डा' कहा था। यहां तक कि हमने पवित्र गंगा को भी गंदे नाले में बदल दिया है। गांधी ने सार्वजनिक जगहों पर साफ-सफाई को लेकर शहरों के लोगों के लापरवाही भरे रवैये पर सख्त टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि

लेखक गांधी रिसर्च फाउंडेशन, जलगांव, महाराष्ट्र में गांधीवादी विद्वान और डीन हैं।

Scanned by CamScanner

गांधी ने कहा था, ''एक आदर्श गांव का निर्माण इस तरह से किया जाएगा कि इसमें स्वच्छता के लिए पूरी गुंजाइश हो। इसमें पर्याप्त रोशनी वाली झोपड़ियां होंगी और इसमें हवा की आवाजाही के लिए निर्माण से जुड़ी सामग्री वैसी होगी, जो घर के 5 मील के दायरे में उपलब्ध हो सके।''

लोग जब बंबई की सड़क पर चलते हैं, तो उन्हें लगातार यह डर बना रहता है, वहां मौजूद इमारतों से कोई उन पर थूक देगा। वह खुले में शौच को 'असभ्यता' मानते थे और उन लोगों के बारे में उनका कहना था, ''अगर कोई भी उस वक्त वहां से गुजरता था, हमें अपनी आंखें नीची करनी पड़ती है।''

सच्चाई की अनुभूति

गांधी के लिए स्वच्छता सिर्फ जैविक आवश्यकता नहीं है; यह जीवनशैली है, सत्य की अनुभूति करने का अटूट हिस्सा है। स्वच्छता को लेकर उनकी समझ सत्य को लेकर उनकी सार्वभौमिक अनुभूति से जुड़ा हुआ है। गांधी सत्य को ईश्वर की तरह पूजते थे और उन्होंने इसे पवित्र माना। लिहाजा, उन्होंने 'स्वच्छता' की तुलना 'ईश्वर भक्ति' से की। उन्होंने 'स्वच्छता' को स्वतंत्रता के लिए जरूरी कदम माना और इसे 18 रचनात्मक कार्यक्रमों की सूची में शामिल किया। सत्य के इस अन्वेषी ने जीवन को सत्य का सबसे करीबी स्वरूप माना और इसलिए उन्होंने जीवन की तुलना सत्य या ईश्वर से की। वैसी सभी प्रक्रियाएं जो जीवन का हिस्सा और इससे संबंधित आचरण भी सत्य की अनुभूति का हिस्सा है। इस अर्थ में गांधी स्वच्छता, व्यक्ति के अंदर और बाहर की सफाई को ईश्वर की अनुभूति का साधन मानते थे। उनका कहना था, ''हम गंदे शरीर के साथ ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। स्वच्छ शरीर का गंदे शहर में वास नहीं हो सकता है।''

स्वराज

भारत की स्वतंत्रता को लेकर गांधी के समग्र नजरिये के कारण उन्हें स्वराज के लक्ष्य में स्वच्छता की अनोखी अहमियत के बारे में समझने का अवसर मिला। भारतीय होम रूल के अधिकार सिलसिले में मांग करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, ''स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।'' गांधी के लिए स्वराज के काफी गहरे मायने हैं। उन्होंने 'यंग इंडिया' में कहा, 'स्वराज पवित्र और वैदिक शब्द है, जिसका मतलब स्व-शासन, आत्म-नियंत्रण होता है। यह अर्थ सभी नियंत्रण से मुक्ति नहीं है, जो अक्सर 'स्वतंत्रता' के अर्थ में प्रयुक्त होता है।' तमाम गतिविधियों को लेकर आत्म-नियंत्रण। इसमें सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने से भी आत्म-नियंत्रण का मामला शामिल है। उन्होंने यह भी कहा, ''मेरे सपनों का स्वराज गरीब आदमी का स्वराज है और समाज के अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति को सहयोग के लिए आत्म-नियंत्रण की जरूरत है।''

गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के मौके पर वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उस कचरे का जिक्र किया था, जो इस पवित्र शहर में दुर्गंध फैला रहा था। उनका कहना था, ''कितनी भी भाषणबाजी हमें स्वशासन (स्वतंत्रता के लिए) उपयुक्त नहीं बनाएगी। हम अपने आचरण से इसके उपयुक्त बन सकते हैं।'' स्वच्छता उनके लिए 'स्वराज्य यज्ञ' रहा।

उन्होंने इस 'आत्म-नियंत्रण' की 'व्यक्तिगत' और 'सार्वजनिक' दोनों जीवन में वकालत की। निपटान संबंधी तंत्र के बारे में गांधी का कहना था, ''स्वराज तब तक पूर्ण स्वराज नहीं माना जाएगा, जब तक इसके तहत सभी इंसानों को जीवन की सामान्य सुविधाएं सुनिश्चित तौर पर मुहैया नहीं कराई जाती हैं।''

स्वच्छता, राष्ट्र निर्माण का एक कार्य

स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने स्वतंत्रता के आयामों की व्याख्या की और 'स्वच्छ व्यवहार' के महत्व को रेखांकित किया। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि ''खुद की सरकार के बारे में सोचने से पहले हमें आवश्यक परिश्रम करना होगा।'' गांधी ने सेहत के दृष्टिकोण से गांवों की स्थिति को बेहद खराब बताया था। उनका कहना था, ''हमारी गरीबी का एक प्रमुख कारण साफ-सफाई के बारे में जरूरी ज्ञान की कमी है।'' इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि स्वराज भारत को सिर्फ अंग्रेजी दासता से नहीं बल्कि हर तरह की दासता से मुक्त कर रहा है।

एक और अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वराज सतत परिश्रम और पर्यावरण के बुद्धिमतापूर्ण उपयोग का फल होगा।

आनंद प्रदान करने वाला कार्य है स्वच्छता

गांधी अहिंसात्मक जीवन को ईश्वर और सत्य की पूजा के सबसे अच्छे साधन के रूप में देखते थे। वह सफाई को शुद्धिकरण का कार्य मानते थे और इसमें उन्हें काफी आनंद मिलता था। गांधी के निजी सचिव प्यारेलाल इस बारे में दिलचस्प किस्सा बताते हैं। उनके मुताबिक, यह मामला नोआखली का है, जहां हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सौहार्द कायम करने के लिए गांधी सघन दौरे पर थे। उन्होंने लिखा है, ''यहां तक कि नोआखली में रात काफी ओस भरी थी और गांधी जी को जिस फुटपाथ से गुजरना था, उसमें काफी फिसलन हो गई थी। यह 19 जनवरी, 1947 की बात है, जब वह बादलकोट से अलकारा के लिए रवाना हुए थे। हालांकि, सख्त पैदल मार्च के आदी रहने के बावजूद कर्नल जीवन सिंह का संतुलन बिगड़ गया और वह लुढ़क गए। इसके बाद गांधी ने हंसते हुए उन्हें उठने में

Scanned by CamScanner

देने के लिए अपनी लाठी का आखिरी सिरा आगे बढ़ाया।''

फुटपाथ की जगह इतनी संकरी थी कि दोनों एक-एक कर ही आगे बढ़ सकती है। अचानक से यह काफिला रुक गया। दरअसल, गांधी रुककर कुछ सूखी पत्तियों की मदद से फुटपाथ पर से मल हटा रहे थे। फुटपाथ को कुछ सांप्रदायिक शरारती तत्वों द्वारा फिर से गंदा कर दिया गया था। इस पर मनु ने पूछा, ''आप मुझे यह काम क्यों नहीं करने देते?'' गांधी ने हंसते हुए जवाब दिया, ''आपको नहीं पता है कि इस तरह का काम करने में मुझे कितनी खुशी होती है।''

ग्राम-राज्य

उनकी राय में गांव सभी प्रमुख उत्पादों, आहार का केंद्र होते हैं और ग्राम राज्य भारत का दिल है। गांधी का मानना था कि ग्राम्य जीवन में भारत की आत्मा है। इसलिए उन्होंने हिंद स्वराज की तुलना 'ग्राम राज्य' से की। स्वतंत्र भारत के गांवों की कल्पना करते हुए गांधी ने कहा, ''गांव को सुधार कर ऐसा बनाया जाए, जहां ग्राम्य जीवन से जुड़ी हर तरह की जरूरतों के उत्पादन के लिए 'ग्राम उद्योग हो, कोई अनपढ़ नहीं हो, सड़कें साफ हों, निकासी के लिए तय जगह हो और कुएं भी साफ हों।''

गांधी ने कहा था, ''एक आदर्श गांव का निर्माण इस तरह से किया जाएगा कि इसमें स्वच्छता के लिए पूरी गुंजाइश हो। इसमें पर्याप्त रोशनी वाली झोपड़ियां होंगी और इसमें हवा की आवाजाही के लिए निर्माण से जुड़ी सामग्री वैसी होगी, जो घर के 5 मील के दायरे में उपलब्ध हो सके।''

गांवों की खराब स्थिति पर खेद जताते हुए उन्होंने लिखा था, ''अगर गांवों में साफ-सफाई की स्थिति बेहतर होती है, तो न सिर्फ लाखों रुपये की बचत होगी, बल्कि लोगों के रहन-सहन के स्तर में भी काफी हद तक सुधार होगा। एक बीमार किसान कभी भी सेहतमंद किसान के बराबर मेहनत नहीं कर सकता है।''

स्वच्छता के मुद्दे पर प्रतिक्रिया

साफ-सफाई संबंधी दिक्कतों पर गांधी ने प्रस्ताव दिया था कि ''हर गांव में एक जगह पर सबसे सस्ता शौचालय बनना चाहिए।'' उनके मुताबिक, स्वच्छता से संबंधित पूरे विषय पर विस्तार से मंथन नहीं किया गया है। यह पेशा गंदा नहीं बल्कि पवित्र और जीवन को सुरक्षा प्रदान करने वाला है। सिर्फ हमने इसका स्तर नीचे कर दिया है। हमें इसे ऊपर उठाकर इसे वास्तविक दर्जा मुहैया कराना है।

गांधी ने कहा है कि सत्याग्रह और रचनात्मक कार्यक्रम एक ही पक्षी के दो पंख हैं। किसी एक पहलू के बिना दूसरे का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने स्वच्छता जैसे रचनात्मक कार्यक्रम और स्वतंत्रता संग्राम के बीच जो अटूट संबंध बनाया, वह पूरे देश में साफ तौर पर जाहिर था। शौचालय की सफाई और स्वच्छता के अन्य कार्य सत्याग्रही के लिए योग्यता बन गए। हर सार्वजनिक सभा में (चाहे वह ब्रिटिश के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान हो या समाज सुधार की पहल) में 'गांवों की सफाई' का पहलू जुड़ा हुआ रहता था।

मेहतर या भंगी कहे जाने वाला देश का एक तबका लंबे वक्त से मैला ढोने के काम से जुड़ा था और यहां तक कि इस समुदाय को बाकी हरिजनों द्वारा भी नीची नजर से देखा जाता था। गांधी इन लोगों की तकलीफों को लेकर काफी चिंतित थे, क्योंकि इस तबके को समाज के सबसे निचले पायदान पर माना जाता था, जबकि वे समुदाय की स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित सबसे अहम काम को अंजाम देते थे।

उनका कहना था, ''ये सबके द्वारा सामाजिक रूप से बहिष्कृत हैं, जबकि वह समाज में साफ-सफाई के लिए सबसे जरूरी समूह है, लिहाजा उनका अस्तित्व भी उतना ही आवश्यक है।'' भंगी समुदाय के लोगों को अपने हाथों से मैला उठाकर बास्केट में रखना पड़ता था और कीटाणुओं और बैक्टीरिया से सुरक्षा के लिए उन्हें किसी तरह का उपाय नहीं मुहैया कराया जाता था। भंगी बंधुओं को सम्मान देने के लिए गांधी ने प्रस्ताव दिया कि 'हम सबको खुद को भंगी बनना पड़ेगा।' जब भी वह दिल्ली जाते थे, तो वह भंगी समुदाय के लोगों के साथ उनकी कॉलोनी में रहते थे या उनसे मिलते थे।

गांधी के इस नजरिये के बाद कई संस्थानों ने उनके इस आह्वान को अपनाया और 'सफाई' अभियान शुरू किया। सफाई विद्यालय-देहू रोड, निर्मल ग्राम निर्माण केंद्र, नाशिक जैसे कुछ संस्थानों ने इस अभियान को काफी गंभीरता से लिया।

हरिजन सेवक संघ ने 1963 में साबरमती गांधी आश्रम, अहमदाबाद में सफाई विद्यालय की स्थापना की। इसका मकसद भंगियों को इस तरह के काम से मुक्त कराना था। सफाई विद्यालय के मुख्य उद्देश्य इस तरह हैं: झाड़ू लगाने वालों और मेहतरों का उत्थान; शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य और सफाई के स्तर के बेहतर बनाना।

निष्कर्ष

गांधी ने सत्य की ईश्वर की तरह पूजा की और अहिंसा को इसका साधन माना- यह 'जीवन जीने का साधन' है। 'साधन' और 'साध्य' के बारे में गांधी ने कहा कि वह वास्तविक अर्थ में साधन को साध्य से ज्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे, क्योंकि साधन पर उनका अख्तियार रहता है। उनका कहना था कि अगर आप साधन को दुरुस्त रखते हैं तो साध्य अपने-आप ठीक रहेगा। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि विश्व परिदृश्य पर आगे बढ़ते हुए भारत को शुद्ध और स्वच्छ रास्ता अपनाना चाहिए और इससे लक्ष्य यानी साध्य के रूप में 'प्रतिष्ठा और गौरव' हासिल होगा। उन्होंने कहा था, ''जब बसंत की आभा हर पेड़ में परिलक्षित होती है, तब पूरी पृथ्वी युवापन की ताजगी से भर जाती है। जब स्वराज की भावना पूरे समाज में फैल चुकी है, तो जीवन के हर क्षेत्र में एक ऊर्जा का भाव है।'' ❑

संदर्भ

1. 'बीओई इकनॉमिक ग्रोथ: मीटिंग द चैलेंजेज ऑफ ग्लोबल डिवेलपमेंट', 6 अक्टूबर 2004,
2. http://www.worldbank.org/depweb/english/beyond/beyondco/beg_01.pdf|04
3. सीडब्ल्यूएमजी, खंड 13, पृ. 213।
4. स्पीच एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सीडब्ल्यूएमजी, खंड 13, पृ. 213।
5. कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम: इट्स मीनिंग एंड प्लेस, नवजीवन, अहमदाबाद, 1941।
6. यंग इंडिया, 19/11/1925।
7. यंग इंडिया, , 19-03-1931, पृ. 38।
8. आईबिड, पृ. 212
9. यंग इंडिया, 26-03-1931, पृ. 46।
10. स्पीच एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सीडब्ल्यूएमजी, खंड 13, पृ. 213
11. शिक्षण अने साहित्य, 18-08-1929; 41:295।
12. यंग इंडिया, 12-06-1924, पृ. 195।
13. यंग इंडिया, 05-01-1922, पृ. 4 और यंग इंडिया, 27-08-1925, पृ. 297, एमओएमजी, पृ. 319।
14. प्यारेलाल - लास्ट फेज।
15. लेटर टू मुन्नालाल शाह, 4-4-1941; 73:421।
16. हरिजन, 18-08-1940।
17. शिक्षण अने साहित्य, 18-08-1929; 41:295।
18. हरिजन, 05-12-1936; 64:105।
19. यंग इंडिया; 5 नवंबर, 1925।
20. http://www.ssi.org.in/about_history.htm
21. हरिजन, 18-01-1942, पृ. 4।

Scanned by CamScanner

स्वच्छता के दूत

संतोष कुमार मल्ल

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने रैलियों, प्रतियोगिताओं, भारत स्काउट और गाइड जैसी गतिविधियों के माध्यम से कई सामुदायिक लोक-संपर्क कार्यक्रम भी शुरू किये हैं ताकि जन-जागृति का प्रसार हो और लोगों को साफ-सफाई तथा व्यक्तिगत आरोग्य के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। स्वच्छ भारत अभियान में विभिन्न कार्यक्रमों तथा मंचों पर बच्चों, उनके माता-पिता तथा अध्यापकों को भागीदारी बनाकर केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने बच्चों को समाज के स्वच्छता-दूत के रूप में उभर कर आने का मौका दिया है।

भगवद्गीता के 13वें अध्याय में 'शौचम्' अर्थात् स्वच्छता का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आत्मोन्नति करना चाहता है तो स्वच्छता एक ऐसा गुण है जिसे उसे अपनाना होगा। 'शौच' से मन की निर्मलता, संतोष, इन्द्रियों पर विजय और आत्मानुभूति की स्थिति में पहुंचने की क्षमता भी उत्पन्न होती है। हमारी समृद्ध संस्कृति और मूल्य प्रणाली में भी आंतरिक और बाह्य स्वच्छता पर जोर देते हुए इसे शरीर, मन और आत्मा के कल्याण के लिए आवश्यक बताया गया है। 'स्वच्छता दिव्यता के बहुत समीप है' - भारतीय संस्कृति का सदियों पुराना एक ऐसा जीवन-मूल्य है जिसमें हमने जन्म लिया है और हम पले-बढ़े हैं। यह एक सुस्थापित तथ्य है कि किसी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य से ही उस राष्ट्र की अच्छी स्थिति का निर्धारण होता है और यह भी सत्य है कि स्वच्छता नागरिकों के आरोग्य को बढ़ाने में योगदान करने वाले विभिन्न कारकों में से सबसे प्रमुख है। सरकार के स्वच्छता अभियान के तब तक वांछित परिणाम नहीं आ सकते जब तक इसमें जनता की भागीदारी न हो और वह इसे जनांदोलन का रूप न दे दे। 'स्वच्छ भारत' अभियान को प्रत्येक देशवासी का अभियान बनाने का माननीय प्रधानमंत्री का 2 अक्टूबर, 2014 का आह्वान अब धीरे-धीरे एक वास्तविकता बनता जा रहा है और समाज के सभी वर्गों, आयु और पृष्ठभूमियों के लोग इसमें बड़े पैमाने पर हिस्सा ले रहे हैं।

लेखक केंद्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीनस्थ स्वायत्तशासी संगठन के आयुक्त हैं। ईमेल: skmall1973@gmail.com

Scanned by CamScanner

यह बात सब है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रमुख उद्देश्यों में से एक प्रमुख मकसद यह भी रहा है कि किस तरह विद्यार्थी में सबके साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए सह-अस्तित्वपूर्ण दृष्टिकोण के साथ संतुलित जीवन जीने की भावना जगाकर कि उसकी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग किया जाए। शिक्षा बच्चे को न केवल समकालीन विश्व के साथ सामन्जस्य स्थापित करने की प्रक्रिया में मदद करती है, बल्कि यह उसे भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार करती है। जीवन के शुरुआती दौर में हमारी समृद्ध संस्कृति और जीवन-मूल्यों से बच्चे को अवगत कराने से उसे अपनी जड़ों से जुड़ने में आसानी होगी। वह अनायास उन मूल्यों को आत्मसात कर लेगा, क्योंकि जीवन-मूल्यों को ग्रहण किया जा सकता है, सिखाया नहीं जा सकता। कोमल मस्तिष्क वाले बच्चों का स्वस्थ और संतुलित समाजीकरण तभी संभव है जब उसे विविध प्रकार के अवसर प्राप्त हों, उसे ऐसे पर्यावरण और परिवेश के साथ संपर्क का मौका मिले जिसमें इन मूल्यों पर अमल हो रहा हो, तभी वह इन्हें आत्मसात कर सकेगा।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के देश तथा विदेश में 1190 से अधिक स्कूल हैं और यह स्कूली शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में मानदंड तय करने वाली संस्था है। इनमें समाज के सभी क्षेत्रों के पहली कक्षा से लेकर बारहवीं तक के बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। संगठन ने बच्चों को हमारे देश की समृद्ध जीवन मूल्य प्रणाली से जोड़ने में हमेशा जोर दिया है ताकि उनका स्वस्थ और संतुलित विकास हो। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने रैलियों, प्रतियोगिताओं, भारत स्काउट और गाइड जैसी गतिविधियों के माध्यम से कई सामुदायिक लोक-संपर्क कार्यक्रम भी शुरू किये हैं ताकि जन-जागृति का प्रसार हो और लोगों को साफ-सफाई तथा व्यक्तिगत आरोग्य के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। स्वच्छ भारत अभियान में विभिन्न कार्यक्रमों तथा मंचों पर बच्चों, उनके माता-पिता तथा अध्यापकों को भागीदारी बनाकर केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने बच्चों को समाज के स्वच्छता-दूत के रूप में उभर कर आने का मौका दिया है।

संगठन ने स्वच्छता के इस अभियान को स्कूल की प्रमुख शैक्षिक गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु बनाकर बच्चों को सीखने का एक शानदार मौका बना दिया है। ये गतिविधियां हैं:

- स्वच्छता को स्कूल की मानसिकता में समाहित किया जा चुका है।
- पाठ्यचर्या का हिस्सा बन जाने से बच्चे रोजमर्रा की गतिविधियों जैसे फिल्म शो, पेंटिंग/निबंध लेखन प्रतियोगिताओं, 'रोल प्ले' गतिविधियों, अभियानों आदि के माध्यम से स्वच्छता संबंधी रोजाना के कार्यों में लगातार हिस्सा लेते रहते हैं।
- बच्चे स्वच्छता के बारे में स्कूल में जो कुछ सीखते हैं उसे अपने परिवार और आस-पड़ोस तक लेकर जाते हैं और यह बात स्कूल के कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी के रूप में देखी जा सकती है।
- स्वच्छता अभियान के तहत विद्यार्थी न केवल परिवार में साफ-सफाई के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं बल्कि सफाई का संदेश प्रसारित करने वाले स्वच्छता-दूत के रूप में भी कार्य करते हैं।
- देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान स्थित एफ.आर.आई. केन्द्रीय विद्यालय ने 2016 में सबसे स्वच्छ स्कूल की श्रेणी में 'राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार' जीता और माननीय प्रधानमंत्री से यह सम्मान ग्रहण किया।

1. स्वच्छता गतिविधियों में संलग्न वन अनुसंधान संस्थान केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थी।

2. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त श्री संतोष कुमार मल्ल और एफ.आर.आई. केन्द्रीय विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती चारु शर्मा प्रधानमंत्री से पुरस्कार प्राप्त करते हुए, साथ में तत्कालीन केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू भी हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों में स्वच्छ भारत अभियान पूरे संकल्प के साथ चलाया जा रहा है और हमारे स्कूल पहले के मुकाबले न सिर्फ स्वच्छ हुए हैं बल्कि 2014 से पहले की तुलना में अधिक हरे-भरे भी हो गये हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन का प्रयास न सिर्फ स्कूल और उनके आस-पास के माहौल को साफ-सुथरा रखना है बल्कि पेड़-पौधे लगाकर स्कूलों को हरा-भरा रखना भी है ताकि बच्चों में पर्यावरण संबंधी साक्षरता को बढ़ावा मिले।

- विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र का हरित विद्यालय कार्यक्रम बच्चों के सीखने का एक कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत सैद्धांतिक ज्ञान और पाठ्य पुस्तकों के बजाय 'करके सीखने' पर जोर दिया जाता है।
- कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों को प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का ऑडिट कराने में मदद दी जाती है, उन्हें पर्यावरण के प्रबंधनकर्ता के रूप में अपना खुद मूल्यांकन करने की प्रविधि बतायी जाती है और इस ऑडिट से पहचानी गई कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है।
- जो स्कूल अपनी रिपोर्ट भेजते हैं उनका कार्यनिष्पादन के आधार पर मूल्यांकन कर प्रमाणन किया जाता है। स्कूलों द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर फीडबैक भी उपलब्ध कराया जाता है।

Scanned by CamScanner

सफलता की कहानी

स्वच्छ बंधन के रूप में मनाया गया रक्षा बंधन

भाई और बहन के बीच प्रेम के प्रतीक के तौर पर मनाया जाने वाला त्योहार रक्षा बंधन इस बार झारखंड के गोड्डा जिले के एक गांव में स्वच्छ बंधन की तरह मनाया गया। इस सिलसिले में अनुसूचित जनजाति के लड़कों वाले एक आवासीय मध्य विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोड्डा जिले के सुदर पहाड़ी प्रखंड और पहाड़पुर ग्राम पंचायत के रामपुर गांव में मौजूद राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय उत्क्रमिक उच्च विद्यालय-धमारो में इस संबंध में कार्यक्रम हुआ। यह गांव काफी दूर-दराज के इलाके में मौजूद है। गोड्डा के जिला स्वच्छ भारत प्रेरक (जेडएसबीपी) शिवनाथ चटर्जी के मुताबिक इस गांव के बच्चे स्वच्छ भारत अभियान को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं थे और न ही उन्हें हाथ धोने की सही तकनीक या अहमियत के बारे में बताया गया था। इसके अलावा उन्हें खाने से पहले और शौचालय के इस्तेमाल के बाद हाथ धोने की जरूरत के बारे में भी नहीं बताया गया था। साथ ही, उन्होंने पहले कभी रक्षा बंधन भी नहीं मनाया था।

छात्र-छात्राओं को स्वच्छता, सफाई संबंधी सुरक्षित प्रचलनों, हाथ धोने और अपने पर्यावरण को साफ करने के प्रति जागरूक किया गया। बच्चों को बताया गया कि स्वच्छ बंधन न सिर्फ भाइयों और बहनों बल्कि सभी के लिए है।

इस सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम के बाद उन लोगों के बीच 'स्वच्छ बंधन' के प्रतीक वाली राखी का आदान-प्रदान किया गया। इन लोगों ने स्वच्छता की शपथ ली और अपने कैंपस को साफ करने का संकल्प लिया। उन्होंने खुले में शौच नहीं करने और दूसरों को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी लेने पर भी सहमति जताई।

- 2015 में ऑनलाइन ऑडिट की शुरुआत के बाद से ऑडिट के लिए पंजीकरण कराने वाले केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है।
- 2015 में 329 स्कूलों ने पंजीकरण कराया, 2016 में 739 स्कूल पंजीकृत हुए और 2017 में इनकी संख्या 858 हो गयी है।
- देश भर में कुल 54 हरित स्कूलों में से करीब 18 प्रतिशत केन्द्रीय विद्यालय थे।
- केन्द्रीय विद्यालयों को हर साल एक हरित विद्यालय पुरस्कार प्राप्त हो रहा है।

केन्द्रीय विद्यालय ओट्टापालम और केन्द्रीय विद्यालय पांगोड तो पर्यावरण संरक्षण संबंधी गतिविधियों में शानदार सुधार के लिए 'परिवर्तन के संवाहक' का दर्जा हासिल करने में सफल रहे हैं। (समूचे भारत में केवल चार स्कूल इस नयी और प्रतिष्ठित श्रेणी में शामिल होने में कामयाब रहे हैं जिनमें से दो केन्द्रीय विद्यालय हैं।) 2017-18 में हरित पुरस्कार जीतने वाले इन दो केन्द्रीय विद्यालयों के कुछ महत्वपूर्ण योगदान इस प्रकार हैं :

केन्द्रीय विद्यालय पांगोड छावनी, केरल

- हरित क्षेत्र : स्कूल का 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र हरा-भरा है।
- वायु : स्कूल के 71 प्रतिशत निवासी परिवहन के ऐसे साधनों को इस्तेमाल करते हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से कम नुकसान पहुंचाते हैं। 8 प्रतिशत पैदल चलने और साइकिल जैसे प्रदूषण न फैलाने वाले परिवहन साधनों का उपयोग करते हैं।
- कूड़ा-कचरा : स्कूल से निकलने वाले कूड़े-कचरे का इस्तेमाल इसके बायोगैस संयंत्र में ईंधन के तौर पर किया जाता है जिससे बायोगैस की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित होती है। स्कूल परिसर में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगी हुई है।
- पानी : स्कूल के आस-पास के गड्ढों में जमा बरसात के पानी को नालियों के जरिए विद्यालय के आस-पास के भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने में इस्तेमाल में लाया जाता है। कुछ पानी को पास के जंगल से होकर बहने और कर्मणा नदी में जाने को छोड़ दिया जाता है।

केन्द्रीय विद्यालय ओट्टापालम, केरल

- ऊर्जा : पिछले एक साल में स्कूल के बिजली बिल में कमी आयी है। स्कूल के प्रशासनिक ब्लॉक में गैर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। 50 किलोग्राम की कूड़ा-करकट रखने की क्षमता वाला बायो गैस संयंत्र करीब 10 कि.ग्रा. गैस उत्पन्न करता है।
- वायु : स्कूल के केवल एक प्रतिशत निवासी निजी वाहनों का उपयोग करते हैं।
- कूड़ा-कचरा : स्कूल 'अपना कूड़ा कम करो' के सिद्धांत का पालन करता है। प्राथमिक कक्षाओं में दो कूड़ेदान वाली प्रणाली अपनायी जाती है। हर रोज आखिरी पीरियड के अंत के पांच मिनट कूड़ा-करकट बटोरने के लिए होते हैं।
- पानी : स्कूल के पुराने वर्षा जल संचयन ढांचे का जीर्णोद्धार किया गया है। छत पर गिरने वाले वर्षा जल को भूमिगत जलाशय में पहुंचाया जाता है। इस पानी का उपयोग स्कूल के शौचालयों और पोछा लगाने और बगीचे में किया जाता है।

इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) की हरित स्कूल प्रतियोगिता

- केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा आयोजित उस प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वालों को ट्राफी और क्रमश: 3.5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये और 2.0 लाख रुपये के नकद पुरस्कार दिये जाते हैं।
- केन्द्रीय विद्यालय एएफएस बेगमपेट को 2015 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।
- केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर 2, आर.के. पुरम 2016 में 307 प्रतियोगियों में से प्रथम स्थान पर रहा।
- केन्द्रीय विद्यालय आई.आई.टी. कानपुर 2017 में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

साफ-सफाई, स्वच्छता, आरोग्य और पर्यावरण-स्वास्थ्य के बारे में समग्र दृष्टिकोण के विकास के लिए केन्द्रीय विद्यालय ने अपने स्कूल परिसरों और उनसे बाहर कई गतिविधियां/कार्यक्रम प्रारंभ किये हैं। ये नियमित विद्यालयी चर्या का हिस्सा हैं और इनका उद्देश्य सबके स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ावा देना है। इनमें से कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:

- प्रत्येक स्कूल को कूड़े-कचरे के निपटान के बारे में जागरूक बनाने

Scanned by CamScanner

जाए इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि फालतू कचरे का निस्तारण स्कूल परिसर में ही उसे खाइयों या गड्ढों में जमाकर उससे कम्पोस्ट खाद बनाकर बगीचों में किया जाए।

- विद्यार्थियों को इस बात के लिए जागरूक बनाया जाए कि बचा हुआ भोजन और खाने-पीने की चीजें केवल निर्धारित स्थान पर ही फेंकी जाए।
- बालिकाओं की व्यक्तिगत स्वच्छता का भी खास तौर पर ध्यान रखा जाए और विशेषज्ञों को बुलाकर स्वास्थ्य और स्वच्छता पर सत्र आयोजित किया जाए।
- प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम किया जा रहा है और कुछ स्कूलों को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित भी किया जा चुका है।
- स्कूलों में बड़ी कक्षाओं के छात्रों को अपनी पुरानी किताबें छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों को देने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे एक ओर उनमें अपनी किताबों को भेंट में देने के लिए साफ-सुथरा रखने की आदत का विकास हो रहा है तो दूसरी ओर इससे वृक्षों को बचाने में भी बड़ी मदद मिल रही है।
- 2016-17 में बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों ने अपनी 258385 पुस्तकें छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों को भेंट कीं, जिससे करीब 51.667 टन कागज की बचत हुई और कागज के लिए 874 वृक्षों को कटने से बचाया जा सका।
- 2017-18 में भी यह मुहिम जारी रही और बच्चों ने 504679 पुस्तकें उपहार में दीं, जिससे करीब 100.935 टन कागज की बचत हुई और 1716 पेड़ों को कटने से बचाया जा सका।
- बच्चों को उनके जन्म दिन पर पेड़ लगाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है और मेहमानों को तोड़े हुए फूलों का गुच्छा उपहार में देने की बजाय जीवित पौधे उपहार में दिये जाने लगे हैं।
- विद्यार्थियों में अच्छे नागरिक के गुणों के विकास के लिए स्कूलों में बिजली की किफायत करने का अभियान भी जोर पकड़ने लगा है।
- कक्षा में कक्षा का उपयोग न होने पर कक्षा की लाइटें और पंखों को बंद कर

सफलता की कहानी

उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए स्वच्छता रैंकिंग पुरस्कार 2018

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने हाल में नई दिल्ली में उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वच्छता रैंकिंग पुरस्कार दिए। स्वच्छता रैंकिंग पुरस्कार के लिए 8 अलग-अलग श्रेणियों में उच्च शिक्षा के 51 बेहतरीन संस्थानों को चुना गया है।

स्वच्छता रैंकिंग पुरस्कार की प्रमुख विशेषताएं

स्वच्छता रैंकिंग की पहल उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई है। इसका मकसद शैक्षणिक संस्थानों के कैंपस को साफ-सुथरा बनाए रखने उनके बीच समकक्ष स्तर पर दबाव बनाना है, ताकि छात्र-छात्राओं के लिए पढ़ाई का माहौल बेहतर और साफ-सुथरा हो और ऐसे माहौल में अच्छा और ऊंचा सोच सकें।

विभाग को लगता है कि शैक्षणिक संस्थानों को न सिर्फ अपने कैंपस की सफाई में अहम भूमिका निभानी चाहिए, बल्कि वे जागरूकता पैदा कर और अन्य सहायता के जरिये स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए अपने आसपास के गांवों को भी गोद लें।

इस साल की रैंकिंग में शैक्षणिक संस्थानों से पिछले साल के मुकाबले दोगुनी प्रतिक्रिया मिली है। इस बार 6,000 से भी ज्यादा संस्थानों ने भागीदारी की है। रैंकिंग के आकलन के लिए पैमानों को ज्यादा वैज्ञानिक बनाया गया है और उसमें वर्षा के जल के प्रबंधन, सौर ऊर्जा, छात्रावास के रसोई घर के उपकरणों की गुणवत्ता, जल आपूर्ति प्रणाली की गुणवत्ता, रखरखाव प्रणाली आदि पहलुओं को शामिल किया गया है।

देने की आदत बन गयी है।

- ऊर्जा की किफायत और ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता कम करके पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन पहले चरण में दिल्ली, बिहार, असम, त्रिपुरा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में अपने स्कूलों में सौर ऊर्जा पर आधारित फोटो वोल्टैक (पी.वी.) प्रणालियां लगा रहा है। दिल्ली के 12 केन्द्रीय विद्यालयों में सोलर पैनल लगाने का कार्य पूरा हो चुका है। अब तक पुराने तरह के 54419 बल्ब/ट्यूब लाइटों को बदलकर उनकी जगह एल.ई.डी. लाइटें लगा दी गयी हैं। इसके अलावा 948 सोलर लाइटें भी लगायी गयी हैं और इस दिशा में कार्य जारी है।
- स्कूलों की मौजूदा इमारतों में वर्षा जल संचय प्रणाली कायम की जा रही है। स्कूलों की 755 स्थायी इमारतों में से 231 में वर्षा जल संचय प्रणालियों का विकास किया गया है जबकि बाकी में इनका विकास करने का काम चल रहा है। केन्द्रीय विद्यालयों की सभी नयी इमारतों में वर्षा जल संचय प्रणालियों का विकास किया जा रहा है।

स्वच्छता अभियान के तहत केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा पिछले चार वर्षों में आयोजित कुछ प्रमुख गतिविधियां/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

- केन्द्रीय विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों, कर्मचारियों और अधिकारियों को स्वच्छता शपथ दिलाना
- स्कूल परिसरों और उनके आस-पास की सफाई
- स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वाले जाने-माने लोगों और विशेषज्ञों की प्रेरक वार्ताएं
- सुबह की सभा में व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए बच्चों की जांच/प्रोत्साहन
- स्कूल के शौचालयों को साफ-सुथरा रखने और बच्चों तथा स्टाफ के लिए स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का विशेष अभियान
- स्कूलों/केन्द्रीय विद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों/मुख्यालय में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन
- केन्द्रीय विद्यालयों में स्वच्छ और हरे-भरे माहौल को बढ़ावा देने के लिए 2016-17 के शैक्षिक सत्र से क्षेत्रीय स्तर पर 'स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार' और 'हरित विद्यालय

Scanned by CamScanner

पुरस्कार' की शुरुआत जिनके अंतर्गत चल वैजंती और नकद पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

स्वच्छता पर प्रश्नोत्तर कार्यक्रमों का आयोजन

पृथ्वी दिवस का आयोजन/जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमों आदि में भागीदारी

स्वच्छता विषय पर ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन

'हरित दिवाली-स्वच्छ दिवाली' अभियान का आयोजन

- 15 सितंबर, 2018 से प्रारंभ 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान में सभी स्तरों पर व्यापक भागीदारी।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन स्वच्छता अभियान के सभी संबद्ध पक्षों को इस अभियान से जोड़कर इसकी मूल भावना को आगे बढ़ा रहा है। यह लगातार चलने वाला कार्यक्रम है न कि एक दिन या सप्ताह के लिए आयोजित किया जाने वाला कोई कार्यक्रम। समूचे कार्यक्रम को स्कूलों की कार्य-प्रणाली के तहत समाहित कर दिया गया है और अब यह रोज़मर्रा की गतिविधि के रूप में प्रणाली का हिस्सा बन गया है। बच्चों को विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों के माध्यम से स्वच्छता के दिन जीवन-मूल्यों की शिक्षा दी जाती है वह सहभागिता वाले तरीके से सिखाई जाती है। जीवन के शुरुआती दौर में यह सब बताये जाने से ये जीवन-मूल्य उनके मन-मस्तिष्क में स्थायी रूप से अंकित हो जाएंगे और ये बच्चे आगे चलकर सही अर्थों में स्वच्छता के सच्चे दूत बनेंगे। ❑

सफलता की कहानी

लड़कियां खुद जुटीं शौचालय निर्माण में

सरकार द्वारा देश भर में चलाये जा रहे स्वच्छ भारत अभियान को शुरू हुए चार साल का समय गुजर गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर, 2014 को नई दिल्ली से इस अभियान की शुरुआत की थी। इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि इस अभियान को एक चुनौती की तरह लिया जाना चाहिए। सरकारी स्तर पर शुरू हुए इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जन सामान्य भी अब धीरे-धीरे साफ-सफाई की अहमियत को जान और समझ कर इससे जुड़ रहा है। स्वच्छ भारत अभियान का असर शहरों, नगरों और कस्बों से होता हुआ गांवों तक पहुंचने लगा है।

बड़े-बुजुर्गों के अलावा युवा और छोटी आयु के बच्चे भी स्वच्छता अभियान की अहमियत को समझ कर उस पर अमल भी कर रहे हैं। ऐसा ही वाकया हुआ है मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के पास बसे सीहोर जिले के श्यामपुर तहसील के झरखेड़ा गांव में। जहां पंद्रह-सोलह साल की बच्चियों ने खुले में शौच जाने का बहिष्कार करते हुए अपनी अन्य बहनों और मां की सहायता से घर में शौचालय का निर्माण करते हुए मिसाल कायम की है। इस काम के लिए उन्होंने बकायदा स्कूल से दो दिन का अवकाश भी लिया। झरखेड़ा गांव की रामभरोसी सेन के पति की मृत्यु बरसों पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गयी थी। किसी तरह मेहनत मजदूरी कर वह अपने और अपनी पांच बेटियों का लालन-पालन कर रही है। बच्चियों की पढ़ाई-लिखाई में विशेष रुचि को देखते हुए वह सभी को शिक्षा दिलवा रही है। पांचों बच्चियां गांव के स्कूल में पढ़ती हैं। दसवीं में पढ़ने वाली राजकुमारी और नौवीं कक्षा की छात्रा पूजा को स्कूल और ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की जानकारी मिली। इस अभियान के तहत उन्हें खुले में शौच की गलत परंपरा को पूरी तरह समाप्त कर घर-घर में पक्के शौचालय बनाने की पहल के बारे में पता चला। बुनियादी सुविधाओं और जानकारी के अभाव के साथ-साथ गांव में बरसों से खुले में शौच जाने के चलन के कारण इनके घर में भी शौचालय नहीं था। इसलिए जैसे ही

इन्हें शौचालय निर्माण के बारे में पता चला तो उन्होंने भी अपनी मां को इस बारे में बताया। धन के अभाव के कारण पहले तो रामभरोसी ने शौचालय बनवाने से मना कर दिया, लेकिन जब राजकुमारी और पूजा ने उन्हें सरकार की इस योजना और सरकारी मदद की बात बताई तो वह भी झट से घर पर शौचालय बनवाने के लिए राजी हो गयी और फिर पूरा परिवार जुट गया इस काम में। इसके लिए दोनों लड़कियों ने स्कूल में दो दिनों की छुट्टी का आवेदन भी दिया जिसे मास्टर जी ने खुशी-खुशी स्वीकार कर उन्हें छुट्टी दे दी। फिर क्या था आनन-फानन में ये बच्चियां अपनी मां और अन्य बहनों की सहायता से गड्ढा खोदने में लग गयीं। चूंकि उन्हें स्कूल और पंचायत स्तर पर इस बात की जानकारी मिल गयी थी कि जलबन्ध शौचालय के लिए अधिक जगह की जरूरत भी नहीं होती है और गड्ढा भी अधिक गहरा खोदने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ बरस बाद जब गड्ढा भर जाता है तब दूसरा गड्ढा खोद लिया जा सकता है। इस प्रकार का शौचालय बदबू रहित होता है। पांच से छह व्यक्तियों के परिवारों के लिए जलबन्ध शौचालय काफी कारगर साबित होते हैं। इन शौचालयों की एक और विशेषता है कि जो गड्ढा बंद कर दिया जाता है कुछ बरसों में उसमें खाद बन कर तैयार हो जाती है। इस प्रकार की तमाम जानकारी एकत्रित कर गांव की ये बेटियां जल्द से जल्द शौचालय बनाने में जुट गयीं।

ग्राम पंचायत की ओर से भी उन्हें सरकारी सहायता मिल गयी। देखते-देखते ही सीमेंट, ईंट और अन्य सामग्री भी जुटा ली गयी और तैयार हो गया पक्का शौचालय घर पर ही। अब इन बहनों की लगन, मेहनत और जज्बे की हर तरफ सराहना हो रही है और ये बन रही हैं अन्य लोगों की प्रेरणास्रोत भी। इस बारे में राजकुमारी का कहना है कि "बचपन से ही हम लोग पास के मैदान में ही शौच के लिए जाते थे। अकेले जाने में डर और शर्म लगती थी। हम पांच छह लड़कियां किसी बड़ी उम्र की महिला के साथ मुंह अंधेरे शौच के लिए जाते थे कि कहीं कोई देख न ले। दोपहर में तो जरूरत पड़ने पर भी शौच जाया नहीं जाता था। लेकिन अब तो हमारे घर पर ही शौचालय बन गया है तो हम सभी की परेशानी खत्म।"

– वीणा मंचलोक पाठक
लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।
ईमेल : veenasahlokpathak@gmail.com

Scanned by CamScanner

स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत

आलोक कुमार तिवारी

यात्रियों ने अब सोशल मीडिया की ताकत को महसूस करना शुरू कर दिया है और वे अब अपनी विक्कतों के जल्द से जल्द निपटारे और सवालों के जवाब के लिए ट्विटर और फेसबुक का सहारा ले रहे हैं... इस तरह की शिकायतों को ट्विटर से भेजे जाने के साथ यात्रियों को पहले से मौजूद प्रणाली 'मेरी बोगी साफ करें' और हेल्पलाइन नंबर 138 के बारे में भी अवगत कराया जाता है। 'मेरी बोगी साफ करें' प्रणाली के तहत यात्री अपना पीएनआर नंबर 58888 पर एसएमएस कर अपनी सीट की सफाई के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं

रेल परिवहन आम लोगों के लिए आने-जाने और माल ढुलाई के सबसे बेहतर साधनों में से एक है। साथ ही, परिवहन का यह माध्यम पर्यावरण के अनुकूल भी है। भारतीय रेल हमेशा से ऐसे उपायों के प्रति प्रतिबद्ध रहा है, जो विशाल आबादी और क्षेत्रीय प्रभावों के बावजूद पर्यावरण के हिसाब से कम से कम नुकसानदेह रहे हैं।

महात्मा गांधी की 145वीं जयंती के अवसर 2 अक्टूबर, 2014 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय स्तर का मिशन 'स्वच्छ भारत अभियान' शुरू किया। इस अभियान के तहत 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य है। इस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत के बाद रेल मंत्रालय ने 'स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत' अभियान शुरू किया, जिसका मकसद सभी रेलवे स्टेशन के अहातों और रेलगाड़ियों में स्वच्छता की स्थिति को बेहतर बनाना था। रेलवे के पास 87,000 से भी ज्यादा स्टेशन हैं और हर रोज औसतन 13,000 से भी ज्यादा ट्रेनें चलती हैं। क्षमता से अधिक भीड़, अनियंत्रित इस्तेमाल, यात्रियों की आदतों आदि के कारण इन स्टेशनों और ट्रेनों पर सफाई की स्थिति में सुधार और इसे बनाए रखना चुनौतीपूर्ण काम है, जहां यात्री लंबा वक्त भी गुजारते हैं।

रेल मंत्रालय ने 'स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत' अभियान के तहत कई तरह की पहल की है। इसके तहत इस तरह के कदम उठाए गए हैं: (1) सभी प्रमुख स्टेशनों पर सफाई के काम की आउटसोर्सिंग; (2)मशीनों सफाई के लिए गुंजाइश बनाने की खातिर प्लेटफॉर्म के फर्श में सुधार; (3) अलग-अलग तरह के कचरों के लिए अलग कचरे का डिब्बा मुहैया कराना; (4) सफाई के काम की निगरानी के लिए सीसीटीवी की तैनाती; (5) यात्री डिब्बों में जैविक-शौचालय लगाया जाना; (6)नागरिकों की राय इकट्ठा करने के लिए 'उपभोक्ता शिकायत' वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करना। इसके अलावा (7) विभिन्न स्टेशनों पर भुगतान के बदले इस्तेमाल वाले शौचालयों को भी बनाना; (8) चलती ट्रेन में हाउसकीपिंग सेवाओं को शुरू करना, नामांकित ट्रेनों में मेरे बोगी की सफाई और कोच मित्र सेवाएं; (9) पहली बार ट्विटर के जरिये 24X7 लोक शिकायत प्रणाली और यात्रियों के लिए मेडिकल, सुरक्षा और अन्य आपातकालीन सहायता के लिए प्रावधान किए गए हैं।

'ट्रेन स्टेशन की सफाई' (सीटीएस) का मकसद ट्रेनों के सफर के दौरान चुनिंदा स्टेशनों पर ठहराव के वक्त उनकी सीमित सफाई की जाती है। अब तक रेल विभाग में 39 सीटीएस को चालू किया जा चुका है। इसके अलावा, यात्रियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा सफाई अभियान शुरू किया जाता है, जिसका एकमात्र मकसद ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों के सफाई के स्तर में महत्वपूर्ण और सतत सुधार है। प्रमुख स्टेशनों पर सफाई के प्रयासों के असर के आकलन के लिए 407 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर थर्ड पार्टी द्वारा स्वच्छता के सूचकांकों के आधार पर सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। सर्वे की रिपोर्ट में सफाई के स्तर को सुधारने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में दिशा-निर्देश का मामला भी शामिल है। सफाई के काम के लिए सक्षम एजेंसी चुनने में खुला, पारदर्शी, निष्पक्ष और बोली

लेखक रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय (पर्यावरण और हाउसकीपिंग प्रबंधन) के प्रधान कार्यकारी निदेशक हैं। उन्होंने अपने 34 वर्ष के कार्यकाल के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठित परियोजनाओं पर काम किया है। ईमेल: alok_tewari60@hotmail.com

Scanned by CamScanner

लगाने की प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया अपनाए जाने के कारण सेवा संविदाओं में सुधार को बढ़ावा मिला है। सफाई के यांत्रिक उपकरणों और अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर एकीकृत हाउसकीपिंग ठेका प्रणाली लाई गई है। सेवा संविदा को लागू करने से जुड़ी विभिन्न स्थितियों से निपटने में जोनल रेलवे के मार्गदर्शन के लिए भारतीय रेलवे में सेवा संविदा के लिए ठेके/संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) की पेशकश की गई है। इससे पहले सेवा संविदा का संचालन कार्य संविदा की जीसीसी से भी संचालित होता था और संपत्तियों के सृजन/रखरखाव की दिशा में अलग-अलग शर्तें थीं और इस वजह से ये सेवा संविदा की चुनौतियों से निपटने में अपर्याप्त साबित हो रहे थे।

स्टेशनों, कोचिंग डिपो और ट्रेनों की हाउसकीपिंग के लिए जारी नए मानक नीलामी दस्तावेज में ठेकेदारों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए 10 फीसदी भारिता 'किस्म/गुणवत्ता के इस्तेमाल और उपभोग्य सामग्री और मशीनरी की मात्रा' को दी गई है और यह मासिक भुगतान से भी जुड़ा हुआ मामला है।

इसमें दो पैकेट वाली ठेका प्रणाली का पालन किया जाता है। न्यूनतम योग्यता की शर्तों के अलावा, तकनीकी मूल्यांकन चरण में कम से कम 70 फीसदी अंक हासिल करने वाले बोलीकर्ता ही वित्तीय बोली को खोलने में सक्षम होंगे। हाउसकीपिंग ठेकों में कार्य बल से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जैविक-मैट्रिक प्रणाली का प्रावधान, उपयोगकर्ता की राय के आधार पर भुगतान और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने की खातिर कीमतों में बदलाव संबंधी नियम जैसे चीजें शामिल

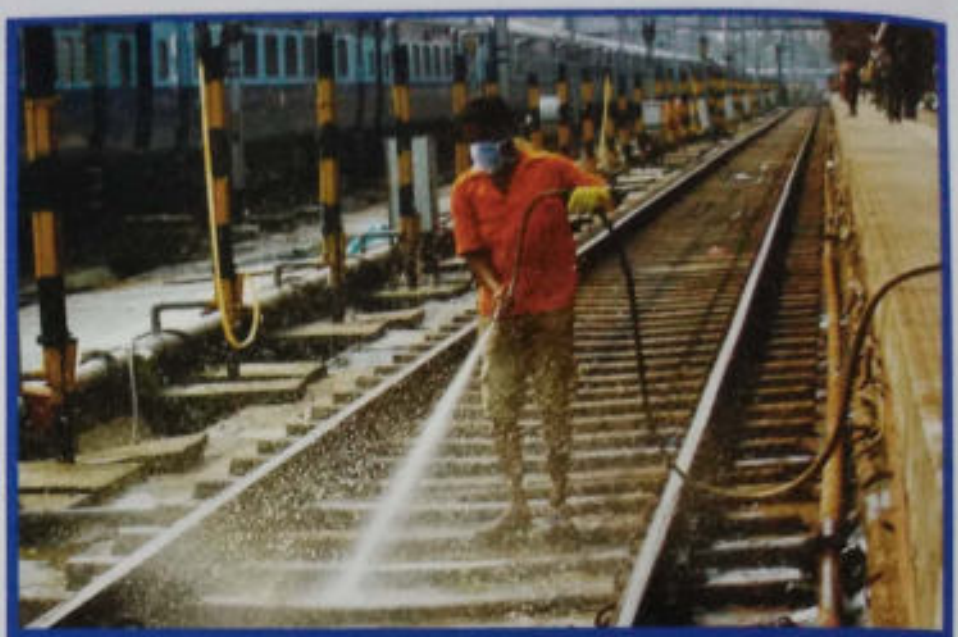

सफाई के काम के लिए सक्षम एजेंसी चुनने में खुला, पारदर्शी, निष्पक्ष और बोली लगाने की प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया अपनाए जाने के कारण सेवा संविदाओं में सुधार को बढ़ावा मिला है।

की गई हैं। जोनल रेलवे ने इसी मानक नीलामी दस्तावेज के आधार पर ठेकों को पास करना शुरू किया है। सेवा अनिवार्यता की जरूरतों को पूरा करने के लिए फील्ड अफसरों का सशक्तिकरण किया गया है।

बहरहाल, सफाई को लेकर शिकायत/असंतोषजनक काम के मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाती है और ठेके की शर्तों के मुताबिक ठेकेदार पर उपयुक्त जुर्माना भी लगाया जाता है, ताकि ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति नहीं हो। रेलवे स्टेशनों पर इस्तेमाल के बदले भुगतान वाले शौचालयों समेत अतिरिक्त शौचालयों का भी निर्माण किया गया है। भारतीय रेल नियम 2012 के क्रियान्वयन (रेलवे कैंपस में स्वच्छता पर बुरा असर डालने वाली गतिविधियों के लिए जुर्माना) पर चौकसी बढ़ाई गई है। प्रमुख स्टेशनों पर सफाई की निगरानी के लिए सीसीटीवी का इस्तेमाल भी बढ़ाया गया है।

रेलवे के जोनों द्वारा विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बारी-बारी से साप्ताहिक जोरदार सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। समय-समय पर रेलवे के अलग-अलग क्षेत्रों में सफाई से जुड़े खास विषयों पर केंद्रित अभियान भी चलाए जाते हैं। स्वच्छता जागरूकता अभियानों को अंजाम देने के लिए जनहित से जुड़ा काम करने संस्थानों/सामाजिक संगठनों समेत तमाम स्वैच्छिक संगठनों को इस अभियान से जोड़ा गया है। रेल का उपयोग करने वाले लोगों के बीच स्वच्छता को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सार्वजनिक स्तर पर घोषणाओं आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने 2017-18 में जैविक-शौचालय समेत साफ-सफाई पर 2,522 करोड़ रुपये खर्च किए।

Scanned by CamScanner

रेलवे सोशल मीडिया पर ग्राहकों से जुड़ने के लिए पहले ही रेल मंत्रालय का ट्विटर हैंडल /RailMinIndia और फेसबुक पेज 'मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज- इंडिया' पेश कर चुका है। इसके अलावा, ग्राहकों से प्रभावकारी जुड़ाव कायम करने के मकसद से रेलवे के सभी डिवीजन के मैनेजरों और महाप्रबंधकों के ट्विटर हैंडल भी मौजूद हैं। यह ज्यादा असरदार संवादमूलक तंत्र साबित हुआ है, जहां दिक्कतों का निपटारा वास्तविक समय में किया जाता है।

यात्रियों ने अब सोशल मीडिया की ताकत को महसूस करना शुरू कर दिया है और वे अब अपनी दिक्कतों के जल्द से जल्द निपटारे और सवालों के जवाब के लिए ट्विटर और फेसबुक का सहारा ले रहे हैं। ट्रेन में यात्रा कर रहा कोई भी यात्री सहायता के लिए रेलवे से तत्काल संपर्क कर सकता है। पहले इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यात्रियों के साथ यह संवादमूलक तंत्र इस तरह से काम करता है-

- अधिकारी ट्वीट/पोस्ट को पढ़ते हैं और इसे संबंधित प्राधिकार (जोन/डिवीजन/रेलवे बोर्ड निदेशालय) को टैग कर देते हैं।
- ट्वीट/पोस्ट के बाद यह डिवीजन पहुंचता है और संबंधित शाखा अधिकारी जरूरी सहायता के लिए तत्काल कदम उठाते हैं और इस तरह से यात्री की दिक्कत का निपटारा हो जाता है। समस्या का निपटारा हो जाने के बाद अधिकारी शिकायत की स्थिति के बारे में ट्वीट करते हैं।
- 'रेलवे की बोगियों में और स्टेशनों पर साफ-सफाई' को लेकर मिले ट्वीट/पोस्ट का उपरोक्त प्रणाली के जरिये वास्तविक समय में यानी तत्काल निपटारा किया जाता है।
- इस तरह की शिकायतों को ट्विटर से भेजे जाने के साथ यात्रियों को पहले से मौजूद प्रणाली 'मेरी बोगी साफ करें' और हेल्पलाइन नंबर 138 के बारे में भी अवगत कराया जाता है। 'मेरी बोगी साफ करें' प्रणाली के तहत यात्री अपना पीएनआर नंबर 58888 पर एसएमएस कर अपनी सीट की सफाई के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

इसके अलावा, ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीओएमएस) भी प्रचलन में है, जहां यात्री अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। रेलवे ने भारत सरकार द्वारा खुले में शौच के खिलाफ 25-09-2016 को शुरू किए गए अभियान में सहयोग करते हुए इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई। जैविक-शौचालय तकनीक को भारतीय रेलवे और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय रेलवे ने मिलकर संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह पर्यावरण के अनुकूल, कम लागत वाली और मजबूत तकनीक है और दुनिया की रेलवे प्रणाली में यह अपनी तरह का पहला प्रयोग है। डीआरडीओ ने इस प्रणाली में इस्तेमाल किए गए जीवाणुओं की प्रभावोत्पादकता की जांच सियाचिन ग्लेशियर जैसी चरम मौसमी परिस्थितियों में की है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये अवायवीय जीवाणु मानवीय मलमूत्र को मुख्य तौर पर पानी और बायगैस में बदल देते हैं (मुख्य तौर पर मिथेन-सीएच4 और कार्बन डाइऑक्साइड यानी सीओ2)। गैस वायुमंडल में विलीन हो जाती है और अवशिष्ट पानी पटरियों पर गिर जाता है। इस तरह से मानवीय मल रेलवे पटरियों पर नहीं गिरता है और इससे स्टेशन का अहाता और पटरियां साफ रहती हैं। जैविक शौचालयों का दुरुपयोग रोकने के लिए जोनल रेलवे द्वारा इस तरह के शौचालयों के इस्तेमाल के बारे में नियमित तौर पर यात्रियों को जानकारी दी जाती है। बोगियों पर स्टिकर चिपका कर, ऑडियो/वीडियो क्लिप और प्रदर्शनी आदि के जरिये इस बारे में यात्रियों में जागरूकता फैलाई जाती है।

रेलवे-डीआरडीओ के जैविक-शौचालय से लैस पहली ट्रेन ग्वालियर-वाराणसी-बुंदेलखंड एक्सप्रेस थी। इस ट्रेन में जैविक-

Scanned by CamScanner

शौचालय की सुविधा जनवरी, 2011 में शुरू की गई थी। इस संबंध में उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिलने के बाद इन जैव-शौचालयों को और ट्रेनों की बोगियों में लगाया गया। साल 2014 से ट्रेनों में जैविक-शौचालय लगाने की रफ्तार में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और रेलवे का इरादा मार्च, 2019 तक सभी बोगियों में जैविक-शौचालय लगाने का है। रेलवे के 27 सेक्शनों को हरित ट्रेन कॉरीडोर घोषित किया जा चुका है। इन सेक्शनों में ट्रेनों से किसी तरह मल-मूत्र नहीं गिरता है, क्योंकि इन क्षेत्रों से गुजरने वाली सभी ट्रेनों में शत-प्रतिशत जैविक-शौचालय हैं।

साफ और बेहतर शौचालय मुहैया कराने और शौचालयों में पानी की खपत को कम करने के मकसद से रेलवे जैविक-वैक्यूम शौचालय का परीक्षण भी कर रहा है। इसमें विमान जैसा यात्री इंटरफेस पर वैक्यूम शौचालय होता है और जैविक-डायजेस्टर टैंक बोगी के शौचालय वाले क्षेत्र के नीचे मौजूद होता है।

रेलवे में स्वच्छता अभियान के तहत स्टेशनों पर एकीकृत स्वच्छता प्रणाली मुहैया कराई जा रही है, जबकि 1,000 से भी ज्यादा ट्रेनों में इसके चलायमान के रहने के दौरान भी हाउसकीपिंग की सुविधाएं दी गई हैं। साथ ही, एसी बोगी के यात्रियों को दिए जाने वाले चादरों की सफाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए मशीनों से धुलाई की व्यवस्था की जा रही है।

बदलाव साफ तौर पर नजर आए, इसके लिए ठोस कचरा प्रबंधन का पहलू भी काफी महत्वपूर्ण है। ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए इसका तीन श्रेणियों में वर्गीकरण जरूरी है-स्वाभाविक तरीके से नष्ट होने के योग्य (गीला कचरा), स्वाभाविक तरीके से नष्ट नहीं होने के योग्य (सूखा कचरा) और खतरनाक कचरा। रेलवे ने अपने स्टेशनों और अन्य ठिकानों पर जमा होने वाले ठोस कचरे के पर्यावरण के अनुकूल लिहाज से निपटारे के लिए पायलट परियोजना शुरू की है। इसके तहत कचरे को ऊर्जा में भी बदलने की बात है। जयपुर और नई दिल्ली में पायलट संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जो स्वाभाविक रूप से नष्ट होने वाले कचरे को जैविक-मिथेनीकरण की प्रक्रिया के जरिये बिजली में रूपांतरित कर देंगे। इन संयंत्रों से पैदा होने वाली ऊर्जा का उपयोग आसपास के स्टेशनों पर उपयुक्त सेवाओं में किया जाएगा।

साफ और बेहतर शौचालय मुहैया कराने और शौचालयों में पानी की खपत को कम करने के मकसद से रेलवे जैविक-वैक्यूम शौचालय का परीक्षण भी कर रहा है। इसमें विमान जैसा यात्री इंटरफेस पर वैक्यूम शौचालय होता है और जैविक-डायजेस्टर टैंक बोगी के शौचालय वाले क्षेत्र के नीचे मौजूद होता है।

साल 2016 में पहली बार रेलवे स्टेशनों का (ए1 और ए श्रेणी के 407 स्टेशनों पर) साफ-सफाई के लिए स्वतंत्र थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा ऑडिट किया गया। इस तरह के सर्वे को 2017 और 2018 में फिर से किया गया। स्वच्छता को लेकर 210 महत्वपूर्ण ट्रेनों की रैंकिंग का इसी तरह का सर्वेक्षण भी पूरा होने के करीब है।

स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत-2018 के तहत रेलवे स्टेशनों के सफाई संबंधी अभियान में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। यह साफ तौर पर रेलवे अधिकारियों और यात्रियों के संयुक्त प्रयासों का नतीजा है। यात्रियों के व्यवहार में बदलाव के कारण भी हमें स्वच्छ भारत के सपने के करीब पहुंचने में मदद मिली है। इस साल के मूल्यांकन में ए1 और ए श्रेणी के 407 स्टेशनों के साफ-सफाई संबंधी अंक में 2017 के मुकाबले 17.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। जिन क्षेत्रों में स्वच्छता की उपलब्धियां हासिल की गई हैं, वे कुछ इस तरह हैं-

1. बोतलों को दबाने वाली मशीनों के जरिये प्लास्टिक कचरे में कमी।
2. सफाई नैपकिन वेंडिंग मशीनों के जरिये रेलवे स्टेशनों पर व्यक्तिगत साफ-सफाई का इंतजाम।
3. प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सफाई के काम की आउटसोर्सिंग।
4. स्कूलों, एनजीओ और समुदायों में जागरूकता अभियान चलाना।

बोगियों में तिलचट्टों की मौजूदगी को खत्म करने के लिए निम्न समय-सारणी के अनुसार अधिकृत एजेंसियों द्वारा बोगियों में खास तौर पर इस मकसद के लिए सफाई की जाती है:

- एसी बोगियों और पैंट्री कार में: 15 दिनों में एक बार।
- बिना एसी वाली आरक्षित बोगियों में: 30 दिनों में एक बार।
- बिना एसी वाली अनारक्षित बोगियों में : 60 दिनों में एक बार।

रेलवे यात्रियों को परिवहन का सुरक्षित, स्वच्छ और सेहतमंद मुहैया कराने की अपनी जिम्मेदारियों और कर्त्तव्यों को लेकर जागरूक है। इस काम में उपयोगकर्ताओं के सहयोग की भी जरूरत है। तोड़फोड़, सुविधाओं के दुरुपयोग आदि की खबरें भी आती रहती हैं। बेशक सुविधाओं को फिर से बेहतर बनाने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए काफी मेहनत और पैसे की जरूरत होती है। अतः रेलवे 'स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत' के इस प्रयास में सभी पक्षों की सक्रिय सहभागिता मांग रहा है और इस दिशा में प्रयास भी कर रहा है। ❑

Scanned by CamScanner

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का समापन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर, 2018 को महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन के मौके पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के संस्कृति केंद्र में। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनियो गुटरेश, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, पेय जल और स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती, संचार और रेल राज्य मंत्री (प्रभारी) श्री मनोज सिन्हा, आवासीय और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप पुरी और पेय जल और स्वच्छता राज्य मंत्री श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनगी भी मौजूद थे।

चार दिनों तक चला महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन 2 अक्टूबर, 2018 को संपन्न हो गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने समापन भाषण में कहा कि महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई। उनका कहना था कि महात्मा गांधी से प्रेरित होकर भारत के लोगों ने स्वच्छ भारत को दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन बना दिया है। पीएम ने बताया कि साल 2014 में ग्रामीण स्वच्छता का आंकड़ा 38 फीसदी था, जो अब बढ़कर 94 फीसदी पर पहुंच गया है। उनके मुताबिक 5 लाख से भी ज्यादा गांव खुले में शौच की समस्या से मुक्त हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 2 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस के साथ महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन (एमजीआईएससी) में लगी डिजिटल प्रदर्शनी का मुआयना करते हुए।

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन के तहत 4 दिनों का यह कार्यक्रम दुनिया के स्वच्छता मंत्रियों और अन्य नेताओं को एक मंच पर लाया।

इस सिलसिले में प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनियो गुटरेश के साथ डिजिटल प्रदर्शन का भी निरीक्षण किया। सम्मेलन के मंच पर मौजूद हस्तियों ने महात्मा गांधी की स्मृति में डाक टिकट और गांधी जी के पसंदीदा भजन 'वैष्णव जन तो' पर आधारित सीडी भी जारी की। इस अवसर पर स्वच्छ भारत पुरस्कार भी बांटे गए। ❑

Scanned by CamScanner